राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

सचिन ने बैट निर्माता कंपनी स्पार्टन पर किया मुकदमा

>> 13

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 5

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 15 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

लोकतंत्र के प्रहरी

आपातकाल के 44 साल

सुना रहे संघर्ष की कहानी

नई दिल्ली : 25 जून, 1975 की अर्द्धरात्रि भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया। 21 मार्च 1977 तक 21 माह का यह कालखंड भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। जिन्होंने इसका विरोध किया, जेल गए, यातनाएं सहीं... उनके संघर्ष की कहानी, उनकी जुबानी। ● पेज 13

सरोकार

ई-कचरे के निस्तारण की कारगर युक्ति पर जोर

जमशेदपुर : केंद्र सरकार की पहल पर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर (झारखंड) ने ई-कचरे निस्तारण की पर्यावरण हितैषी तकनीक विकसित की है। विज्ञानियों के इस सफल प्रयोग को हाथों हाथ लिया जा रहा है। अनेक उद्यमियों ने इसमें रुचि दिखाई है। (पेज-13)

एससीओ में पाकिस्तान को लगा दोहरा झटका

कूटनीतिक सफलता ▶ पहले प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा, फिर संयुक्त घोषणापत्र में शामिल हुआ सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा

पीएम ने कहा, आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त पोषित करने वालों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में शुक्रवार को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक का नाम लिए बिना उस पर जमकर निशाना साधा। करीब दो घंटे बाद सभी आठ सदस्य देशों की तरफ से जारी बिश्केक घोषणापत्र में सीमा पार से आतंकवाद को दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर रखा।

एससीओ की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक ही मंच पर बैठे मोदी ने कहा, आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन व वित्तीय मदद प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। 'आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए हर मानवतावादी को संकीर्ण दायरे से बाहर निकलना होगा।' उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का भी आह्वान किया। उन्होंने अफगानिस्तान मुद्दे को भी जोर-शोर से उठाया।

सहयोग के लिए रखी 'हेल्थ' की अवधारणा

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए 'हेल्थ' (एचईएएलटीएच) की अवधारणा पेश की। इसमें 'एच' से आशय स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग, 'ई' से आशय आर्थिक सहयोग, 'ए' से आशय वैकल्पिक ऊर्जा, 'एल' से आशय साहित्य और संस्कृति, 'टी' से आशय आतंकवाद मुक्त समाज और 'एच' से आशय मानवीय सहयोग से है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कई अवधारणाएं और परिभाषाएं गढ़ चुके हैं।

सम्मेलन के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी घोषणापत्र में हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि किसी भी तर्क से आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसमें भारत की एक पुरानी मांग का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र की अगुआई में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग स्थापित करने का आह्वान किया गया। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक समग्र समझौते को स्वीकार करने के आह्वान के साथ यह भी कहा गया कि इसमें हर देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता का आदर होना चाहिए। घोषणापत्र में आतंकवाद और इसके पीछे की सोच का खात्मा करने के लिए भी सहमति बनाने की बात कही गई।

अगला सम्मेलन रूस में : अगला एससीओ सम्मेलन रूस में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी। साथ ही मोदी ने कनेक्टिविटी के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरीडोर, चाबहार बंदरगाह, अश्गाबत समझौता जैसी पहल कनेक्टिविटी पर भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं।

इमरान ने अलापा कश्मीर राग : सम्मेलन में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर राग अलापने से नहीं चूके। दक्षिण एशिया में शांति बहाली का आह्वान करते हुए इमरान ने कहा, 'इस क्षेत्र में तनाव को सहयोग में बदलने की जरूरत है। इसके बगैर यहां शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। यहां सियासी मतभेद दूर करने, लंबित मुद्दों को सुलझाना भी शांति के लिए जरूरी है।' इसके बाद उन्होंने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की, लेकिन यह भी कहा, 'वह गैरकानूनी तरीके से जब्त किए गए क्षेत्र में लोगों के खिलाफ सरकार समर्थित आतंकवाद की भी निंदा करते हैं।' (पेज-5 भी देखें)

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायटर

बिश्केक में हो ही गई मोदी-इमरान की मुलाकात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और पाकिस्तान के नेताओं की एक साथ मौजूदगी हमेशा से खास होती है और इस बार भी यह खास रही। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच अंततः एक संक्षिप्त मुलाकात हो ही गई। यह मुलाकात सिर्फ सामान्य हालचाल पूछने तक ही सीमित रही। वैसे दो दिनों तक चली इस बैठक में दोनों नेता सात बार एक-दूसरे के सामने आए, लेकिन इससे पहले न तो कोई बातचीत हुई और न ही सार्वजनिक तौर पर सामान्य शिष्टाचार निभाने की कोई औपचारिकता हुई।

गुरुवार को मोदी और खान दो बार एक ही समारोह में एससीओ के अन्य सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ शामिल हुए थे, जबकि शुक्रवार सुबह से लेकर देर शाम तक पांच समारोहों में वे एक साथ आसपास रहे। तीन बार फोटो सेशन हुआ और इसमें भी दोनों नेताओं के बीच फासला बना रहा। पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर बाहर आई कि दोनों नेताओं के बीच सामान्य मुलाकात हुई है। इसकी पुष्टि बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी की। पाक विदेश मंत्रालय के सूत्रों का यह भी कहना है कि भारत में हाल ही में संपन्न चुनावों पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई, लेकिन भारतीय पक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए है।

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▶ पृष्ठ 2

हाई कोर्ट ने रद किया दाखिलों पर डीयू का फैसला

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियमों को बदलने के फैसले को हाई कोर्ट ने रद कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को तीन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में डीयू के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में पिछले साल के पात्रता मानदंडों के आधार पर ही प्रवेश होगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

सुरक्षाबलों ने पुलवामा में मार गिराए लश्कर के दो आतंकी

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकरोधी अभियान में तेजी लाते हुए शुक्रवार को बरोबंडुना (पुलवामा) में भीषण मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकियों को मार गिराया। ज्ञात हो कल ही आतंकियों ने सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाया था।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

भारत से रक्षा सहयोग की सीमा तय करेगा एस-400 सौदा

वाशिंगटन : अमेरिका ने भारत और रूस के बीच होने वाले एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौदे को लेकर फिर आपत्ति जाहिर की है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, वह भारत की सुरक्षा जरूरतें पूरा करने को तैयार है, पर एस-400 सौदे को वह भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग में सीमा के तौर पर देख रहा है।

क्रिकेट महाकुंभ

ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका — दोपहर 3:00 बजे से — स्थान : लंदन

द. अफ्रीका vs अफगानिस्तान — शाम 6:00 बजे से — स्थान : कार्डिफ

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

हड़ताल ने ली पांच मरीजों की जान, ममता के रवैये पर सैकड़ों डॉक्टरों के इस्तीफे

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- बंगाल में मारपीट के बाद कई राज्यों के डॉक्टर हड़ताल पर
- अनेक राज्यों में ओपीडी सेवाएं ठप पड़ीं, विरोध में डॉक्टरों ने लगाया हेलमेट
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 17 जून को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान

कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट के बाद बंगाल से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल में, शुक्रवार को देश भर के डॉक्टरों के शामिल हो जाने से मरीजों की जान पर बन आई है। इलाज नहीं मिलने से बंगाल में ही पांच मरीजों की मौत हो गई है। बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व राजस्थान समेत कई राज्यों में ओपीडी सुविधाएं चरमरा गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये के विरोध में सैकड़ों डॉक्टरों ने इस्तीफे दे दिए हैं। अकेले बंगाल में ही 700 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है।

कुछ राज्यों में काली पट्टी बांध तो कुछ में विरोध स्वरूप हेलमेट पहनकर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आए। कुछ डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी को बातचीत के लिए बुलाया है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने 17 जून से राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। वहीं, कलकता हाई कोर्ट ने एक याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इन्कार करते हुए ममता सरकार से कार्रवाई की जानकारी मांगी है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई है। उधर, टोक्यो स्थित वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने भी डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन किया है।

ज्ञात हो, कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में बीते सोमवार एक मरीज की मौत के बाद उनके तीमारदारों ने डॉक्टरों से मारपीट की थी। इसमें कुछ डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल की आग शुक्रवार को देशभर में फैल गई। कई राज्यों में डॉक्टर शुक्रवार को एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने डॉक्टरों ने रखीं छह शर्तें पेज>>7

पश्चिम बंगाल की घटना के बाद एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा हड़ताल से परेशान मरीज व परिजन। संजय

कार्तिकेय चंद्रेश बने जेईई एडवांस्ड के टॉपर

जागरण संवाददाता, रुड़की : इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित परीक्षा जेईई एडवांस्ड-2019 में महाराष्ट्र के बल्लारपुर निवासी गुप्ता कार्तिकेय चंद्रेश ने ऑल इंडिया टॉप किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा निवासी हिमांशु गौरव सिंह ने दूसरा और दिल्ली के अर्चित बुबना ने तीसरा स्थान हासिल किया है। लड़कियों के वर्ग में हैदराबाद के माधापुर की शबनम सहाय पहली रैंक पर रहीं। उनकी ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक दसवीं है।

कार्तिकेय फेसबुक से

जेईई एडवांस परीक्षा का जिम्मा इस बार आइआइटी रुड़की के पास था। परीक्षा संचालन समिति के चेयरमैन डॉ. एमएल शर्मा ने बताया कि गुप्ता कार्तिकेय चंद्रेश ने 372 में से 346 अंक और छात्राओं में अव्वल रही शबनम ने 308 अंक प्राप्त किए हैं। उन्होने बताया कि इस वर्ष जेईई एडवांस्ड एक और दो की परीक्षा में कुल 161319 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें 38705 अभ्यर्थी सफल रहे। इनमें 33349 छात्र और 5356 छात्राएं हैं। (पेज-6)

झारखंड में नक्सलियों ने अगवा कर पांच पुलिसकर्मियों का मार डाला

जागरण न्यूज नेटवर्क, रांची

- सरायकेला-खरसावां जिले के साप्ताहिक हाट में घटना को दिया अंजाम
- हथियार लूटकर सभी बाइक से भाग गए प. बंगाल की ओर, उनके चेहरे ढके हुए थे

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले स्थित तिरुलडीह थाना क्षेत्र के कुकुडू साप्ताहिक हाट में शुक्रवार शाम तकरीबन 6.30 बजे नक्सलियों ने राज्य पुलिस के दो सब-इंसपेक्टर और तीन सिपाहियों को बंदूक और चाकू के बल पर अगवा कर लिया। फिर सबकी गोली मार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद नक्सली पुलिसकर्मियों की बंदूक लूट कर पश्चिम बंगाल की ओर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दो बाइक पर सवार होकर बाजार पहुंचे आधा दर्जन नक्सलियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। सभी ने मुंह पर गमछा लपेट रखा था।

थाना में ताला लगा भागे पुलिसकर्मी : दहशत का आलम यह था कि तिरूलडीह थाने के मेन गेट पर ताला लगाकर पुलिसकर्मी भाग गए। कोई घटनास्थल तक जाने की हिम्मत नहीं कर सका। आसपास की सभी दुकानदार भी भाग निकले। ध्यान रहे तिरूलडीह के थाना प्रभारी महावीर उरांव सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर डांस करने के आरोप में तीन-चार दिन पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं।

> सूबे में अंतिम सांसें गिन रहे नक्सलवादियों ने बौखलाहट में घटना को अंजाम दिया है। शहादत बेकार नहीं जाएगी, जारी रहेगी कठोर कार्रवाई।
>
> -रघुवर दास, सीएम

हाल के दिनों में बढ़ीं नक्सली वारदातें : सरायकेला जिले में हाल के दिनों में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ गई है। कुचाई में 28 मई को नक्सलियों ने आइइडी धमाका किया था जिसमें कोबरा -209 बटालियन और झारखंड पुलिस के 15 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इसके पूर्व चुनाव के दौरान खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत खरसावां में मतदान बूथ पर नक्सलियों ने बम विस्फोट किया था।

गुमला में हाट से भाजपा कार्यकर्ता की अपहरण कर हत्या : गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के कटिया गांव में गुरुवार शाम नक्सलियों ने साप्ताहिक हाट से भाजपा कार्यकर्ता ब्रजेश साहू (38) का अगवा किया और तकरीबन आधा किलोमीटर दूर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने मौके पर पर्चा भी फेंका, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी लेने के साथ ही ब्रजेश साहू को पुलिस का एसपीओ बताया गया है। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने पास ही स्थित बीड़ी के पत्तों से लदा ट्रक फूंक डाला। इन दोनों घटनाओं से ग्रामीणों में खौफ पसर गया और वे अपने घरों में कैद हो गए। पुलिस के पहुंचने के बाद भी वह बोलने को तैयार नहीं हैं।

घातक होगा दिल्ली मेट्रो में सियासी दखल

मुफ्त सवारी की घोषणा से मेट्रोमैन ई. श्रीधरन आहत, पीएम मोदी को लिखा पत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त सवारी के प्रस्ताव से आहत मेट्रोमैन ई. श्रीधरन ने इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताते हुए बेहद घातक करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत न होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जापानी एजेंसी के ऋण की वापसी में बड़ी मुश्किलें आएंगी। मेट्रो में सियासी दखल रोकने का फैसला इसके पहले चरण के समय ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष किया गया था।

पत्र में श्रीधरन ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार सचमुच में महिलाओं को मुफ्त सवारी कराने की इच्छुक है तो उनके बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि डीबीटी के मार्फत जमा करा दे। इससे वह मनमाफिक सवारी कर सकेंगी। गौरतलब है कि दिल्ली में मेट्रो की दैनिक सवारी करने वाली महिलाओं की बड़ी संख्या बाहर से आती है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के लागू होने से स्थितियां खराब होंगी और छात्र, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग वर्ग भी ऐसी मांग करेंगे। इसके बाद यह बीमारी दूसरे राज्यों की मेट्रो रेल में भी फैल सकती है।

दिल्ली मेट्रो में केंद्र व राज्य सरकार बराबर की हिस्सेदार है। ऐसे में फैसला अकेले राज्य सरकार कैसे ले सकती है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेट्रो दिवालिया हो सकती है। श्रीधरन ने मोदी से जोर देकर कहा है कि वह इस तरह के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार न हों। यह पत्र 10 जून 2019 को लिखा गया है।

तत्कालीन पीएम वाजपेयी को भी लेना पड़ा था टोकन : श्रीधरन ने पत्र में मेट्रो के पहले चरण के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी टोकन खरीदकर शाहदरा से कश्मीरी गेट तक की यात्रा करनी पड़ी थी। इससे एक अच्छा संदेश गया, जो आज भी कायम है। स्टाफ और यहां तक कि प्रबंध निदेशक भी मेट्रो रेल में टिकट खरीदकर ही यात्रा करते हैं।

सिसोदिया ने कहा, मेट्रोमैन के पत्र से स्तब्ध हूं

राज्य ब्यूरो : ई श्रीधरन के मोदी को पत्र लिखने के जवाब में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेट्रोमैन को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने कहा है कि मुफ्त यात्रा पर आपका पक्ष हमारी योजना के प्रति आपकी गलतफहमी को दर्शाता है। आपके विरोध से स्तब्ध हूं। हम डीएमआरसी से दस लाख कूपन खरीदकर महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। इससे महिलाओं को तो सुविधा होगी ही मेट्रो का राजस्व व राइडरशिप भी बढ़ेगी।

राष्ट्रव्यापी 'ऑपरेशन थंडर' में रेल टिकट दलालों पर गिरी गाज

नई दिल्ली : रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध तरीकों से ट्रेन टिकट कंफर्म कराने वाले दलालों के राष्ट्रव्यापी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में गुरुवार को देश के डेढ़ सौ शहरों में छापे मार कर पौने तीन सौ दलालों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पचास हजार यात्रियों से संबंधित 32 लाख रुपये कीमत के बाइस हजार टिकट जब्त किए गए। (पेज-7)

भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया

नई दिल्ली : भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर रविवार से आयात शुल्क में वृद्धि का फैसला किया है। अमेरिका द्वारा गत वर्ष स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले के बाद भारत ने प्रतिक्रिया के तहत इन अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क वृद्धि का फैसला किया था। बाद में इसकी समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई। वित्त मंत्रालय से जल्द अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। (पेज-10)

विश्व कप

1200 पाउंड तक में ब्लैक में बिकी हैं भारत-पाकिस्तान के मैच की टिकट, आइसीसी भी चाहती है दोनों प्रतिस्पर्धियों के बीच हो धमाकेदार मुकाबला

भारत-पाक की भिड़ंत पर सांसों का रुकना लाजिमी है...

विश्व कप में दैनिक जागरण

अभिषेक त्रिपाठी ● मैनचेस्टर

नॉटिंघम में बारिश के कारण भारत-न्यूजीलैंड मैच रद होने के बाद जब मैं शुक्रवार की सुबह ट्रेन से मैनचेस्टर की तरफ बढ़ा तो पूरे रास्ते बारिश की बूंदें डराती रहीं कि रविवार को इनका कहर विश्व कप के अब तक के सबसे बड़े मुकाबले पर ना पड़ जाए। मैनचेस्टर पिकेडली रेलवे स्टेशन से ट्राम लेकर ओल्ड ट्रैफर्ड उतरा तो सामने ही विश्व कप की बड़ी सी बारिश से भीगी होर्डिंग दिखी, जिसमें लिखा था 'द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्रिकेट सेलिब्रेशन।' उसे देखकर मन में यही ख्याल आया कि अगर क्रिकेट के सबसे बड़े मेले में भारत-पाक का मुकाबला बारिश से धुल गया तो ब्लैक में 1200 पाउंड (करीब एक लाख रुपये) तक की टिकट लेने वालों का क्या होगा, आइसीसी दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी?

धूप से खिले चेहरे : दोपहर होते-होते ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में धूप खिल आई और इसी के साथ आइसीसी के सीईओ डेव रिचर्डसन का चेहरा भी खिल गया। उन्होंने कहा, चार दिन बाद धूप खिली है, जो मददगार होगी। इसके बाद मैदानकर्मी मैदान को मैच के लिए तैयार करने में जुट गए। सेंट्रल पिच से कवर हटाया गया तो पता चला कि इस पर रत्ती भर भी घास नहीं है। कुल मिलाकर आइसीसी चाहती है कि दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों के बीच धमाकेदार मुकाबला हो। हालांकि मौसम विभाग की मानें तो रविवार को बारिश की संभावना 50 फीसद तक है। हालांकि शाम होते ही मैनचेस्टर में दोबारा से बारिश होना शुरू हो गई।

भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक, युजवेंद्रा सिंह चहल और विजय शंकर ने मशहूर इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड का दौरा किया। इंस्टाग्राम

एशिया कप के बाद अब होगी मुलाकात : 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इन्कार कर दिया। उसके बाद से ये दोनों टीमें सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) और एशिया क्रिकेट परिषद (एसीसी) के टूर्नामेंट में ही भिड़ती हैं। इन दोनों के बीच आखिरी मुकाबला पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में दुबई में एशिया कप में हुआ था। तब भारत ने दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान को मात दी थी। हालांकि इससे पहले 2017 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को पराजित किया था।

दर्शकों को है पूरी उम्मीद : कभी कानपुर व कोलकाता की तुलना जिस मैनचेस्टर से की जाती थी, वहीं पर यह मुकाबला होना है। मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर युनाइटेड जैसे दो बड़े फुटबॉल क्लबों का घर अब क्रिकेट युद्ध का अखाड़ा बनने वाला है। करीब 26 लाख की आबादी वाले इस शहर में 15 फीसद भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी व अफगानी हैं। यहां पर टैक्सी चलाने वाले रमेश कुमार ने कहा, मैच की एक-एक टिकट बिक चुकी हैं। कुछ वेबसाइट में टिकटें रीसेल हो रही हैं। लोग 200 पाउंड तक में इन्हें खरीद रहे हैं। वहीं, एक पाकिस्तानी प्रशंसक रफीक आजमी ने कहा, इसमें शक नहीं कि हमारी टीम कमजोर है, लेकिन हमने विराट की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया है। जब ये दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो सांसों का रुकना लाजिमी हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती की शिकायत पर राजद्रोह का केस

नईदुनिया, रायपुर

- दो लोगों को हवालात में डाला, सरकार ने पुलिस से कहा-वापस लें मुकदमा
- सियासत गरमाने पर सीएम बोले- सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक

सोशल मीडिया पर बिजली कटौती से संबंधित पोस्ट करने पर छत्तीसगढ़ में चौबीस घंटे में दो लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, अब दोनों मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत मिल गई है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से राजनीति गरमा गई है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस सरकार खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। इसके बाद बघेल ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी को दर्ज मामले वापस लेने का निर्देश दिया।

राजनांदगांव जिले के मुसरा गांव निवासी मांगेलाल अग्रवाल ने बिजली कटौती को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था। उसे आधार बनाकर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार महासमुंद जिले के दिलीप शर्मा ने वेब मोर्चा पोर्टल पर 50 गांवों में 48 घंटे बिजली बंद होने की खबर चला दी। बिजली कंपनी के डीई एसके साहू की शिकायत पर पुलिस गुरुवार रात 11 बजे शर्मा के घर पहुंची और उन्हें थाने ले आई। पुलिस ने भ्रामक विषयवस्तु को जनमानस में प्रसारित कर जनाक्रोश फैलाने के प्रयास का केस दर्ज कर हवालात में डाल दिया। इस मामले में विपक्ष की बयानबाजी के बाद दोपहर दो बजे मुख्यमंत्री ने दोनों मामलों पर संज्ञान में लिया। उन्होंने डीजीपी से बात की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। जहां मामले दर्ज हो चुके हैं, उन्हें वापस लिया जाए। बघेल ने कहा, कांग्रेस और उसकी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर हैं। जिस तरह की कार्रवाई अभी हुई है, उस तरह का काम प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार करती थी। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद बिजली कंपनी ने दोनों मामले वापस ले लिए।

21 हजार छात्रों ने डीयू में दाखिले के लिए शुक्रवार को आवेदन किए। आवेदन प्रक्रिया 30 मई से चल रही है। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 3 लाख 39 हजार तक पहुंच गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 15 जून 2019

शहीदों के परिजनों को मिलेंगे घर

योजना ▶ उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी

योजना के तहत फ्लैट की कीमत का 50 फीसद ही चुकाना होगा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब एससी-एसटी (अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति) और शहीदों के परिजनों के लिए भी आवासीय योजना लाएगा। हालांकि इसके लिए अलग से नए फ्लैटों का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि पुरानी आवासीय योजनाओं के तहत जो बचे हुए फ्लैट हैं, उन्हीं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। शहीदों के परिजनों को जहां फ्लैट की कीमत का 50 फीसद ही डीडीए को चुकाना होगा, वहीं एससी-एसटी को भी बाजार दर से काफी कम पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।

शुक्रवार को उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष अनिल बैजल की अध्यक्षता में राजनिवास में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में उक्त योजना सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। जल्द ही डीडीए की ओर से स्वीकृत सभी प्रस्तावों पर काम शुरू हो जाएगा। बोर्ड की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित कराने के लिए पेनाल्टी सहित जो छूट 28 जून तक है, उसे अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

एससी-एसटी को मिलेंगे पुरानी योजनाओं के बचे हुए 500 फ्लैट : डीडीए की ओर से पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली में एससी-एसटी को पुरानी योजनाओं के तहत बचे हुए पांच सौ फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन फ्लैटों की उपलब्धता का अनुपात 2:1 होगा। फ्लैट की कीमत पुरानी योजना के अनुसार ही वसूल की जाएगी। डीडीए द्वारा अब तक 47 आवासीय योजनाओं में चार लाख से अधिक फ्लैटों का आवंटन किया गया है। इनमें लगभग 18 फीसद फ्लैट एससी-एसटी को आवंटित किए गए हैं।

शहीदों के परिजनों को मिलेंगे एक हजार फ्लैट : देश की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले शहीदों के परिजनों को भी फ्लैट देने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत उन्हें सिंगल बेडरूम वाले एक हजार फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनकी कीमत आधी रखी जाएगी। ये सभी फ्लैट नरेला और रोहिणी में होंगे। फ्लैटों के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। ये फ्लैट वही हैं जिन्हें 2014, 2017 और 2019 की ऑनलाइन आवासीय योजना में किसी ने नहीं खरीदा था। डीडीए को उम्मीद है कि इन फ्लैटों को शहीदों के परिवार वालों को देने से न केवल फ्लैट बिक जाएंगे, बल्कि शहीदों के परिवारों का भी भला हो सकेगा।

कमर्शियल बिल्डिंगों पर लागू होगा अपार्टमेंट एक्ट : बोर्ड बैठक में कमर्शियल बिल्डिंगों के लिए अपार्टमेंट एक्ट लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इस एक्ट के तहत अब कमर्शियल बिल्डिंगों में व्यापार करने वाले सीधे डीडीए के साथ लीज समझौता कर सकेंगे। इससे जहां एक ओर बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगेगी, वहीं इन बिल्डिंगों के व्यापारी सीलिंग के भय से भी मुक्त हो सकेंगे।

दिल्ली वासियों को मिलेगा पैदल चलने का हक : डीडीए बोर्ड की बैठक में दिल्ली में वॉकेबिलेटी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआइयूए) द्वारा इस आशय के नीतिगत मसौदे पर जल्द ही लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली मेट्रो, यातायात पुलिस, यूटीपैक (यूनिफाइड ट्रैफिक एंड टांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर) एवं डीएसआइआइडीसी (दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के प्रतिनिधियों संग बैठक कर डीडीए की ओर से इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत फिलहाल आइटीओ, दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी एवं दक्षिणी परिसर, उत्तम नगर क्रासिंग, चांदनी चौक, आइएसबीटी, आइएनए, हौज खास-आइआइटी, नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस, करोल बाग, साकेत-मालवीय नगर, कमला नगर, लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन द्वारका, अरबिंदो मार्ग पर अधचीनी क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मंडी हाउस, पुराना किला, प्रगति मैदान और दिल्ली चिड़ियाघर क्षेत्र, इंद्रलोक स्टेशन क्षेत्र, राजेंद्र प्लेस स्टेशन और डी.सी. क्षेत्र, आजादपुर मंडी और मेट्रो स्टेशन क्षेत्र, आसिफ अली रोड और जेएलएन मार्ग क्षेत्र का चयन किया है। यहां पर फुटपाथ पूरी तरह से अतिक्रमण और अवैध कब्जा मुक्त कराए जाएंगे।

48 घंटे से फंसे हैं कुवैत जाने वाले यात्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

होटल में बैठे कुवैत जाने वाले परेशान यात्री। (यात्रियों से प्राप्त फोटो)

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुवैत जाने वाली कुवैत एयरवेज की उड़ान रद होने से कई यात्री दिल्ली में पिछले 48 घंटे से फंसे हैं। एयरवेज कर्मियों का कहना है कि ऑपरेशनल कारण से उड़ान रद की गई थी। इसके बाद अलग-अलग उड़ानों से यात्रियों को गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। उधर, उड़ान रद होने के कारण कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट के अलावा होटल की बुकिंग इत्यादि भी रद हो चुकी है।

12 जून की रात दो बजे कुवैत जाने वाली कुवैत एयरवेज की उड़ान उड़ान संख्या केयू-382 रद हो गई। विदेश यात्रा के लिए 150 से ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। पहले तो यात्रियों ने सोचा कि कुछ घंटे में अन्य उड़ान से उन्हें गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन एयरवेज के अधिकारियों ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। स्थित यह है कि करीब 48 घंटे बीतने के बावजूद वे होटल और एयरपोर्ट के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनकी यात्रा किसी तरह पूरी हो सके।

यात्रियों के मुताबिक, उन्हें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द सभी को अगली उड़ान से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इसी बीच सभी को बसंतकुंज स्थित होटलों में ठहरा दिया गया। इस उड़ान के ज्यादातर

▶ **कुवैत एयरवेज की उड़ान रद होने के बाद भेजने की नहीं हुई व्यवस्था**

यात्री, हैदराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश से जबकि कुछ दिल्ली के थे। हैदराबाद निवासी यात्री प्रमोद रेड्डी के मुताबिक उन्हें होटल में रुके करीब 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन एयरवेज के अधिकारी उनकी कोई सुध नहीं ले रहे। वे करीब 70 यात्रियों के साथ होटल में ठहरे हुए हैं। सभी अपनी यात्रा के लिए लगातार होटल से एयरपोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। एयरवेज न तो उनके सवाल का सही जबाव दे रही है और न ही यह बताया जा रहा है कि उन्हें यात्रा के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के यात्री राकेश कुमार ने बताया कि कुवैत से उनकी पेरिस के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट थी। वहां उनके होटल भी बुक थे, लेकिन उड़ान रद होने से सारी बुकिंग रद करानी पड़ी।

न्यूज गैलरी

दिल्ली में बढ़ रहे अपराध पर संज्ञान लें शाह : केजरीवाल

नई दिल्ली : आप ने राजधानी की कानून-व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गत 24 घंटों में राजधानी में पांच हत्याएं हो गईं। यह वाकई में अपराध की चरम स्थिति है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह से अपील करता हूं कि वह राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था पर उचित संज्ञान लें। (जासं)

छेड़छाड़ के विरोध पर हत्या के मामले में मिलेंगे 15 लाख

नई दिल्ली : बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारे गए कारोबारी के परिजनों को दिल्ली सरकार 15 लाख की मदद देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस परिवार को मदद देने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए भी प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों का कहना है कि अभी तक पूर्व में इस तरह के मामलों में नौकरी देने की बात सामने नहीं आई है। इसलिए अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। (जासं)

निवेशकों ने किया ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का गठन

संवाद सहयोगी, दादरी : बाइक बोट कंपनी के निवेशक अपनी रकम वापस लेने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को ऑल इंडिया बोट टैक्सी यूनियन का गठन किया है। आगे की लड़ाई इसके बैनर तले लड़ी जाएगी। यह घोषणा धरने पर बैठे निवेशकों ने धरनास्थल पर की। निवेशक वाट्सएप ग्रुप बनाकर एक-दूसरे को जानकारी शेयर कर रहे हैं।

निवेशक राजकुमार सिवाच ने बताया कि कंपनी द्वारा ठगी गई रकम मुआवजे समेत शीघ्र मिल सके, इसलिए यूनियन का गठन किया गया है। यह यूनियन अदालत, सरकारी विभागों आदि में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी के निदेशक संजय भाटी व फ्रेंचाइजी हेड विजय कसाना पुलिस रिमांड पर हैं। उन्होंने बताया कि यूनियन ने 13 जून को प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को ज्ञापन भेजकर इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए सभी पीड़ित निवेशकों को उनकी रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि यूनियन 17 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान संसद भवन के समक्ष शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी, ताकि यह प्रकरण संसद में उठ सके और पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल सके। यूनियन ने इसके लिए सभी सांसदों को पत्र भेजा है।

विधानसभा चुनाव से पहले लोगों में भ्रम फैला रही आप : मनोज तिवारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख केजरीवाल सरकार मुफ्त घोषणाएं देने का एलान कर रही है। सच्चाई यह है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी (आप) अब लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल द्वारा महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा कराने की घोषणा हवा-हवाई साबित होगी। मेट्रो का कहना है कि इस योजना को पूरा करने में आठ माह का समय लगेगा। अब केजरीवाल सरकार मुफ्त वाई-फाई देने का भी वादा कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं, जबकि इस योजना को पूरा करने में भी अभी समय लगेगा। तिवारी ने सवाल किया कि क्या केजरीवाल ने वर्ष 2015 के चुनाव के दौरान मुफ्त वाई-फाई की घोषणा करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के बारे में सोचा था।

कांग्रेस ने किया मेट्रोमैन श्रीधरन के पत्र का स्वागत : प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ई. श्रीधरन द्वारा पीएम को लिखे गए पत्र का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने से मेट्रो का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर केजरीवाल सरकार को दिल्ली की महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो वह सीधे उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दें।

महिलाओं को दिए जाएंगे गुलाबी कार्ड : भारद्वाज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन को कोई गलतफहमी हुई है। इसलिए उन्होंने इस तरह का पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है। वहीं, मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मुहैया कराने के लिए उचित मैकेनिज्म बनाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच भारद्वाज ने कहा कि मेट्रो में यात्रा के लिए अभी तक नीले कार्ड का इस्तेमाल होता है। दिल्ली के अंदर अगर महिलाओं को मुफ्त यात्रा देनी है तो इसी तरह के गुलाबी कार्ड बनवाकर महिलाओं को दे दिए जाएं। डीएमआरसी और सुरक्षा कर्मियों को सिर्फ महिलाओं के लिए स्टेशन में दाखिल होने और निकलने के लिए एक अलग रास्ते की व्यवस्था करना है। वहां एक सीआइएसएफ का जवान, होमगार्ड या कोई सिविल डिफेंस का जवान इस चीज पर निगाह रखे कि महिलाओं वाले रास्ते से सिर्फ महिलाएं ही आ-जा सकें।

कार सवार बदमाश सहित दो की गोलियों से भूनकर हत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नंद नगरी इलाके की वजीराबाद रोड पर तीन से चार बदमाशों ने कार सवार दो लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। घायल हालत में दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान खूरवेश पहलवान (43) और कंछी लाल (33) के रूप में हुई है।

खूरवेश नंद नगरी थाने का घोषित बदमाश था। इस पर हत्या, रंगदारी समेत कई धाराओं में 41 मुकदमें दर्ज थे और वर्ष 2015 में इस पर मकोका भी लगाया गया था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने जिस रिट्ज कार को वारदात में इस्तेमाल किया था, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार खूरवेश अपने परिवार के साथ प्रताप नगर के बी-ब्लॉक में रहता था। इसके परिवार में पिता राम सिंह, मां कमलेश, पत्नी ममता, बेटा प्रवीण, बेटी लक्षिता और चार भाई हैं। खूरवेश का नंद नगरी इलाके में टीबी केबल का कारोबार था। इसके साथ ही इसी इलाके में अखाड़ा भी चलाता था। कंछी नंद नगरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे। वह जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर की कार चलाते थे।

पिछले साल के मानदंडों पर ही होंगे डीयू में दाखिले : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ **डीयू प्रशासन का फैसला हाई कोर्ट ने किया रद**

▶ **पंजीकरण की तारीख को 22 जून तक बढ़ाने का दिया निर्देश**

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियमों को बदलने के फैसले को हाई कोर्ट ने रद कर दिया। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा व तलवंत सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में डीयू के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में पिछले साल के पात्रता मानदंडों के आधार पर ही प्रवेश होगा। पीठ ने डीयू प्रशासन को रजिस्ट्रेशन की तारीख को 14 जून से बढ़ाकर 22 जून तक करने के निर्देश भी दिए। स्पष्ट किया कि आदेश इस वर्ष पर ही लागू होगा, अगर डीयू प्रशासन अगले शैक्षणिक सत्र में नियमों में संशोधन करना चाहता है तो कर सकता है।

दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को तीन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि नियम में संशोधन का फैसला पहले लिया जा सकता था। कोई यह नहीं कह रहा कि आपका फैसला सही नहीं है, लेकिन इसका समय सही नहीं है। शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए डीयू प्रशासन को कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले नियमों में बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं। पीठ ने डीयू प्रशासन से पूछा कि क्या आप एक दिन पहले ऐसा कर सकते हैं। एक महीने पहले छात्रों को नोटिस देना चाहिए था। पीठ ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

उधर, डीयू प्रशासन ने दलील दी कि वह प्रत्येक वर्ष कोर्स के लिए योग्यता श्रेणी में बदलाव करता है और बुलेटिन ऑफ इनफॉर्मेशन (बीआइएस) में दिए गए मापदंड शैक्षणिक सत्र के लिए होते हैं, न कि हमेशा के लिए। इसलिए बीआइएस में बदलाव के संबंध में पहले से नोटिस देना जरूरी नहीं है। नए नियमों से किसी छात्र को परेशानी नहीं होगी और अगर किसी को होती है तो वह डीयू की शिकायत कमेटी या फिर अदालत का रुख कर सकता है। डीयू ने पीठ से आग्रह किया कि वह इस फैसले में हस्तक्षेप न करे, नहीं तो वर्तमान वर्ष का पूरा शैक्षणिक टाइम-टेबल बिगड़ जाएगा।

..तो बेस्ट ऑफ फोर में एक फीसद का आएगा अंतर : बीकॉम (ऑनर्स), बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र समेत कई स्नातक कोर्स की योग्यता श्रेणी में बदलाव करने के फैसले के खिलाफ दो जनहित याचिकाएं व एक छात्रा की तरफ से याचिका दायर की गई है। बेटी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि अगर शीर्ष चार विषयों में गणित को शामिल किया तो उनकी बेटी के बेस्ट ऑफ फोर में एक फीसद से अधिक का अंतर आ जाएगा। नियमों में बदलाव मनमाना व असंवैधानिक है।

नए मानदंड रद करने की मांग : अधिवक्ता चरणपाल सिंह बागरी ने याचिका में दावा किया कि अंतिम समय में नियमों में संशोधन करने का फैसला स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। पिछले साल तक अगर किसी छात्र को गणित में 50 फीसद अंक आते थे तो वह अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स में आवेदन कर सकता था, लेकिन इस साल बेस्ट ऑफ फोर के लिए गणित के अंकों को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब यह कि गणित शीर्ष चार विषयों में से एक होगा और इनके कुल जोड़ को दाखिले का आधार माना जाएगा। इसी तरह से बीकॉम ऑनर्स में किसी छात्र के लिए गणित-बिजनेस मैथमैटिक्स के कुल जोड़ 45 फीसद अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। इस साल इस मानदंड में संशोधन किया गया है, जिसकी नई शर्तों के मुताबकि छात्र को गणित-बिजनेस मैथमैटिक्स में 50 फीसद या अधिक अंक के साथ पास होना चाहिए और कुल जोड़ अंक 60 फीसद होना चाहिए। नए मानदंड को रद करने की मांग की गई है।

दाखिला नियमों में यह किया गया था बदलाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष दाखिले के मानदंडों को बदल दिया था। इससे सबसे ज्यादा परेशानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स व बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रम में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को हुई।

नए मानदंड के तहत तय किया गया कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए 12वीं में मैथ्स में पास होना जरूरी है। साथ ही मैथ्स को बेस्ट फोर में शामिल किया जाएगा। बेस्ट फोर के कुल फीसद अंक 60 या इससे ज्यादा होने चाहिए। पिछले वर्ष इकोनॉमिक्स ऑनर्स पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए मैथ्स में पास होना अनिवार्य था, लेकिन इसे बेस्ट फोर सब्जेक्ट में शामिल करने की कोई पात्रता नहीं थी। वहीं, बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए 50 अंक मैथ्स एवं बिजनेस मैथ्स में होने अनिवार्य किए गए। वहीं बेस्ट फोर में कुल फीसद अंक 60 फीसद या उससे ज्यादा बनने चाहिए, जबकि पिछले साल बीकॉम ऑनर्स में दाखिला लेने के लिए मैथ्स में किसी प्रकार के अंकों को निर्धारित नहीं किया गया था।

नोएडा, ग्रेनो को बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

ग्रेनो प्राधिकरण में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पौधा देकर स्वागत करते यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह। जागरण

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के यीडा शहर अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे। शहरवासियों को वे तमाम जनसुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसके वे हकदार है। यातायात व्यवस्था को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पुलिसिंग व्यवस्था उच्चकोटि की होंगी। शुक्रवार को तीनों प्राधिकरणों के विकास कार्यों की समीक्षा करने ग्रेटर नोएडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक हुए विकास कार्यों पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तीनों शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहती है। तीनों शहरों में नागरिक सुविधाओं का टोटा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने नागरिक सुविधाओं की अनदेखी की है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के विकास का जो सपना देखा गया था, वह अभी अधूरा है। प्रदेश सरकार इस सपने को अब पूरा करेगी। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें सहायक साबित होगा। इसलिए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होना चाहिए। जमीन अधिग्रहण समेत निर्माण की सभी बाधाओं को अविलंब दूर करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास का विकास उस क्षेत्र के दीर्घकालिक आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार एयरपोर्ट के आसपास अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर विकसित करना चाहती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरी विकास कार्यक्रम में तेजी आनी चाहिए। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर का विकास स्थानीय लोगों के विकास के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने ठोस कूड़ा निस्तारण की समस्या तत्काल दूर करने पर बल दिया। तीनों शहरों में जाम न लगे, इसके लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाने के निर्देश दिए गए। तीनों शहरों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन मानस से लेकर उद्यमी, कारोबारी, किसान आदि सभी को पूर्ण सुरक्षा मिले। कोई भी व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्राधिकरण अधिकारी अब सरकार के विकास के उद्देश्य को पूरा करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ऐसे अधिकारियों को प्राधिकरणों में तैनात नहीं रहने दिया जाएगा, जो विकास में बाधक बनेंगे अथवा जिनके पास विकास का एजेंडा नहीं होगा।

मोंटी चड्ढा के करीबियों पर भी हो सकती है कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ **प्लॉट के नाम पर ठगी के मामले में दो करीबियों की भूमिका संदिग्ध**

▶ **कंपनी के बैंक खातों की भी होगी जांच, ईओडब्ल्यू की पड़ताल जारी**

हाईटेक डेवलपर्स कंपनी द्वारा गाजियाबाद में प्रस्तावित हाईटेक सिटी में प्लॉट देने के नाम पर निवेशकों से करोड़ों की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच जारी है। पुलिस ने कंपनी के निदेशक और वेव ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मोंटी चड्ढा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में अन्य आरोपितों सहित मोंटी चड्ढा के करीबियों की संलिप्तता की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कंपनी के दो करीबियों की भूमिका संदेह के दायरे में है। उन पर कार्रवाई संभव है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मोंटी से इस संबंध में पूछताछ की। इसमें उसने कुछ बातें बताईं और बाकी जानकारी अदालत में देने की बात कही। मोंटी से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। यह पता लगाया जा है कि निवेशकों की रकम किन-किन खातों के जरिये जमा की गई और उसे कहां-कहां और किस-किस मद में खर्च किया गया। कंपनी के तीन से चार खातों के आधार पर रुपये के लेनदेन का पता आर्थिक अपराध शाखा लगा रही है। इस मामले में कंपनी से जुड़े करीब सात मुख्य पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने पांच को दोषी मानकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

फिलहाल पुलिस टीम इससे जुड़े दस्तावेजों और आरोपित के करीबियों की भूमिका की जांच कर रही है। उधर मोंटी की गिरफ्तारी के बाद कंपनी निवेशकों की रकम को लौटाने की कवायद में जुट गई है। पुलिस की मानें तो मामला अदालत और कई निवेशकों से जुड़े होने के कारण तमाम कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत के संज्ञान में होगी। ईओडब्ल्यू ने निवेशकों से करोड़ों की ठगी में रियल स्टेट कारोबारी मोंटी चड्ढा उर्फ मनप्रीत सिंह चड्ढा को बुधवार को आइजीआइ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। आरोपित रियल स्टेट और शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा का बेटा है। महरौली में चड्ढा बंधुओं की गोलीबारी में पोंटी की मौत हो गई थी। मोंटी चड्ढा पर प्लॉट के नाम पर 29 निवेशकों से साढ़े छह करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। उसने 1500 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित हाईटेक सिटी में लोगों को प्लॉट दिलाने का झांसा दिया था।

कटऑफ की नई तारीखें जारी कर सकता है डीयू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट के शुक्रवार को आए फैसले के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन को दाखिला प्रक्रिया के मानदंडों को फिर से बदलना पड़ेगा। डीयू प्रशासन ने इस वर्ष बीकॉम ऑनर्स व इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ अन्य पाठ्यक्रमों के पात्रता मानदंडों को बदल दिया था। वहीं, अदालत ने डीयू प्रशासन को रजिस्ट्रेशन की तारीख भी 14 जून से बढ़ाकर 22 जून तक करने का निर्देश दिया है। इससे डीयू कटऑफ की नई तारीखें भी जारी कर सकता है। उसने पहले कटऑफ की तारीख 20 जून निर्धारित की थी। मामले में डीयू प्रशासन की तरफ से जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। डीयू के रजिस्ट्रार ने 22 जून को अकादमिक परिषद की बैठक बुलाई है। शनिवार को डीयू की दाखिला समिति की तरफ से बैठक बुलाए जाने के भी संकेत हैं, जिसमें उन सभी पाठ्यक्रमों के पात्रता मानदंडों पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है, जिन पर छात्रों ने सवाल उठाए थे।

अकादमिक परिषद के सदस्य प्रोफेसर रसाल सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि डीयू हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। डीयू में बड़ी संख्या में छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। कई कॉलेज और विभाग हैं। प्रवेश प्रक्रिया में इन सभी की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, क्योंकि ये सब हितधारक हैं। सभी कॉलेजों की स्टाफ काउंसिल, सभी विभागों की कमेटी ऑफ कोर्स, विभागीय शोध समिति, संकायों के शोध मंडल, संकायों की प्रवेश समिति, स्टैंडिंग कमेटी और अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की तमाम विधायी संस्थाओं की संस्तुतियों और निर्णयों से ही डीयू की प्रवेश नीति अंतिम रूप लेती है। इसलिए इस प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध होने के साथ सरल भी होना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि एग्जाम ब्रांच की तरह अलग से एडमिशन ब्रांच भी होनी चाहिए, जो सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके प्रवेश नीति बनाए।

शिक्षक संगठनों ने डीयू प्रशासन पर उठाए सवाल : इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस के संयोजक और एसोसिएट प्रोफेसर पंकज गर्ग ने कहा कि नए मानदंड अकादमिक परिषद (एसी) और कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में स्वीकृति के लिए नहीं लाए गए। यह डीयू प्रशासन का गलत फैसला था, जिसका खामियाजा लाखों छात्रों को झेलना पड़ेगा।

व्यवस्था

एयरपोर्ट पर लगाई गईं एक लाख एलईडी लाइट, अभी और लगेंगी, 50 फीसद बिजली की होगी बचत, सफेद रोशनी में पौधों को भी मिलेगा पोषण

विशेष एलईडी लाइट से जगमग होगा आइजीआइ एयरपोर्ट

संतोष शर्मा, नई दिल्ली

देश के सबसे बड़े इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) पर नए-नए प्रयोग होते रहते हैं। यहां यात्री सुविधा में विस्तार के प्रयास के साथ ही ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण को बचाने की पहल भी जारी है। इसी कड़ी में एयरपोर्ट पर विशेष प्रकार की लाइट लगाई जा रही हैं। इनके दूधिया प्रकाश से न केवल एयरपोर्ट की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि इनसे कम गर्मी उत्पन्न होगी। इनकी सफेद रोशनी से वहां लगाए गए इनडोर पौधों का भी पोषण होगा। विशेष एलईडी से एयरपोर्ट पर 50 फीसद बिजली की बचत की जा सकेगी। एक लाइट 50 हजार घंटे तक चलेगी।

दरअसल, वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सफेद प्रकाश से पौधों का विकास ज्यादा होता है। इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद मिलती है। वहीं, लाइट से कम गर्मी निकलने से वहां के एयर कंडीशनिंग पर दबाव भी कम पड़ता है। इससे बिजली की अतिरिक्त बचत हो सकेगी।

आइजीआइ एयरपोर्ट पर वर्तमान में टर्मिनल के अंदर स्थित लाउंज, इमिग्रेशन-डिपार्चर, चेक-इन और रिटेल एरिया सहित सीढ़ी के अलावा एप्रन क्षेत्र में एक लाख एलईडी लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। अभी 35 फीसद लाइट ही लगी हैं। शेष 65 फीसद लाइट लगाने का काम वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूरा कर लिया जाएगा।

एयरपोर्ट संचालक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के मुताबिक एयरपोर्ट पर ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के प्रति विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अलग-अलग प्रयासों से एयरपोर्ट पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में जहां कार्बन उत

2 नए कमान तैनात करेगी सेना शिमला में। इसके बाद यहां जवानों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बीच, सेना ने बेहतर समन्वय और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास होने के कारण ट्रेनिंग कमान को शिमला से मेरठ स्थानांतरित करने का फैसला किया है।

तेलंगाना में भाजपा देख रही दक्षिण का पश्चिम बंगाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीएम चंद्रशेखर राव के पैतृक गृह और उनकी पुत्री की सीट जीतने के बाद उत्साहित भाजपा ने तय की रणनीति
- आने वाले शहरी निकाय चुनाव में होगी सत्ताधारी पार्टी के साथ सीधी लड़ाई

लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले पश्चिम बंगाल की तरह भाजपा की भावी रणनीति में अब तेलंगाना सबसे ऊपर है। केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश इकाई को स्पष्ट निर्देश है कि जमीनी स्तर पर ऐसे मुद्दों पर अभियान तेज किया जाए जो हर वर्ग के लिए अहम हो। पहली परीक्षा यूं तो आने वाले शहरी निकाय चुनाव में ही होगी। कोशिश होगी कि वह चुनाव भाजपा और सत्ताधारी टीआरएस के बीच सीधी लड़ाई वाला हो। साढ़े चार साल बाद विधानसभा और फिर अगले लोकसभा चुनाव के लिए भी अभी से विस्तार की योजना तैयार हो गई है जिसमें प्रदेश इकाई के साथ-साथ केंद्रीय नेतृत्व को भी लगातार नजर रखने को कहा गया है।

गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खासकर तीन राज्यों का नाम लिया था जहां पार्टी का प्रदर्शन उत्साहित करता है। इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ तेलंगाना भी शामिल था। तेलंगाना का प्रदर्शन इसलिए उत्साहित करता है, क्योंकि वहां से चार सीटों की कल्पना बहुत कम लोगों ने की थी। भाजपा की जीत इसलिए भी अहम थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही बहुमत से जीते मुख्यमंत्री

अमित शाह जागरण आर्काइव

चंद्रशेखर राव की बेटी ही नहीं, खुद राव की पुरानी सीट करीमनगर भी भाजपा ने जीत ली। करीमनगर की जीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह राव की जन्मभूमि भी है और तेलंगाना आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। राव अपनी योजनाओं की शुरुआत भी यहीं से करते रहे हैं। अब यह भाजपा के खाते में है।

इस जीत के कई कारण रहे हैं। एक तो पश्चिम बंगाल की तरह प्रदेश अध्यक्ष डा. के लक्ष्मण की अगुआई में स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन तेज रहा। खासकर महंगी शिक्षा, रोजगार आदि के मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। केंद्र की योजनाओं को लेकर प्रदेश इकाई पूरे प्रदेश में पहुंची। जातिगत विस्तार पर ध्यान रहा। खुद प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से आते हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या पचास फीसद से ऊपर है और आबादी के लिहाज से बहुत छोटे वर्ग वेलम्मा से आने वाले चंद्रशेखर राव इसी पिछड़ी जाति के बल पर सत्ता में लौटे थे।

डा. लक्ष्मण की रणनीति है कि आने वाले दिनों में पिछड़े वर्ग में और ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की जाए। फिलहाल भाजपा लोकसभा चुनाव में 19 फीसद वोट ही हासिल कर पाई है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की नजर कांग्रेस पर भी टिकी है और रणनीति यह है कि तेलंगाना को कांग्रेस मुक्त कर रेड्डी समुदाय में पकड़ बनाई जाए। इसी रणनीति के तहत पिछले दिनों रेड्डी समुदाय के नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया।

बताते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस समेत दूसरे दलों के कई और नेता भाजपा में आ सकते हैं। पार्टी का और विस्तार हर जाति वर्ग में होगा। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश को निर्देश है कि निकाय चुनाव में कोई कसर न छूटे। कांग्रेस मुक्त तेलंगाना की शुरुआत यहीं से करने की कोशिश होगी। कर्नाटक के बाद दक्षिण में भारत का यह दूसरा प्रवेश द्वार होगा।

छह से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- हमारा लक्ष्य दो करोड़ 20 लाख नए सदस्य बनाने का : शिवराज
- हर बूथ में कम से कम 25 सदस्य किए जाएंगे सुनिश्चित

लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नए सिरे से अपनी सदस्यता बढ़ाने के अभियान में जुट गई है। 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी भाजपा का लक्ष्य कम से कम 20 फीसद नए सदस्य जोड़ने का है। जोर इस पर होगा कि भाजपा हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर बूथ में मौजूद हो। इस दौरान भाजपा की कोशिश संगठनात्मक रूप से कमजोर राज्यों में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने पर होगी। सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान छह जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा। सदस्यता मिस्ड काल से होगी लेकिन साथ ही फार्म भी भरे जाएंगे।

प्रदेश प्रभारियों की बैठक 17 जून को होगी और आगे का लक्ष्य तय कर दिया जाएगा। एक जुलाई तक सभी जिलों की बैठक संपन्न होगी जिसमें मंडल और बूथ तक इसे

शिवराज सिंह चौहान जागरण आर्काइव

क्रियान्वित करने की रणनीति बना दी जाएगी। सदस्यता अभियान को संगठन पर्व की संज्ञा देते हुए शिवराज ने कहा कि देश के युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगाव है। इसे देखते हुए पार्टी बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों को भी सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दो करोड़ 20 लाख नए सदस्य बनाने का है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। कई राज्यों में इससे अधिक सदस्य बनाने की कोशिश होगी। इनमें खासतौर पर उन राज्यों पर जोर दिया जाएगा, जिनमें भाजपा की मौजूदगी कम है और संगठनात्मक रूप से अपेक्षाकृत है। खासतौर पर बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, ओडिशा, कश्मीर घाटी, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में सघन अभियान चलाया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि इन राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर रहा था।

नए सदस्यता अभियान की शुरुआत जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन छह जुलाई से होगी और 6 जुलाई से 10 अगस्त तक और फिर 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सक्रिय सदस्य बनाने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में शिवराज ने बताया कि मिस्ड काल के साथ ही फार्म भी इसलिए भरवाए जाएंगे ताकि कोई असमंजस न रहे।

नीट को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता एवं दाखिला परीक्षा (नीट)-2019 को चुनौती देने वाली एक याचिका को सुनने से इन्कार कर दिया। नीट को लेकर छात्रों के एक समूह ने याचिका दायर की थी और दावा किया था कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हुई नीट के चार सवालों के उत्तर गलत थे। नीट को पांच मई को कराया गया था।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और सूर्यकांत की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा कि जज विषयों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायाधीश उन लोगों से बेहतर विशेषज्ञ नहीं हैं जिन्होंने सवालों की जांच की है। पीठ इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ ने छात्रों की प्रश्नों के उत्तर के लिए संबंधित विषय के विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की अपील को भी खारिज कर दिया। बाद में याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली। नीट-2019 की काउंसिलिंग 19 जून से शुरू होगी। गुरुवार को न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी तथा अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन पीठ छात्रों की याचिका सुनने पर राजी हो गई थी। याचिका हैदराबाद के छात्र कायथी रोहन रेड्डी तथा तीन अन्य छात्रों की ओर से एडवोकेट महफूज नाजकी ने दायर की थी।

नीति आयोग की बैठक में केंद्र की घेराबंदी करेंगे कांग्रेसी मुख्यमंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नीति आयोग की शनिवार को होने वाली बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक सुर में बोलते दिख सकते हैं। इन मुख्यमंत्रियों ने पूरी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक से एक दिन पहले दिल्ली में अहम बैठक की है। यह बैठक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिल्ली स्थित आवास पर रखी गई थी। जहां इन सभी मुख्यमंत्रियों को रात्रिभोज भी दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की इस बैठक को कांग्रेसी मुख्यमंत्री गंभीरता से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में नीति आयोग की यह पहली बैठक है। माना जा रहा है कि इनमें कांग्रेस शासित राज्य अपने मुद्दों के साथ-साथ पार्टी के एजेंडे को भी प्रमुखता से रख सकते हैं।

कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक से एक दिन पहले जिस तरह से दिल्ली पहुंचकर रणनीतिक चर्चा की है, उसे राजनीतिक रूप से सरकार को घेरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर रखी गई इस बैठक में सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। इनमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को न्योता भेजा गया। देर शाम तक पंजाब को छोड़ अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए थे। मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में लोकसभा चुनाव के बाद की स्थितियों को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीमार हैं जिस कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।

हिंदी की अनिवार्यता खत्म करने को साजिश मान रहे सदस्य

नई शिक्षा नीति ▶ सदस्यों ने कहा, मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट ही असली

डॉ. कुरील ने कहा-बदलाव के पीछे की साजिशों की होनी चाहिए जांच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से हिंदी की अनिवार्यता को खत्म किए जाने का विरोध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। विरोध में उतरे नीति तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों के मुताबिक मसौदे में किए गए बदलाव के पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि दस्तावेज में जिस हिंदी को पिछले साठ साल से भी अधिक समय से अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने का जिक्र था, उसे इस नई शिक्षा नीति के मसौदे से चुपचाप गायब कर दिया गया।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वाली कमेटी के वरिष्ठ सदस्य डॉ. कृष्ण मोहन त्रिपाठी के मुताबिक हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की सिफारिश पहली बार 1956 में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने की थी। उसी ने ही त्रिभाषा का भी यह फार्मूला दिया था। इसके बाद डॉ. डीएस कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग ने भी त्रिभाषा फार्मूले के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अनिवार्य रूप से हिंदी को

प्रतीकात्मक।

पढ़ाने की बात कही। हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने के जिक्र को कभी भी दस्तावेज से हटाया नहीं गया, जबकि नई शिक्षा नीति में ऐसा किया गया है।

नीति का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के दूसरे सदस्य डॉ. आरएस कुरील के मुताबिक नीति में जो विषय सर्वसम्मति से शामिल किया गया है, उसे बगैर चर्चा के हटाने का कदम किसी साजिश की ओर इशारा करता है। वैसे भी नीति की किसी सिफारिश को मानने या ना मानने का फैसला सरकार का होता है, लेकिन नीति से ऐसे विषय को कभी भी हटाया नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। यह बदलाव किसकी मर्जी से किया गया है। कमेटी ने मानव संसाधन विकास मंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी है, उनमें त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की सिफारिश है। जिस मसौदे पर लोगों से राय ली जा रही है, वह बदला हुआ है। उन्होंने कहा कि असली मसौदा तो वहीं है, जो कमेटी ने मंत्री को सौंपा है।

जनमत
मुद्दा

क्या नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले को हटाकर सरकार हिंदी के प्रसार के दायित्व से पीछे हट रही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

facebook.com/muddajagran
mudda@jagran.com

धनंजय मुंडे को गैरकानूनी भूमि खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सरकारी जमीन की गैरकानूनी खरीद करने पर राकांपा नेता और महाराष्ट्र के एमएलसी धनंजय मुंडे के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को शीर्ष कोर्ट का आदेश आने से पहले ही एफआइआर दर्ज की जा चुकी थी।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की पूर्ण शक्ति कोई रामबाम नहीं है और संयम से इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। जस्टिस अजय रस्तोगी और सूर्य कांत की अवकाश कालीन पीठ ने मुंडे की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। राकांपा नेता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने बीड़ जिले के अंबाजोगई तहसील में पुस गांव में जमीन खरीदने के लिए पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा, 'जो बात हमें चिंता में डाल रही है वह हाई कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। इस तरह शक्तियों के इस्तेमाल के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट की पूर्ण शक्ति का संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह रामबाम नहीं है।' शुरू में ही मुंडे की पैरवी कर रहे वकील अमरेंद्र शरण ने कोर्ट को सूचित किया कि महाराष्ट्र पुलिस हाई कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर चुकी है। पीठ ने कहा कि शिकायत और एफआइआर रद करने की जरूरत है। कोई शिकायत नहीं की गई और पुलिस पहले कह चुकी है कि कोई मामला नहीं बन रहा है।

राहुल की जगह कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पीछे हटे एके एंटनी

एके एंटनी फाइल

- एंटनी बोले, स्वास्थ्य कारणों से अध्यक्ष पद संभालने में असमर्थ हूं
- केसी वेणुगोपाल ने भी कार्यकारी अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव ठुकराया

केसी वेणुगोपाल फाइल

नई दिल्ली, आइएएनएस/एएनआइ : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अपने इस्तीफे की पेशकश पर अड़े रहने से पार्टी का वर्तमान संकट खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने उनकी जगह अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से हाथ खींच लिए हैं। वहीं, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने का प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति तलाशने का जिम्मा सौंपा गया है। इस संबंध में जब उन्होंने एके एंटनी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उनके मन में गांधी परिवार के लिए बेहद सम्मान है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह अध्यक्ष का पद संभालने में असमर्थ हैं। इसी तरह कर्नाटक मामलों के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल को कार्यकारी अध्यक्ष पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह पार्टी को मजबूत करने की दूसरी भूमिका में व्यस्त हैं। बता दें कि कर्नाटक में जदएस के साथ सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 में से सिर्फ एक सीट हासिल हुई है। जबकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 225 सीटों में से कांग्रेस को 78 सीटें मिली थीं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस नेता अब नेतृत्व के लिए किसी उत्तर भारतीय चेहरे की तलाश में जुट गए हैं। पार्टी प्रेसिडियम सिस्टम के साथ-साथ कई कार्यकारी अध्यक्षों की व्यवस्था के विकल्प पर भी विचार कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय के बजाय एआइसीसी से दी गई मंजूरी : महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल की नियुक्तियों को मंजूरी शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) की ओर से दी गई। इस आशय का पत्र एआइसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जारी किया गया। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियों की मंजूरी का पत्र कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय से जारी किया जाता है। इससे माना जा रहा है कि राहुल अभी भी अपने फैसले पर अडिग हैं। लेकिन इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे।

कोर्ट का बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर तुरंत सुनवाई से इन्कार

- पीठ ने याची वकील से प्रार्थना में सुधार के लिए रजिस्ट्रार से संपर्क करने को कहा

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हुए नए सिरे से लोकसभा चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार कर दिया। यह याचिका अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और सूर्य कांत की अवकाश कालीन पीठ ने तुरंत सुनवाई से इन्कार करते हुए पीआइएल दायर करने वाले वकील मनोहर लाल शर्मा से अपनी प्रार्थना में सुधार के लिए रजिस्ट्रार से संपर्क करने को कहा। शर्मा ने गुरुवार को शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हुए नए सिरे से लोकसभा चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की थी। अपनी याचिका में शर्मा ने दावा किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक, चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही कराए जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वकील ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव को निरस्त करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ याचिका दायर करने पर शीर्ष कोर्ट ने शर्मा पर 50,000 रुपये का जुर्माना किया था।

ईवीएम पर संदेह जताने के लिए नकवी ने कांग्रेस की आलोचना की

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर संदेह जाहिर करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सबसे पुरानी पार्टी चुनाव में पराजय के लिए अपना मूल्यांकन करने की जगह अहंकार प्रदर्शित कर रही है। ईवीएम विलाप मंडली फिर से सक्रिय हो गई है। पहले तो वीवीपैट पर्ची का ईवीएम से मिलान करने की मांग की अब कोई चूक नहीं पाने के बाद बहाना ढूंढ रही है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभियान की तैयारी में सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शनिवार को होगी चर्चा
- बैठक में जल शक्ति मंत्री को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है

बारिश का पानी सहेजने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार यह अभियान राज्यों के साथ मिलकर चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को होने वाली बैठक में इसकी रूपरेखा पर विचार-विमर्श होने जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुद्दा सबसे ऊपर है। इसमें राज्यों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजनाएं तैयार करने के लिए आग्रह किया जाएगा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए काउंसिल की बैठक में जल शक्ति मंत्री को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मुद्दे पर ऐसे समय विचार करने जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही देश के सभी सरपंचों को खुद पत्र लिखकर बारिश का पानी बचाने का इंतजाम करने को कहा है। सूत्रों ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि बारिश के दौरान खेत का पानी खेत में जमा किया जाए, जबकि गांव का पानी गांव के पोखर व तालाब में जमा हो। इससे स्थानीय स्तर पर ही पानी की जरूरत पूरी हो सकेगी। साथ ही कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी।

सूत्रों ने बताया कि गांवों के साथ-साथ शहरों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ वित्तीय प्रोत्साहन घोषित कर सकती है। यह घोषणा आगामी आम बजट में हो सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर सरकार के प्रस्तावित अभियान के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि अभी इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम 'मन की बात' कार्यक्रम में भी इस संबंध में लोगों से अपील कर सकते हैं।

कर्नाटक में सरकार बचाने के लिए कुमारस्वामी ने दो निर्दलीय विधायकों को बनाया कैबिनेट मंत्री

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपने मंत्रिमंडल में दो निर्दलीय विधायकों को शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने 13 माह पुरानी अपनी गठबंधन सरकार को स्थिरता देने के लिए यह कदम उठाया है।

आर. शंकर और एच. नागेश को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इन दोनों ने पहले सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और भाजपा के करीब चले गए थे। इसके बाद यू टर्न लेते हुए दोनों सत्ताधारी गठबंधन के करीब आ गए। यह कदम गठबंधन में उपजे असंतोष को थामने और दोनों विधायकों के फिर से विरोधी खेमे में जाने से रोकने के लिए उठाया गया है। शंकर को कांग्रेस खाते से और नागेश को जदएस खाते से मंत्री बनाया गया है। गठबंधन की व्यवस्था के अनुसार कुल 34 मंत्रियों में से कांग्रेस और जदएस के खाते में क्रमशः 22 और 12 मंत्रियों के पद हैं। दो निर्दलीय विधायकों के सरकार में शामिल होने के बाद 224 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन की ताकत 118 हो गई है। कांग्रेस के 78, जदएस के 37, बसपा के एक और दो निर्दलीय विधायक हैं। भाजपा के पास 105 विधायक हैं।

बेंगलुरु में शुक्रवार को शपथ समारोह के बाद राज्यपाल वजुभाई वाला। साथ में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (बाएं से दूसरे), उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर और मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले निर्दलीय विधायक आर शंकर (बाएं) और एच नागेश (दाएं)। प्रेट्र

विस्तार से पहले तीन पद खाली थे। दो जदएस कोटे से और एक कांग्रेस कोटे का पद था। राज्यपाल वजुभाई वाला ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने से पहले शंकर ने कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया से मुलाकात की और उन्हें अपनी पार्टी कर्नाटक प्राजनावंत जनता पक्ष के कांग्रेस में विलय करने का पत्र सौंपा। हालांकि हाल ही में जदएस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले एच. विश्वनाथ और एमएलसी बीएम फारूक का नाम तीसरे खाली पद के लिए चल रहा था, लेकिन जदएस नेतृत्व ने इस पद को अभी खाली रखने का फैसला लिया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

होगी सुनवाई

आइपीसी की धारा 149 की वैधानिकता को दी गई है चुनौती, शीर्ष अदालत ने याचिका पर अटार्नी जनरल को जारी किया नोटिस

परखा जाएगा उन्मादी भीड़ का हिस्सा रहने का कानून

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अपराध के समान उद्देश्य से एकत्रित गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा रहे हर व्यक्ति को उस अपराध का दोषी मानने का कानून, भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 149 सुप्रीम कोर्ट के स्कैनर पर है। कोर्ट इस कानून की वैधानिकता परखेगा। कोर्ट ने धारा 149 को चुनौती देने वाली याचिका पर अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। मामले पर गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर सुनवाई होगी।

सरल भाषा में इस धारा का मतलब है कि अगर कोई अपराध के समान उद्देश्य से हथियार के साथ दंगाई भीड़ में शामिल था और उस भीड़ में से किसी ने किसी की हत्या कर दी तो भीड़ में शामिल हर व्यक्ति हत्या का दोषी माना जाएगा।

याचिकाकर्ता का कहना है कि हो सकता है कि भीड़ में शामिल हर व्यक्ति उतना गंभीर अपराध न करना चाहता हो जितना दूसरे ने कर दिया इसलिए हर व्यक्ति को उसकी भूमिका के मुताबिक सजा होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि यह कानून ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए 1857 की क्रांति के समय लाया गया था। मूल कानून में इस धारा की अवधारणा नहीं थी। अब आजादी के बाद भी इस कानून के तहत अदालतें बिना सोचे समझे सजा दे रही हैं जो कि संविधान के तहत प्राप्त बराबरी, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों का हनन है।

कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली यह रिट याचिका मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले हजारी और नाथूलाल ने दाखिल की है जिन्हें इसी धारा के तहत अन्य 21 लोगों के साथ हत्या के जुर्म में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन पीठ ने वरिष्ठ वकील सुशील कुमार जैन की दलीलें सुनने के बाद मामले पर विचार का मन बनाते हुए अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया है।

धारा 149 को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह धारा आइपीसी के चेप्टर आठ का भाग है जो शांति भंग के अपराधों की बात करता है। इसमें धारा 141 से लेकर 149 तक के प्रावधान दिये गये हैं। जिसमें गैर कानूनी भीड़ किसे कहा जाएगा किसे ऐसी भीड़ का सदस्य माना जाएगा, इसका उल्लेख है। हथियार व बिना हथियार के उस भीड़ का हिस्सा रहने पर छह महीने से लेकर तीन साल तक की सजा की बात धारा 141 से लेकर 148 तक की गई है। जबकि धारा 149 अलग तरह के अपराध की बात करती है।

याचिका में कहा गया है कि धारा 149 का अदालतें मनमाना उपयोग कर रही हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हथियार के साथ दंगाई भीड़ का हिस्सा रहता है लेकिन आगे बढ़कर अपराध में हिस्सा नहीं लेता है तो उसे धारा 149 के तहत सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने स्वयं के केस का उदाहरण देते हुए कहा है कि उसे धारा 149 के साथ धारा 302 में उम्रकैद की सजा दी गई है जबकि उसने क्या अपराध किया था यह स्पष्ट नहीं है। सिर्फ इतना स्पष्ट है कि वह हमला करने वाली भीड़ में शामिल था और उसके हाथ में लाठी थी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग ने इस धारा में संशोधन से यह कहते हुए मना कर दिया था कि इसमें सजा आइपीसी की धारा 38 के मुताबिक होगी यानी जिसने जितना अपराध में हिस्सा लिया उसे उतनी सजा मिलेगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि वास्तव में अदालतें ऐसा नहीं करती इसलिए धारा 149 को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 15 जून 2019

1 जुलाई से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5000 की जगह 6500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3250 की जगह 4500 रुपये मानदेय मिलेगा छत्तीसगढ़ में। भूपेश सरकार ने मानदेय बढ़ाकर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है।

सिद्धू का विभाग बदलने के बाद भूजल अथॉरिटी बिल ला सकती है सरकार

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

इस बार जहां देश के कई महानगरों में पीने के पानी के संकट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर फोकस करने को मजबूर कर दिया है, वहीं कैप्टन और सिद्धू के विवाद में पंजाब को भी नई भूजल अथॉरिटी मिल सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू स्थानीय निकाय महकमे के मंत्री होने के नाते यह आरोप लगाते रहे हैं कि भूजल अथॉरिटी उनके विभाग में हस्तक्षेप है, जिसके चलते यह बिल कई महीनों से रुका हुआ है। अब उनके इस महकमे से हटने व उनकी जगह ब्रहम मोहिंदरा के आने के बाद भूजल अथॉरिटी बनाने का रास्ता साफ हो सकता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने भूजल अथॉरिटी का बिल आने वाले विधानसभा सेशन में लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

नवजोत सिंह सिद्धू जागरण आर्काइव

पंजाब में भूजल चिंताजनक स्तर तक गिर चुका है, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वाटर पॉलिसी लाने को कहा था। पंजाब किसान आयोग ने यह पॉलिसी तैयार कर ली, जिसमें केंद्रीय जल अथॉरिटी की तरह राज्य जल अथॉरिटी बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें न केवल भूजल, बल्कि बरसाती और नदियों के पानी को भी रेगुलेट करने की योजना भी है। पिछले बजट सेशन में सरकार इसका बिल ला रही थी, लेकिन जिस दिन यह बिल पेश होना था, उसी दिन स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इसका विरोध कर दिया। लिहाजा यह बिल मौके पर ही वापस ले लिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इस बात को लेकर अड़ गए कि यह उनके विभाग में दखलअंदाजी है।

क्या होगा बिल में : इस बिल में शहरों में बरते जाने वाले पानी को रेगुलेट करने, उसकी दरें निश्चित करने आदि का अधिकार अथॉरिटी के पास जाना था। सिद्धू का कहना था कि यह उनके महकमे में दखलअंदाजी है। मुख्यमंत्री ने सिद्धू को मनाने के लिए उनकी अगुआई में एक कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया और इन्हें इजरायल भेजने का प्रस्ताव रखा, ताकि कमेटी पानी के संकट और उससे निजात पाने के समाधान को सीख सके। विभाग का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू का यह तर्क सही नहीं है कि वाटर अथॉरिटी किसी के काम में हस्तक्षेप करेगी।

अथॉरिटी का काम पानी को मैनेज करना है। इसमें नहरी पानी, बरसाती पानी और भूजल तीनों शामिल हैं। वैसे भी स्थानीय निकाय विभाग के एक्ट में साफ है कि वह केवल पीने के पानी को लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। वहां भी पानी सिंचाई विभाग ही नहरों या रजबाहों से भेजता है। अगर यह हस्तक्षेप है तो बिजली भी दूसरा विभाग ही लोगों को उपलब्ध करवाता है? यह लोकल बॉडीज की अपनी तो नहीं है। सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि दरअसल समस्या यह है कि ड्राफ्ट बिल में खेती के लिए उपयोग हो रहे पानी को निकाल दिया है। शहरी सीटों से जुड़े हुए विधायकों और मंत्रियों का लगता है कि वाटर चार्जेस बढ़ाने से शहरी वोट बैंक पर असर होगा।

राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत में अंतर नहीं बता पाई इंदौर की महापौर

नईदुनिया, इंदौर : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत में अंतर नहीं बता पाईं। इस वीडियो में एक पत्रकार के पूछने पर महापौर ने पहले राष्ट्र गान (जन-गण-मन) का सही उत्तर दिया और कहा कि राष्ट्र गान खड़े होकर गाना पड़ता है। बैठकर गाने से उसका अपमान होता है। बाद में उन्होंने जन-गण-मन को राष्ट्र गीत बताया और कहा राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान एक ही हैं।

यह वीडियो नगर निगम के बुधवार को हुए बजट सम्मेलन का है, जिसमें राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत को लेकर गफलत हुई थी। पार्षदों को सम्मेलन की शुरुआत में 'वंदे मातरम्' गाना था, लेकिन उन्होंने 'जन-गण-मन' गा दिया। बाद में गलती का अहसास हुआ तो 'जन-गण-मन' बीच में रोककर 'वंदे मातरम्' शुरू किया गया।

मामले की शिकायत नेता प्रतिपक्ष फौजिया अलीम ने संभागायुक्त, कलेक्टर और निगमायुक्त से की है। इस मामले में महापौर ने कहा कि बुधवार को सम्मेलन के दौरान शोरगुल में मुझसे सवाल किया गया था, इसलिए मैं ठीक तरह से सुन नहीं पाई। संभवतः इसीलिए गफलत हुई होगी।

महागठबंधन की नाव मझधार में ले जा रहे मांझी

अरविंद शर्मा, पटना

- साल भर बाद होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन नहीं मिल रहे घटक दलों के सुर-ताल
- मांझी ने तेजस्वी यादव को अपरिपक्व और बच्चा बताया

लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद बिहार में महागठबंधन की नाव फंसी हुई नजर आ रही है। सालभर बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन घटक दलों के सुर-ताल अलग-अलग हैं। गठबंधन की गांठ खुलती जा रही है। सबसे बड़े घटक दल के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव दो हफ्ते से 'गायब' हैं। इस बीच, सहयोगी दलों को सीटें बांटने की बेताबी है। न लोकसभा चुनाव में हार की संयुक्त समीक्षा, न आगे के लिए समन्वय। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) प्रमुख जीतनराम मांझी ने विधानसभा की 35 सीटें अपने लिए तय कर ली हैं, तो रालोसपा भी पीछे क्यों रहती। उपेंद्र कुशवाहा को भी 27 सीटों से कम नहीं चाहिए। करीब दस दिन पहले इफ्तार की दावतों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आत्मीय तरीके से मेल-जोल बढ़ाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने तो महागठबंधन के नेता पर 'प्रहार' भी शुरू कर दिया है।

महागठबंधन के सबसे बुजुर्ग एवं अनुभवी नेता मांझी सियासी व्यवहार के साथ-साथ बयानों से भी तेजस्वी पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के अज्ञातवास पर तंज कसा है। कहा है कि हार के सदमे से उबरने के लिए वह कहीं रिफ्रेश होने गए हैं। दो कदम आगे बढ़कर मांझी ने लालू प्रसाद के सियासी उत्तराधिकारी को अपरिपक्व और बच्चा बताया है। खुद से तुलना की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की उम्र कम है। वह लालू प्रसाद और मेरी तरह परिपक्व नहीं हैं। उम्र का हवाला देकर पूर्व सीएम ने नेता प्रतिपक्ष की सियासी समझदारी पर भी सवाल खड़ा किया है। दो-दो सीटों से पराजित होकर उपेंद्र कुशवाहा भी दोहरे सदमे में हैं। उनके अगले कदम का इंतजार है।

फिर डोल रहा मांझी का मन : कांग्रेस से सियासी सफर की शुरुआत और नीतीश कुमार की कृपा से 2014 में बिहार की सत्ता संभालने वाले जीतनराम मांझी की गतिविधियां और बेबाक अभिव्यक्तियां बता रही हैं कि महागठबंधन का माहौल उन्हें रास नहीं आ रहा है। उनका मन फिर डोल रहा है। तीन और चार जून के बीच 24 घंटे में सीएम नीतीश कुमार से दो-दो बार मुलाकात का बहाना भले ही इफ्तार की दावत हो सकता है, किंतु मिलने का तरीका और सियासत का हाल संकेत कर रहा है कि उन्हें नए कुनबे की तलाश है। आना-जाना शुरू हो चुका है। आगे का सफर अभी बाकी है।

जीतनराम मांझी जागरण आर्काइव

लोस चुनाव में हार की आज समीक्षा करेगी कांग्रेस

बिहार में राजद के साथ गठजोड़ के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों पस्त हो गई, पड़ताल आज होगी। नतीजे के तीन हफ्ते बाद सदानंद सिंह के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता एक साथ बैठेंगे। विधानसभा सत्र के बहाने आत्मावलोकन करेंगे और लोकसभा चुनाव में साथी दलों की मदद की मात्रा को भी तराजू पर चढ़ाएंगे। किसने किसकी कितनी मदद की। वैसे दोनों दलों की ओर से अभी तक पर्याप्त बयानबाजी हो चुकी है। दूसरे पर हवा में तीर चलाए जा चुके हैं। अब उसपर समीक्षा का मुलम्मा चढ़ाया जाएगा। हालात बता रहे हैं कि दोनों साथी दलों के रिश्तों में अब पहले की तरह गर्मजोशी नहीं रह गई है।

टीवी सीरियल की भाषा में ही हो कास्टिंग क्रेडिट और टाइटल

नई दिल्ली, प्रेट्र/एएनआइ : टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले सीरियल और कार्यक्रमों के कास्टिंग, क्रेडिट और टाइटल को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिखाने को अनिवार्य बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया। सरकार का कहना है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है।

सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इसके दायरे में फिल्मों को लाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। जावड़ेकर ने कहा, 'टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सीरियल या कार्यक्रमों के शुरू या आखिर में टाइटल दिखाया जाता है, जो ज्यादातर समय अंग्रेजी में होता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के मकसद से हम सभी टीवी चैनल को यह आदेश जारी कर रहे हैं कि जिस भाषा में कार्यक्रम हो उसी भाषा में उसका टाइटल भी दिखाएं। इसके अलावा अगर वे टाइटल और क्रेडिट को अंग्रेजी भाषा में भी देना चाहते हैं तो वे इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल अनिवार्य है।'

किसी भाषा पर नहीं लगा रहे रोक : जावड़ेकर ने स्पष्ट करते हुए कहा, 'हम किसी भाषा पर रोक नहीं लगा रहे, वास्तव में हम भारतीय भाषाओं को जोड़ रहे हैं।' केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। देशी भाषा को दर्शक भी आसानी से समझते हैं।

बिहार में बीपीएल और एपीएल सबको मिलेगा वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ

राहत ▶ अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू, आधार कार्ड अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आरंभ किया। इसके तहत 1.35 लाख वृद्धों के बैंक खाते में पेंशन योजना की दो माह यानी अप्रैल और मई की राशि स्थानांतरित की गई। अब तक दो लाख लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। उम्मीद है कि 35 से 36 लाख लोगों द्वारा इस योजना के लाभ लिए जाने को ले आवेदन आएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में इस योजना के आरंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल हों या एपीएल, सभी वर्ग के वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रति वर्ष 1800 करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से प्रति वर्ष 1800 करोड़ रुपये का खर्च करेगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार वर्तमान में 35 से 36 लाख वृद्ध इस श्रेणी के हैं, जिन्हें किसी भी योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने निर्णय लिया कि जो कुछ पाने से वंचित हैं उनको लाभ देंगे। कम से कम पोता-पोती को चॉकलेट लाकर देंगे तो अच्छा लगेगा।

अब मुख्यालय से सीधे निर्णय हो जाएगा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे। इससे फायदा यह होगा कि मुख्यालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा और भुगतान में तेजी आएगी। जरूरत इस बात की है कि लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं।

माता-पिता की उपेक्षा करने वालों की खैर नहीं : इस मौके के पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह व्यवस्था भी कर दी है कि जो लोग माता-पिता की उपेक्षा करेंगे उनकी खैर नहीं। एसडीओ के यहां आवेदन देने से ही कार्रवाई हो जाएगी। अपील के लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं, अब डीएम के स्तर पर 30 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। अब दूसरे राज्य यह पूछ रहे हैं कि यह निर्णय किस तरह से लिया। वे लोग भी ऐसा करना चाह रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद वृद्धजनों से उन्होंने यह अपील किया कि सभी लोगों को इस बारे में बताएं।

यह है योजना : इस योजना से 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के सभी वृद्धजन आच्छादित हैं। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या फिर गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) का कोई चक्कर नहीं। पेंशन के रूप में प्रतिमाह 400 रुपये उन्हें मिलेंगे, जिन्हें किसी तरह का कोई पेंशन नहीं मिल रही। 80 वर्ष की उम्र हो जाने पर पेंशन की राशि प्रति माह 500 रुपये हो जाएगी। आवेदन प्रखंड के आरटीपीएस सेंटर में कर सकते हैं और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन आवेदन के लिए एसएसपी. एमआइए.इन पर जाना है। आवेदन के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। पेंशन पहली अप्रैल 2019 की तिथि से मिलेगी।

बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था को शुरू करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जागरण

सरकारी अस्पताल में खत्म होगी दवा तो मंत्रालय में जल जाएगी बत्ती

नईदुनिया, रायपुर

- छग के अस्पतालों में पारदर्शी तरीके से दवा पहुंचाने के लिए हो रही पहल
- बड़ी कंपनियों की जेनरिक दवाओं की होगी खरीदी

छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दवा खत्म होने के बाद मचने वाली अफरा-तफरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग नई पहल करने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है, जिसमें अस्पतालों में दवा खत्म होने की सूचना सीधे मंत्रालय में बैठे अधिकारियों को मिल जाएगी।

स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक ने बताया कि एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी छोटे-बड़े अस्पतालों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। डैशबोर्ड के माध्यम से दवाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। जहां दवा का स्टाक खत्म होने वाला है, वहां अस्पताल को अलर्ट भी जारी हो जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी का हवाला देकर कालाबाजारी होती है। दवाओं का सही आकलन नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर खरीदी करनी होती है, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। अब अस्पताल में दवाओं का सही आकलन किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर खरीदी करने की जरूरत न पड़े। यही नहीं, आनलाइन सिस्टम होने से अगर किसी अस्पताल में दवा खत्म हो जाती है, तो पड़ोस के अस्पताल में उपलब्धता के आधार पर दवा को भेजा जा सकेगा। ऐसा करने से स्थानीय खरीदी पर रोक लग जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

> प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में दवाओं की कमी के कारण मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। इस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए सभी अस्पतालों को आनलाइन जोड़ा जाएगा। यह सॉफ्टवेयर तीन से चार महीने में तैयार हो जाएगा।
>
> **-टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़**

दवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने की तैयारी : छत्तीसगढ़ में छोटी-छोटी कंपनियों की दवा खरीदने के कारण अंखफोड़वा कांड जैसी घटनाएं होती हैं। अब स्वास्थ्य विभाग बड़ी कंपनियों की जेनरिक दवाओं की खरीदी करेगा। बताया जा रहा है कि बड़ी कंपनियां भी 40 फीसदी जेनरिक दवाओं का निर्माण करती है। ऐसे में मरीजों में भरोसा जगाने और सही इलाज के लिए बड़ी कंपनियों की दवाओं की सरकारी खरीदी होगी। बारिक ने बताया कि दवा खरीदी के लिए टेंडर होता है, जिसमें सभी कंपनियां भाग लेती हैं। सरकार जेनरिक दवाओं की ही खरीदी करती है।

ममता ने कहा, बंगाल में रहना है तो बोलनी होगी बांग्ला

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की सभा से खेला 'बांग्ला कार्ड'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों, खासकर भाजपा पर हमला बोलने के लिए 'बांग्ला कार्ड' खेल कर नया सियासी हथकंडा अपनाया है। बाहरी लोगों के बहाने निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप बंगाल में हैं तो आपको बांग्ला बोलनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करुंगी जो बंगाल में रहते हैं और बाइक पर घूमते हैं। ममता ने फिर से दोहराया कि वह बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। उनका यह इशारा भाजपा समर्थक हिंदी भाषियों पर था।

उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा के बीजपुर में शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा में ममता ने कहा, हमें बांग्ला को आगे लाना होगा। जब मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब जाती हूं तो वहां की भाषा बोलती हूं। अगर आप बंगाल में रहते हैं तो आपको बांग्ला बोलनी ही होगी। यहां बताना आवश्यक है कि यह इलाका बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में है जहां तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हिंदी भाषी अर्जुन सिंह को जीत मिली है। इस इलाके में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत है।

तृणमूल के लिए काम करने वाले बेरोजगारों को नौकरी : सभा में सीएम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छा काम करने वाले बेरोजगार युवकों के लिए वह रोजगार की व्यवस्था करेंगी। मंच से ही उन्होंने पार्टी नेताओं को ऐसे युवाओं के बायोडाटा जमा करने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि नौकरी के प्रलोभन के जरिये ममता पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं ताकि 2021 में चुनाव आसानी से जीती जा सके।

बैलेट पेपर की वापसी के लिए करेंगे आंदोलन : भारतीय चुनाव व्यवस्था में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर की वापसी की मांग को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और तेज कर दिया है। ममता बनर्जी ने बताया कि इस मांग के समर्थन में 21 जुलाई को तृणमूल की शहीद दिवस रैली से नए आंदोलन की शुरुआत होगी।

वैराग्यानंद बाबा ने मांगी जल समाधि की अनुमति

नईदुनिया, भोपाल

- कलेक्टर के इन्कार के बावजूद अड़े वैराग्यानंद, डीआइजी को दिए बाबा की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
- लोस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिग्विजय सिंह के हारने पर समाधि लेने की घोषणा की थी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद लापता हुए वैराग्यानंद गिरी महाराज ने अब कलेक्टर से जलसमाधि लेने की अनुमति मांगी है। बाबा ने कहा कि मैं अपनी बात पर अटल हूं और जो प्रण लिया है, उसे जरूर पूरा करूंगा। वैराग्यानंद ने 16 जून को दोपहर दो बजकर 11 मिनट पर जल समाधि लेने की घोषणा की है। हालांकि, कलेक्टर तण पिथौड़े ने अनुमति देने से इन्कार करते हुए डीआइजी को बाबा की सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाने को कहा है। वैराग्यानंद गिरी के वकील सैयद साजिद अली के मुताबिक, अनुमति नहीं मिलने के बाद भी बाबा तय समय पर जल समाधि लेंगे।

महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद ने दिग्विजय सिंह की जीत के लिए साढ़े पांच क्विंटल लाल मिर्च का यज्ञ किया था और घोषणा की थी कि अगर दिग्विजय नहीं जीते तो वह यज्ञ कुंड में जीवित समाधि ले लेंगे। लोकसभा चुनाव में दिग्विजय भाजपा की साध्वी प्रज्ञा से तीन लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। नतीजों के बाद से ही बाबा गायब हो गए थे। सोशल मीडिया पर उनका एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ। इस टेप में समाधि लेने के सवाल पर बाबा नाराज हो गए थे। रमजान माह में रोजा इफ्तार पार्टी की उनकी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे कामाख्याधाम देहरादून में तपस्यारत हैं। बाबा ने अपने वकील सैय्यद साजिद अली के माध्यम से जल समाधि लेने के लिए भोपाल कलेक्टर से अनुमति मांगी थी। कलेक्टर ने डीआइजी को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लिहाजा उनकी जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इधर, डीआइजी ने उनकी सुरक्षा-व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाबा वैराग्यानंद को कंप्यूटर बाबा का नजदीकी भी माना जाता है। कंप्यूटर बाबा ने भी दिग्विजय सिंह की जीत के लिए हठ योग किया था।

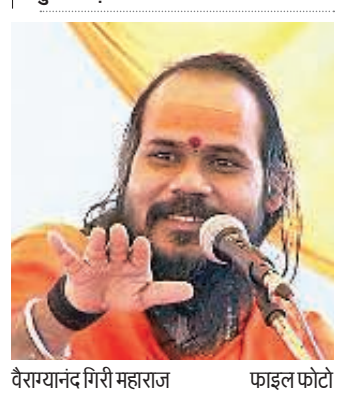
वैराग्यानंद गिरी महाराज फाइल फोटो

> जल समाधि लेने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुमति नहीं दी जा सकती है। पुलिस को उनकी सुरक्षा के लिए लिखा है।
>
> **- तण पिथौड़े, कलेक्टर, भोपाल**

> स्वामी वैराग्यानंद गिरी 16 जून को भोपाल आएंगे। दिग्विजय सिंह को षडयंत्र के तहत हराया गया है। फिर भी वह अपनी बात पर अटल हैं और तय समय पर जल समाधि लेंगे।
>
> **- सैयद साजिद अली, स्वामी वैराग्यानंद गिरी के वकील**

तीन तलाक बिल पर जदयू की राय में तल्खी के साथ नरमी भी

राज्य ब्यूरो, पटना

- मसौदे में सुधार हुआ तो समर्थन के बारे में सोच सकते हैं : त्यागी
- विधि आयोग को लिखा गया नीतीश का पुराना पत्र भी जारी किया

जदयू की तीन तलाक मामले में दी गई राय में तल्खी और नरमी दोनों हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अगर बिल का पुराना मसौदा दोबारा पेश किया गया तो जदयू उसका समर्थन नहीं करेगा। हां, जरूरी संशोधन के साथ यह बिल आता है तो समर्थन के बारे में सोचा जा सकता है। हम सुधार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जटिल मामलों में प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को विश्वास में लेकर ही कोई फैसला लेना हितकर होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने शुक्रवार को कहा कि विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार और उत्तराधिकार जैसे जटिल विषय पर कोई कानून बनाने से पहले सभी पक्षों की राय जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई तरह के धार्मिक समूह हैं जो परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसलिए धार्मिक आधार पर किसी फैसले से पहले इस विषय पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। त्यागी ने कहा कि किसी समूह पर बिना विमर्श के सरकार कोई निर्णय नहीं थोप सकती है।

त्यागी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पत्र भी जारी किया। राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष को संबोधित यह पत्र 24 जनवरी 2017 को लिखा गया है। उस समय आयोग ने सभी दलों से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी थी। कुमार ने पत्र में लिखा था कि समान आचार संहिता को लोगों के कल्याण की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर जल्दबाजी में बिना पर्याप्त सलाह-मशविरा के किसी पर नहीं थोपना चाहिए। हमारी मान्यता है कि लोकतंत्र में विभिन्न समूहों के बीच परस्पर संवाद जरूरी है। जहां तक समान नागरिक संहिता का सवाल है, उसके बारे में कोई भी निर्णय विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ विचार विमर्श के बाद ही करना चाहिए।

ओपी चौटाला के सेल से मिला स्मार्टफोन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सेल में बंद दूसरे कैदी ने सामान अपना बताया, पर जेल प्रशासन को यकीन नहीं
- फोन का पता करने के लिए काल डिटेल की जांच कराएगा जेल प्रशासन

तिहाड़ जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सेल में तलाशी के दौरान स्मार्टफोन, चार्जर व तंबाकू का पैकेट मिला। तलाशी के दौरान चौटाला व इसी सेल में बंद दो अन्य कैदी भी मौजूद थे।

चौटाला व अन्य कैदियों से पूछताछ में रमेश नाम के कैदी ने गलती स्वीकार कर ली, लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता है। जेल प्रशासन पुलिस के सहयोग से बरामद स्मार्टफोन से कॉल डिटेल की पड़ताल करेगी, जिससे पता लगाया जा सके कि क्या इसका इस्तेमाल चौटाला कर रहे थे। जेल प्रशासन हरिनगर थाना पुलिस में मामले की शिकायत देगा।

तिहाड़ जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक राजकुमार ने बताया कि समय-समय पर विभिन्न जेलों में तलाशी अभियान चलाया जाता है। बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे जेलकर्मी जेल संख्या-दो में बंद ओम प्रकाश चौटाला के सेल में पहुंचे। इस सेल में चौटाला के अलावा कैदी रमेश व सुरेंद्र भी हैं। ये दोनों कैदी हत्या के मामले में बंद हैं। जेलकर्मियों ने तलाशी शुरू की तो उन्हें एक चार्जर नजर आया। पूछा तो सब ने चुप्पी साध ली। इसके बाद बिस्तरों को उठाया गया। बिस्तर के नीचे से स्मार्टफोन व तंबाकू का पैकेट मिला। इस बात की सूचना तत्काल आला अधिकारियों को दी गई।

ओम प्रकाश चौटाला जागरण आर्काइव

शुरुआत में तीनों ने इन सामानों को अपना बताने से इन्कार किया, लेकिन जब अधिकारियों की मौजूदगी में इनसे पूछताछ की गई तब कैदी रमेश ने कहा कि स्मार्टफोन, चार्जर व तंबाकू का पैकेट उसका है। अधिकारियों के यह पूछने पर कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल किससे बात करने के लिए किया गया तो उसने चुप्पी साध ली। जेल प्रशासन ने इस बाबत चौटाला व सुरेंद्र से भी पूछताछ की, इस पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली।

बदले जाएंगे सेल के कैदी : जेल प्रशासन का कहना है कि इस घटना के बाद चौटाला के सेल में बंद दोनों कैदियों को अलग सेल में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। जांच में यदि यह पता चलता है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल चौटाला कर रहे थे तब भविष्य में उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जा सकती है। जेल संख्या-दो में ही ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला भी बंद हैं। दोनों शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हैं।

35 साल बाद वकील बने अमर सिंह, पहली याचिका ही खारिज

जागरण संवाददाता, लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सपा सांसद आजम खां के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका जयाप्रदा ने दायर की थी। केस की खास बात यह रही कि जयाप्रदा के वकील के रूप में राज्यसभा सदस्य अमर सिंह पहली बार किसी अदालत में बहस के लिए पेश हुए थे। उनका अधिवक्ता के रूप में 1984 में रजिस्ट्रेशन हुआ था।

बता दें कि जया ने आजम के खिलाफ चुनाव लड़ा था। याचिका को कोर्ट ने पोषणीय न पाते हुए खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि रामपुर संसदीय सीट का क्षेत्राधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट है, न कि लखनऊ, अतः याची जयाप्रदा को यहां याचिका दाखिल करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। याची की ओर से वकील अमर सिंह ने कहा कि आजम मो. जौहर अली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, यह लाभ का पद है। अतः वह एक लाभ के पद रहकर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी पसंद आने लगी महाग्राम विकास योजना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा की महाग्राम विकास योजना भी अब दूसरे राज्यों को ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति और सरल सेवा केंद्रों की तर्ज पर पसंद आने लगी है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार ने राज्य की महाग्राम विकास योजना का विस्तृत प्रारूप मांगा है। पिछले दिनों नई दिल्ली जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में आए विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं विकास, जनस्वास्थ्य और सिंचाई मंत्रियों की बैठक में राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने मनोहर लाल सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से रखा था। महाग्राम विकास योजना के तहत राज्य सरकार ने नाबार्ड से एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लेकर 126 गांवों में सीवर लाइन बिछाने सहित अन्य विकास कार्य करवाने की योजना तैयार की थी। इस योजना पर काम भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि इस योजना के तहत प्रारंभिक बजट का विस्तार भी किया जा सकता है। महाग्राम विकास योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की गई है।

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जागरण आर्काइव

महाग्राम योजना के तहत 16 गांवों में सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा बकाया 110 गांवों में भी यह काम शुरू किया जाएगा। योजना में न सिर्फ सीवर लाइन बिछाने का काम होगा बल्कि विपणन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सुविधाओं के अभाव में गांवों से शहरों की तरफ लगातार बढ़ रहे पलायन को रोका जा सके।

ऐसे पड़ी महाग्राम योजना की नींव : तीन साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पुराने संपर्क के कुछ लोग उनसे मिलने आए और बताया कि उनके गांव में दस हजार से अधिक की आबादी है, इसलिए उनके गांव में सीवर लाइन बिछाई जानी चाहिए। सीएम ने अपने संपर्क के इन लोगों के सुझाव को मानते हुए यह सुविधा उन सभी गांवों को देने की योजना तैयार करवाई, जिनकी आबादी 10 हजार से अ

भारत-पाक संबंधों में सुधार को चीन ने की सहयोग की पेशकश

प्रयास ▸ पाक पीएम के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति ने दिया प्रस्ताव

बिश्केक, प्रेट्र : भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार के लिए चीन ने सहयोग की पेशकश की है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक में यह प्रस्ताव रखा। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में यह कहा गया है।

शी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के एक दिन बाद आई है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन और पनाह देना बंद नहीं करता, उसके साथ बातचीत संभव नहीं है।

शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर हुई इस मुलाकात में शी ने खान से कहा कि चीन 'पाकिस्तान और भारत को अपने संबंधों में सुधार के लिए समर्थन करता है।' जनवरी, 2016 में पठानकोट में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट के हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की है। भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। इस साल फरवरी में पुलवामा में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के हमले और उसके बाद बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायु सेना के हवाई हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। चीन ने दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने की कोशिश की थी।

शिन्हुआ के मुताबिक, इमरान खान के साथ बातचीत में शी ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में भी मदद का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में चीन अपनी क्षमता के मुताबिक मदद देने के लिए तैयार है।

शी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को अपनी सदाबहार साझेदारी को कायम रखना, समेकित और विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान को साझा चिंता के मुद्दों पर गंभीर संवाद करना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयास किया जा सके।

शी ने कहा कि दोनों पक्षों को नए दृष्टिकोण के साथ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के निर्माण को विस्तार और बढ़ावा भी देना चाहिए। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए चीन-पाकिस्तान मुक्त व्यापार समझौता को एक अवसर के रूप में लेने का आह्वान भी किया।

जवाब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते को और मजबूत बनाने और सीपीईसी के निर्माण को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि सीपीईसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका देश प्रभावकारी उपाय करेगा।

बिश्केक में शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

हसन रूहानी और मोदी की नहीं हो पाई मुलाकात

बिश्केक, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच निर्धारित मुलाकात नहीं हो पाई। कार्यक्रम में फेरबदल के कारण एससीओ शिखर वार्ता से इतर होने वाली दोनों नेताओं की बैठक टाल दी गई।

विदेश मंत्रालय द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार 3:35 पर मोदी और रूहानी की मुलाकात निर्धारित थी। एससीओ के नेताओं के लिए भोज का समय बढ़ा दिया गया। इसीलिए दोनों नेता नहीं मिल पाए। एससीओ की दो दिवसीय सालाना शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को किर्गिस्तान की राजधानी पहुंचे थे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोन्बे जिन्बेकोव के साथ शुक्रवार को वार्ता की। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों ने अपने रिश्ते को रणनीतिक संबंध में अपग्रेड किया।

अमेरिका द्वारा भारत और सात अन्य देशों को प्रतिबंध से छह माह की दी गई छूट की अवधि दो मई को समाप्त हो चुकी है। वाशिंगटन ने अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद ईरान के विदेश मंत्री जवाद जारिफ भारत का दौरा कर चुके हैं। जारिफ के साथ मुलाकात में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद भारत कारोबार, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा हितों का ध्यान रखते हुए ईरान से तेल आयात करने के बारे में फैसला लेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अपनी जरूरत का 80 फीसद आयात करता है।

अमेरिका वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा : रूहानी

बिश्केक, एएफपी : खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। एससीओ सम्मेलन में रूहानी ने कहा, 'पिछले दो साल से अमेरिकी सरकार सभी अंतरराष्ट्रीय ढांचों व नियमों का उल्लंघन कर रही है। अमेरिका अपने आर्थिक, वित्तीय व सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करके आक्रामक रुख अपनाए हुए है और क्षेत्र व दुनिया की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन गया है।' रूहानी ने 2015 में किए गए परमाणु समझौते से हटने के लिए भी अमेरिका की आलोचना की। कहा कि अमेरिका अन्य पक्षों एवं देशों पर भी इस बात का दबाव बना रहा है कि वे ईरान के साथ व्यापार अनुबंध सामान्य बनाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को न मानें। उन्होंने समझौते में शामिल अन्य पक्षों का आह्वान किया कि वे जल्द से जल्द समझौता शर्तों का पालन करें ताकि समझौते के तहत ईरान अपने आर्थिक हित विकसित कर सके।

बिश्केक में शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन से पहले ग्रुप फोटो सत्र में बाएं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्टो, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोन्बे जिन्बेकोव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति और उज्बेकिस्तानी राष्ट्रपति। प्रेट्र

एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान के पीएम ने तोड़ा प्रोटोकॉल

बिश्केक, एएनआइ : शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राजनयिक प्रोटोकॉल तोड़कर फिर अपनी फजीहत करवाई है। गुरुवार को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन हॉल में खड़े थे, तब इमरान खान अपनी सीट पर बैठे रहे। इस चूक के लिए सोशल मीडिया में उन्हें खूब ट्रोल किया गया।

इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में इमरान बैठे दिख रहे हैं, जबकि दुनिया के बाकी नेता और वरिष्ठ अधिकारी खड़े हैं। इमरान के नाम का जब एलान हुआ, तो वह थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, लेकिन दूसरे नेताओं के बैठने से पहले ही वह फिर अपनी सीट पर बैठ गए।

▸ **पीएम मोदी समेत दूसरे राष्ट्राध्यक्ष खड़े रहे, जबकि इमरान बैठे रहे**

यूजर बोले, पाक को फिर किया शर्मिंदा : ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में शामिल नहीं होने वाले प्रधानमंत्री इमरान की इस चूक का वीडियो वायरल हो गया है। शिखर सम्मेलन में बैठे रहने को लेकर इमरान खान की सोशल मीडिया में खूब आलोचना की गई। एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने लिखा, 'इमरान खान ने बिश्केक में मुल्क को फिर शर्मिंदा किया है। जब हर कोई खड़ा था, तो वह बैठे रहे। प्रजेंटर ने जब उनका नाम लिया तो खड़े हुए, लेकिन दोबारा बैठ गए। अहंकारी, अशिष्ट या एक मूर्ख?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इमरान खान को आगामी दौरों से पहले राजनयिक शिष्टाचार का अध्ययन करना चाहिए।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वह आए, वह बैठे, वह खड़े हुए और फिर बैठ गए। धिक्कार है कि पीएम इमरान खान को कोई मैनर नहीं है।'

ओआइसी में भी तोड़ा था प्रोटोकॉल : इमरान ने इस महीने के शुरू में सऊदी अरब में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के 14वें शिखर सम्मेलन में भी राजनयिक प्रोटोकॉल की अनदेखी की थी। इस सम्मेलन में सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुलअजीज से मुलाकात के दौरान उन्होंने सलमान के दुभाषिए से कोई बात कही, लेकिन वह जब तक उसका अनुवाद कर सलमान को बताता उससे पहले ही इमरान वहां से चल दिए थे। उस समय इस वाकिये का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के लोगों ने इसके लिए इमरान की आलोचना की थी।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। एपी

मोदी ने किर्गिस्तान के उद्यमियों को दिया भारत में निवेश का न्योता

बिश्केक, एएनआइ/प्रेट्र : एससीओ सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी व किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोन्बे जिन्बेकोव ने शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आपसी हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया। इसमें पीएम मोदी ने किर्गिस्तान के उद्यमियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत बहुत बड़ा बाजार है व अगले पांच साल में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में व्यापार और निवेश के लिए कुशल कामगार, कारोबार की सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस), दोहरे कराधान से बचाव के अलावा बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध है। इसीलिए वह किर्गिस्तान के कारोबारियों को भारतीय उद्यमों में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के करीबी सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं, लेकिन वर्तमान में हमारा व्यापारिक और आर्थिक सहयोग संभावनाओं से कम है। लिहाजा इन प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को मजबूती देना बेहद महत्वपूर्ण है।

मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार और अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए तीन उत्प्रेरकों को भी रेखांकित किया, ये हैं :- अनुकूल माहौल, कनेक्टिविटी और कारोबार से कारोबार। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और मध्य एशिया में कारोबार से कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इसी साल बिश्केक में 'नमस्कार यूरेशिया' नाम से व्यापार मेले का आयोजन भी किया जाएगा। मालूम हो कि भारत-किर्गिस्तान के बीच 2016-17 में 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था।

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोन्बे जिन्बेकोव। एएएफपी

किर्गिस्तान को 20 करोड़ डॉलर का कर्ज, 15 समझौतों पर हस्ताक्षर

बिजनेस फोरम को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोन्बे जिन्बेकोव ने पहले अकेले और फिर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में किर्गिस्तान को 20 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष आपसी भागीदारी को बढ़ाकर रणनीतिक स्तर पर ले जाने को सहमत हुए हैं। दोनों देश विभिन्न विषयों पर साझा विचार रखते हैं और दोहरे कराधान को खत्म करने समेत 15 मुद्दों पर समझौते किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम दोनों देश साथ हैं। विश्व को यह संदेश देना जरूरी है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता।'

धर्म के नाम पर 1500 करोड़ लेकर कंपनी का एमडी फरार

जेएनएन, बेंगलुरु

धर्म के नाम पर लगभग 26 हजार निवेशकों को 1500 करोड़ रुपये का चूना लगाकर आइएमए कंपनी का प्रबंध निदेशक मुहम्मद मंसूर खान दुबई भाग गया है। कंपनी के सात निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) ने शहर के विभिन्न इलाकों से इन्हें गिरफ्तार किया। अदालत ने सभी को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इनका कहना है कि इन्हें इस धोखाधड़ी की जानकारी नहीं थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कंपनी के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज कर लिया है।

गिरफ्तार किए गए निदेशकों के नाम अनवर पाशा, अरशद खान, दादा पीर, नावीद अहमद, नाजीर हुसैन, निजामुद्दीन और वसीम हैं। एसआइटी के प्रमुख बीआर रविकांत गौड़ा ने कहा कि इन आरोपितों से यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी डूब गई और उसका प्रबंध निदेशक मंसूर खान दुबई भाग गया।

एसआइटी ने आइएमए के चार्टर्ड अकाउंटेंट इकबाल खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार निदेशकों ने इस घोटाले में इकबाल खान को भी संलिप्त बताया था। एसआइटी के मुताबिक मंसूर खान ईद की छुट्टी के बाद आठ जून को अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया। ईद की छुट्टी के बहाने से उसने अपना शोरूम बंद कर दिया था।

ईद की छुट्टी के बाद 10 जून को भी जब आइएएम का ज्वेलरी शोरूम नहीं खुला तो इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। अब तक 26 हजार निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम ही हैं। एसआइटी ने आइएमए के मुख्यालय और मुख्य शोरूम में छापा मारकर अहम दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है।

2006 में खोली थी कंपनी : दरअसल, इस धोखाधड़ी की नींव 2006 में ही पड़ गई थी। मैनेजमेंट ग्रेजुएट मंसूर खान ने दुबई से लौटकर आई मोनेटरी एडवाइजरी (आइएमए) नामक कंपनी खोली। उसने एक पोंजी स्कीम चलाई। उसने निवेशकों को बताया था कि उसकी कंपनी बुलियन में निवेश करेगी और निवेशकों को 7-8 प्रतिशत रिटर्न देगी। शुरू में उसने बड़ा रिटर्न दिया भी, जिससे लोगों का उसकी कंपनी में भरोसा बढ़ा। उसने लोगों की धार्मिक भावनाओं को दोहन किया।

धर्म का कार्ड खेला : इस्लाम में ब्याज में मिली रकम को हराम माना जाता है। इस धारणा को तोड़ने के लिए मंसूर खान ने धर्म का कार्ड खेला और निवेशकों को 'बिजनेस पार्टनर' का दर्जा दिया और भरोसा दिलाया कि 50 हजार के निवेश पर उन्हें तिमाही, छमाही या सालाना अवधि के अंतर्गत ब्याज नहीं 'रिटर्न' दिया जाएगा।

▸ **एसआइटी ने कंपनी के सात निदेशकों को किया गिरफ्तार**

▸ **बड़े रिटर्न का वादा कर 26 हजार मुस्लिमों के साथ की धोखाधड़ी**

धार्मिक मुस्लिम का चोला

सार्वजनिक तौर पर मंसूर खान और उसके कर्मचारी हमेशा साधारण कपड़ों में दिखते, लंबी दाढ़ी रखते और ऑफिस में ही नमाज पढ़ते थे। वह नियमित तौर पर मदरसों और मस्जिदों में दान दिया करता था। निवेश करने वाले हर मुस्लिम शख्स को कुरान भेंट की जाती।

मौलवियों और मुस्लिम नेताओं का लिया सहारा

मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए मंसूर खान ने उलेमा, मौलवियों और स्थानीय मुस्लिम नेताओं का सहारा लिया। बेंगलुरु के रहने वाले मुहम्मद नासिर ने कहा कि उनके इलाके की मस्जिद के उलेमा ने उन्हें कंपनी में निवेश करने के लिए जोर दिया। उन्होंने 20 लाख रुपये आइएमए में जमा किए थे। उनकी दो बेटियां हैं, जिनकी शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उन पर है। अब समझ नहीं आ रहा है कि वो यह सब कैसे करेंगे। इसी तरह पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर की रहने वाली उमिया बाई ने 10 लाख रुपये निवेश किए थे।

लापता होने से पहले वीडियो पोस्ट किया

मंसूर खान ने लापता होने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें वह कह रहा है कि नेताओं और अधिकारियों के उत्पीड़न से परेशान होकर वह खुदकशी करने जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने 11 सदस्यीय एसआइटी का गठन किया था। कहा जा रहा है कि शिवाजी नगर के कांग्रेस विधायक रोशन बैग ने भी मंसूर खान से 400 करोड़ रुपये लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। बेग ने इस आरोप को गलत बताया था।

भीम एकादशी अनुष्ठान...

गुजरात के सूरत में पवित्र महोत्सव भीम एकादशी पर भगवान श्रीकृष्ण को मानव निर्मित कुंड में स्नान कराते वैष्णव संत। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने पर भीम को स्वर्ग मिला था। इसलिए इसे भीम एकादशी कहा गया। एएनआइ

कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन

नई दिल्ली, प्रेट्र : कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर अगले महीने दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के द्रास में सेना ने कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई है। इस साल विजय उत्सव तीन दिन 25 से 27 जुलाई तक मनाया जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया, '14 जुलाई को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर विजय ज्योति प्रज्ज्वलित किए जाने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में उत्सवों का आरंभ हो जाएगा। विजय ज्योति 11 कस्बों और शहरों से होती हुई द्रास पहुंचेगी, जहां वह कारगिल युद्ध स्मारक पर प्रज्ज्वलित अनंत ज्योति में विलीन हो जाएगी।' सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि मशाल को लेकर जाने वाली टीमें इस दौरान शैक्षणिक और राष्ट्रवादी वार्ताओं का आयोजन करेंगी और विख्यात शख्सियतों और विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के छात्रों के साथ संवाद करेंगी। इस बार कार्यक्रमों की थीम है, 'रिमेंबर, रिज्वाइस एंड रिन्यू'। लेह में 12 दिनों तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूरे लद्दाख क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। लद्दाख में 'एक दौड़ शहीदों के नाम' का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के दूरदराज इलाकों के लोग भी शामिल होंगे।

आयोजन

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 50वां मुमताज महल फेस्टिवल 16 व 17 जून को, पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगेगी

फिर छिड़ेगी शाहजहां और मुमताज के इश्क की बात

युवराज गुप्ता, बुरहानपुर

मुगल सम्राट शाहजहां एवं मुमताज महल के प्रेम के साक्षी रहे मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में एक बार फिर उनके इश्क की बातें होंगी। दरअसल, 50वां मुमताज महल फेस्टिवल 16 व 17 जून को आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर लगने वाली प्रदर्शनी में ब्रिटिशकाल, फारखी, मराठा, मुगलकाल की नायाब धरोहरों को रखा जाएगा।

इतिहास के जानकार एवं मुमताज महल फेस्टिवल के आयोजक शहजादा मुहम्मद आसिफ खान ने बताया कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल ईरान की रहने वाली थीं और दिल्ली से शाहजहां के साथ बुरहानपुर में आकर बसी थीं। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था। उनके ससुर मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें मुमताज महल का उपनाम दिया था। सात जून 1631 को 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज महल की मौत बुरहानपुर के शाही महल में हुई थी। इसके बाद उनका शव आहूखाना ले जाया गया। आहूखाना के समीप ही पाइन बाग में मुमताज के शव को एक विशेष ताबूत में कब्र में रखा गया। ताबूत को उस समय के विशेष लेप व दवाओं से संरक्षित किया गया था। यहां छह माह कब्र में शव रखा रहा। इसके बाद जब आगरा में ताजमहल का काम पूरा हो गया तब कब्र से शव निकालकर आगरा ले जाया गया और ताजमहल में रखा गया। आज भी इस शाही महल में मुमताज का शाही हमाम, दीवाने खास, दीवाने आम आदि है।

पहले आहूखाना के पाइन बाग में मुमताज के शव को रखा गया था। जब आगरा में ताजमहल का काम पूरा हुआ तो शव यहां रखा गया। फाइल फोटो

1969 में पहली बार 540 रुपये में मनाया गया था फेस्टिवल : मुमताज महल फेस्टिवल मनाने का सिलसिला 1969 से शुरू हुआ। शहजादा आसिफ खान ने अकेले ही इसकी शुरुआत की। 540 रुपये में पहला आयोजन किया गया था। इस बार मुमताज महल की अस्थायी दफन गाह में मुमताज बेगम की 388वीं बरसी पर 17 जून को कुरान ख्वानी (कुरान का पाठ) होगी। इसके साथ ही राजा जयसिंह की छत्री पर देश की शांति और विकास के लिए सर्वधर्म प्रार्थना होगी। इसके बाद रात आठ बजे से फिल्मी अवार्ड का कार्यक्रम होगा। रात 10 बजे ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन होगा।

प्रदर्शनी में यह रहेगा खास : शहर के मुहम्मद नौशाद शेख के पास कई नायाब वस्तुओं का संग्रह है। इनमें से एक चूड़ी वाला बाजा (ग्रामोफोन) है। उनके पास इस विशेष बाजे की 200 रिकॉर्डर (सीडी) का रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि 1968 में यह ग्रामोफोन उनके पिता शेख अहमद मुंबई से खरीदकर लाए थे। इसमें 70 आरपीएम का रिकॉर्डर लगता है। वर्तमान में प्रचलित सीडी का इसे बड़ा रूप माना जा सकता है। इस ग्रामोफोन पर आज भी पुराने गाने सुने जाते हैं। हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य मुहम्मद नौशाद शेख के पास ब्रिटिशकाल, फारखी, मराठा, मुगलकाल की और भी नायाब धरोहरें हैं। इनमें उस जमाने के सुनहरे सिक्के, चांदी व अन्य धातुओं के बर्तन, औजार, लैंप, पानदान आदि शामिल हैं। इन्हें प्रदर्शनी में रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य इतिहासकारों के पास उपलब्ध संग्रह को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

फौजी छावनी था बुरहानपुर

इतिहासकार कमरद्दीन फलक के मुताबिक, मुगलकाल में बुरहानपुर मध्यभारत की दूसरी राजधानी थी। मुगल शासकों ने बुरहानपुर को फौजी छावनी बनाया था इसलिए बादशाह यहां पर आते थे। यहीं से दक्षिण की ओर जाने का मुख्य मार्ग है। इसलिए बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा आर्थिक नजर से यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था।

पूर्व बांग्लादेशी कर्नल और डी कंपनी के साठगांठ की जांच में जुटीं एजेंसियां

नई दिल्ली, आइएएनएस

भारतीय खुफिया एजेंसियां अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम और लंदन में रहने वाले बांग्लादेशी सेना के पूर्व कर्नल के बीच गहरी साठगांठ की जांच कर रही हैं। एजेंसियों को संदेह है कि कथित रूप से गिरोह चलाने में संलिप्त बांग्लादेशी सेना के पूर्व अधिकारी का दाऊद की अंडरवर्ल्ड गतिविधियों के साथ संबंध है। पूर्व सैन्य अधिकारी भारत की पूर्वी सीमा से गतिविधि संचालित कर रहा है।

ब्रिटेन के दैनिक अखबार द संडे टाइम्स में छपी खबर के बाद खुफिया एजेंसियां दाऊद और बांग्लादेशी सेना के पूर्व अधिकारी के बीच साठगांठ की जांच में जुटी हैं। 25 मई को अखबार में छपी विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व कर्नल मुहम्मद शाहिद उद्दीन खान पर बांग्लादेश में आतंकी समूहों को आर्थिक मदद देने, हथियारों के सौदे और मनी लांड्रिंग का आरोप है। अखबार के मुताबिक, पूर्व कर्नल का ब्रिटेन में राजनीतिक संपर्क है और उसने एक सांसद की आर्थिक मदद की है। सूत्रों ने कहा कि 2009 में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व कर्नल लंदन चला गया। उसके बारे में कहा जाता है कि दुबई और ब्रिटेन में उसका कारोबार है।

दाऊद इब्राहिम गैंग के बारे में जारी नई जानकारी के अनुसार, डी कंपनी जाली भारतीय नोट और नशीले पदार्थों की तस्करी में जुटा है। गैरकानूनी गतिविधियां नेपाल और बांग्लादेश से संचालित की जा रही हैं। हाल ही में काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाली भारतीय नोटों की बड़ी खेप जब्त होने के बाद नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी की भूमिका उजागर हुई। भारतीय एजेंसियों की सूचना पर नेपाली पुलिस ने जाली भारतीय नोट रैकेट का भंडाफोड़ किया और दाऊद इब्राहिम के सहयोगी यूनुस अंसारी और तीन पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया।

▸ **ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स में छपी खबर के बाद सतर्क हुई खुफिया एजेंसियां**

12.80 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले में चतरा के प्रधान सहायक कासी प्रसाद गुप्ता और नाजिर इंद्रदेव प्रसाद को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। चतरा के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 15 जून 2019

पुलवामा में लश्कर के दो आतंकी ढेर

मुठभेड़ ▸ सुरक्षाकर्मियों के हाथों मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद

सात घंटे चली मुठभेड़, आतंकी ठिकाना बना मकान भी नष्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में हुए आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकरोधी अभियान में तेजी लाते हुए शुक्रवार को बरोबंडुना (पुलवामा) में एक भीषण मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकियों को मार गिराया।

जानकारी के अनुसार, तड़के सेना की 55 आरआर, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के विशेष अभियान दल (एसओजी) के एक संयुक्त कार्यदल ने बरोबंडुना में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। गांव में दो से तीन आतंकी बीती रात अपने किसी संपर्क सूत्र के पास रहने आए थे। सुरक्षाबलों ने गांव में आने जाने के रास्ते बंद करते हुए जैसे ही तलाशी शुरू की एक मकान में छिपे आतंकियों ने उनकी घेराबंदी तोड़ने के इरादे से फायरिंग कर दी। तड़के करीब साढ़े चार बजे शुरू हुई मुठभेड़ करीब सात घंटे बाद 11.30 बजे दो आतंकियों के मारे जाने के साथ समाप्त हुई। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद मिला है। उनका ठिकाना बना मकान भी मुठभेड़ में नष्ट हो गया।

इसी मकान में छिपे थे लश्कर के आतंकी। मुठभेड़ के बाद घर में लग गई आग। एएनआइ

राज्य पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस दौरान सुरक्षाबलों या आम लोगों को किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। मारे गए आतंकियों की पहचान इरफान अहमद डेगू और तसद्दुक शाह के रूप में हुई है।

मुठभेड़ के बाद भड़की हिंसा : मुठभेड़ में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। बड़ी संख्या में शरारती तत्व भड़काऊ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने वहां तैनात सुरक्षाबलों पर भी पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को बेकाबू होते देख सुरक्षाबलों ने भी लाठियों और आंसूगैस का सहारा लिया। हिंसा में चार लोग जख्मी हो गए। इनमें दो प्रेस छायाकार हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा और बनिहाल-श्रीनगर रेल सेवा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बाद में मारे गए दोनों आतंकियों को दोपहर बाद उनके पैतृक कब्रिस्तान में दफना दिया गया।

कई वारदात में शामिल थे आतंकी : पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मारा गया आतंकी इरफान अहमद डेगू उर्फ अबु जरार जिला पुलवामा में नैना लित्तर का रहने वाला था, जबकि तसद्दुक पांपोर के कदलबल इलाके का रहने वाला था। इरफान वर्ष 2018 से सक्रिय था और इलाहीबाग, पुलवामा में सुरक्षाबलों पर हमले समेत करीब एक दर्जन वारदात में वांछित था। इलाहीबाग हमले में एक जवान शहीद हुआ था। कदलबल का रहने वाला तसद्दुक करीब एक पखवाड़ा पहले पंथाचौक में हुई एक हत्या में शामिल था। इसके अलावा वह पुलिस को सुरक्षाबलों पर हमले की तीन वारदातों में भी वांछित था।

दो दिन पहले मुठभेड़ में शहीद हुए थे पांच जवान : आतंकियों ने दो दिन पहले गत बुधवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में केपी रोड पर भी सुरक्षाबलों पर हमला किया था। इस हमले में पांच सीआरपीएफ कर्मी शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया था। आज जिस गांव में मुठभेड़ हुई वह केपी रोड से करीब 30 किलोमीटर दूर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अवंतीपोर के पास है।

जैश ने अल-उमर-मुजाहिदीन को दी आतंकी हमलों की जिम्मेदारी

नवीन नवाज, जम्मू

▸ पुलवामा हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने के किए आतंकी संगठनों का नापाक गठजोड़

▸ बंदूक और निशाना जैश का होगा और वारदात की जिम्मेदारी लेगा अल-उमर-मुजाहिदीन

अनंतनाग में हुए आतंकी हमले ने साबित कर दिया है कि पुलवामा कांड के बाद जैश-ए-मुहम्मद पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव और घाटी में सक्रिय अधिकांश कमांडरों के मारे जाने से उसने आतंकी संगठन अल-उमर-मुजाहिदीन के साथ नापाक गठजोड़ किया है। यानी बंदूक और निशाना जैश का होगा और जिम्मेदारी लेगा अल-उमर-मुजाहिदीन। जैश सरगना अजहर मसूद के मंसूबों को पूरा करने का जिम्मा उसके करीबी मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम ने संभाल लिया है। हालांकि दोनों का गठजोड़ पुराना है, लेकिन इसे नई धार देते हुए कश्मीर में आतंकी हिंसा को और ज्यादा घातक करने की साजिश रची गई है।

2004 के बाद सिर्फ बयानबाजी तक सिमट कर रह गए अल उमर ने तीन साल पहले 15 अक्तूबर 2016 को पहली बार कश्मीर में किसी आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री सज्जाद गनी लोन के पिता और पीपुल्स कांफ्रेंस के संस्थापक अब्दुल गनी लोन की 21 मई 2002 को श्रीनगर के ईदगाह में हुई हत्या की साजिश भी लटरम ने ही रची थी।

अनंतनाग हमले की जांच में जुटे अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार को हुए हमले की जिम्मेदारी लटरम के संगठन ने बेशक ली है, लेकिन यह जैश की कार्रवाई थी। मारा गया आतंकी विदेशी है और अल-उमर-मुजाहिदीन के इतिहास और वर्तमान को खंगालने पर अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है, जो साबित करता हो कि श्रीनगर शहर में पैदा होने वाले आतंकी संगठन में विदेशी कैडर है। लटरम पहले जेकेएलएफ (जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) के कमांडरों में एक था और वह 1989 तक दो बार आतंकी ट्रेनिंग लेने गुलाम कश्मीर और अफगानिस्तान भी गया था।

1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण कांड में भी उसका नाम आया था। जेकेएलएफ के साथ मतभेदों के बाद उसने अल-उमर-मुजाहिदीन बनाई थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, उसके आतंकी संगठन को कश्मीर के मौजूदा मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के पिता फारूक अहमद का साथ प्राप्त था। ऐसा दावा है कि अल-उमर-मुजाहिदीन नाम मौजूदा मीरवाइज के नाम पर ही रखा गया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अल-उमर-मुजाहिदीन ने इससे पहले भी 26 अप्रैल 2019 को श्रीनगर के में पुलिस चौकी पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में लिप्त आतंकियों को जब पकड़ा गया तो पता चला कि वह जैश के हैं। अल-उमर-मुजाहिदीन ने सिर्फ जिम्मेदारी ली है। दरअसल इसी साल फरवरी में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैश के आत्मघाती हमले और मई माह में मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने बाद जैश अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए अल-उमर-मुजाहिदीन का सहारा ले रहा है।

अल-उमर और जैश का रिश्ता है गहरा

अल-उमर-मुजाहिदीन और जैश का रिश्ता बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए सिर्फ यही जानना काफी होगा कि दिसंबर 1999 मे इंडियन एयलाइंस के विमान और उसमें सवार यात्रियों को कंधार से लाने के लिए जिन तीन आतंकियों को भारत सरकार ने छोड़ा था, उनमें मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम ही थे। लटरम और मौलाना मसूद अजहर की दोस्ती जेल में ही हुई थी। भारतीय जेल से रिहा होने के बाद अजहर मसूद ने जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया था। लटरम ने सरहद पार पहुंचने के बाद अपनी गतिविधियां सीमित कर ली थी, लेकिन कश्मीर में सक्रिय उसके कई आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर उसके कहने पर जैश के साथ जुड़ गए थे।

नासिक में मथूट फाइनेंस के दफ्तर में लूटपाट, एक की हत्या

नासिक, आइएएनएस : शहर के मथूट फाइनेंस के दफ्तर में दिनदहाड़े कम से कम चार डकैतों ने जमकर लूटपाट की और एक ऑडिटर समेत तीन कर्मचारियों पर गोली चलाई। इसमें ऑडिटर की मौत हो गई है। दो अन्य कर्मचारी घायल हैं।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को नासिक के भीड़भाड़ वाले उन्तिवाड़ी इलाके में स्थित कंपनी के दफ्तर में पिस्तौल लेकर घुसे नकाबपोश बदमाशों ने कंपनी के कर्मचारियों व ग्राहकों को डराने के लिए उन पर गोलीबारी कर दी। वह वहां मौजूद ढेर सारा नकद लेकर कुछ ही मिनटों में मोटरसाइकिलों से फरार हो गए।

पुलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल ने बाद में बताया कि ऑडिटर सज्जू सेमुअल को तीन गोलियां लगी हैं। दो अन्य स्टाफर चंद्रशेखर देशपांडे और कैलाश जैन को भी खासी चोटें आई हैं। इन दोनों को बंदूक की बट से मारा गया है। इनको जख्मी हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जाता है कि एक सुरक्षा गार्ड ने अलार्म बजा दिया था जिससे घबराकर उन बदमाशों ने दोबारा फायरिंग की और भाग निकले। पुलिस ने हमलावरों की फुटेज के लिए सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित कर लिए हैं।

लद्दाख : हिमस्खलन में फंसे 81 सैलानियों को सेना ने बचाया

जम्मू, राज्य ब्यूरो

▸ प्रतापपुर और तुरतक में हिमस्खलन होने से फंस गए थे पर्यटक

बर्फीले रेगिस्तान को करीब से देखने के लिए लेह आए 81 पर्यटकों के लिए सेना मसीहा बन गई। खून जमाने वाली ठंड में ये पर्यटक प्रतापपुर व तुरतक में भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। सेना समय पर कार्रवाई न करती तो इन पर्यटकों के लिए ठंड का सामना करना मुश्किल हो जाता। सियाचिन के निकट पहुंचे ये पर्यटक चांगमार व बुकदांग गांवों के पास खराब मौसम के कारण फंस गए। प्रतापपुर से तुरतक के बीच भारी बारिश होने से भूस्खलन हो गया, जिससे उनके वाहन आगे नहीं जा पाए। बुधवार को पहुंचे ये लोग श्योक घाटी की ओर जा रहे थे, जहां कोई आबादी नहीं है। पर्यटकों के दल में महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। दुर्गम हालात में हुए इस भूस्खलन के बारे में जानकारी मिलते ही सेना की सियाचिन ब्रिगेड हरकत में आ गई। सैनिकों के दल को बचाव अभियान चलाने के लिए मौके पर भेज इन पर्यटकों को बचाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इन पर्यटकों को उनके वाहनों से निकाल कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर, कड़ी ठंड से बचाने के लिए गर्म पकड़े, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद उन्हें रात में रुकने के लिए सेना की एक चौकी तक पहुंचा कर उनके खाने-पीने का बंदोबस्त किया गया।

ये पर्यटक पश्चिम बंगाल, गुजरात व अन्य कई राज्यों से यहां घूमने के लिए आए थे। बाद में पर्यटकों को लेह पहुंचाने का भी बंदोबस्त किया गया। पर्यटकों ने उनकी जान बचाने के लिए सेना का आभार जताया और लद्दाख में सेना के योगदान की भी सराहना की।

14 बकरवालों को भी बचाया : बुधवार को लद्दाख की मुश्कोह घाटी में 14 बक्करवाल हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। ये लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए इस क्षेत्र में आए थे। उन्होंने वहां पर अपना अस्थायी डेरा बनाया था। अचानक हिमस्खलन होने से वे उसके नीचे दब गए। बाद में सेना को जब पता चला कि बकरवालों के डेरे हिमस्खलन होने से बर्फ के नीचे दब गए हैं तो अभियान चलाकर सभी को सेना ने सुरक्षित निकाला। इसके बाद उनको मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

आतंकी बनने गुलाम कश्मीर जा रहे चार युवक गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : आतंकी बनने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने गुलाम कश्मीर जा रहे चार स्थानीय युवकों को पुलिस ने गुरुवार देर रात उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे उड़ी सेक्टर के बोनियार गांव में गिरफ्तार कर लिया। इस साल का यह पहला मामला है, जब गुलाम कश्मीर स्थित आतंकी कैंप में ट्रेनिंग के लिए जा रहे चार युवकों को सुरक्षाबलों ने एलओसी के पास पकड़ा हो।

अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए युवकों में से दो दक्षिण कश्मीर और दो उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस को अपने तंत्र से पता चला था कि आतंकी संगठनों द्वारा हाल ही में भर्ती किए गए कुछ युवक हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए गुलाम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। खबर के आधार पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त दस्ते बनाए। इन दस्तों को सभी संभावित रास्तों पर तैनात किया गया, जहां से आतंकी सरहद पार जा सकते थे। गुरुवार आधी रात के करीब बोनियार गांव के ऊपरी हिस्से में जहां से एलओसी करीब तीन से चार किलोमीटर दूर थी, सुरक्षाबलों ने चारों युवकों को पकड़ लिया।

छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में दो इनामी नक्सली मारे गए

नईदुनिया, कांकेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र स्थित मुरनार व मालापारा के बीच जंगल में गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दो नक्सलियों को मार गिराया। इनमें एक पांच लाख का व दूसरा एक लाख का इनामी है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक जी-03 राइफल बरामद की गई है। अमेरिका में बनी इस राइफल का उपयोग पाकिस्तान व बांग्लादेश करते हैं। इससे पहले बस्तर के सुकमा जिले से भी मुठभेड़ के दौरान इस तरह की रायफल बरामद की जा चुकी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जॉइंट ऑपरेशन पेंसी-84 के तहत 12 जून की रात थाना ताड़ोकी, अंतागढ़, रावघाट व फॉल्कन 01 की संयुक्त टीम थाना अंतागढ़ से ग्राम छोटेमुरनार, मालापारा, मानकोट, माहुरपाट की ओर सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। गुरुवार रात करीब नौ बजे छोटेमुरनार व मालापारा के बीच जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब पौन घंटे की फायरिंग के बाद नक्सली जंगल व पहाड़ी का फायदा उठाकर भाग निकले। घटनास्थल की सर्चिंग करने पर दो वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इनकी शिनाख्त आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम खड़का निवासी किसकोड़ो एरिया कमेटी अंतर्गत कोरर-बुधियारमारी एलजीएस कमांडर दीपक (21) उर्फ पीलाराम पुत्र अंजोरीराम कवाची और मानकोट निवासी किसकोड़ो एलजीएस सदस्य रतिराम उपेंडी के रूप में की गई है। दीपक पर पांच लाख व रतिराम पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के मारे जाने अथवा घायल होने की आशंका भी फोर्स ने जताई है। मौके से अमेरिकी राइफल के अलावा दो और राइफल व एक बंदूक बरामद की गई है।

सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति तस्करी के जरिये होती है। आंध्र प्रदेश के नक्सली लीडरों के जरिये बस्तर के नक्सलियों तक ये हथियार पहुंचते हैं। मुठभेड़ के बाद फोर्स का हथियार लूटकर भी नक्सली अपनी ताकत बढ़ाते रहे हैं।

लिट्टे को ट्रिब्यूनल का नोटिस, प्रतिबंध अवधि बढ़ाने पर जवाब मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली हाई कोर्ट के एक ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को नोटिस जारी किया है। इसके जरिये ट्रिब्यूनल ने लिट्टे से उस पर प्रतिबंध की अवधि पांच साल और बढ़ाए जाने को लेकर आपत्ति के बारे में पूछा है।

यह नोटिस गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया। इसे एक अंग्रेजी तथा एक क्षेत्रीय भाषा के अखबार में प्रकाशित भी किया गया है। जस्टिस संगीता धींगरा सहगल की अगुआई वाले ट्रिब्यूनल ने नोटिस के साथ लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी 14 मई 2019 की राजपत्र अधिसूचना को भी संलग्न करने का निर्देश दिया है।

ट्रिब्यूनल का गठन गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत किया गया है। भारत ने वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीलंका के इस आतंकी संगठन के समर्थक व इससे सहानुभूति रखने वाले लोग भारत में भी रहे हैं।

जेईई का काउंसिलिंग शिड्यूल कल होगा जारी

जागरण संवाददाता, रुड़की

ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के चेयरमैन डॉ. एमएल शर्मा ने बताया कि सफल अभ्यर्थियों को आइआइटी में दाखिले के लिए काउंसिलिंग का शेड्यूल दो दिन बाद जारी किया जाएगा। इस साल देशभर की 23 आइआइटी में लगभग 12 हजार सीटों के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।

वेबसाइट डाउन होने से दिक्कत : परीक्षा परिणाम सुबह जारी कर दिया गया था, लेकिन दोपहर तक वेबसाइट डाउन रही। इस कारण छात्र-छात्राओं को परिणाम देखने में काफी दिक्कत आई।

ऑल इंडिया टॉप फाइव रैंकर्स

रैंक	नाम	जोन
1	गुप्ता कार्तिकेय चंद्रेश	बॉम्बे
2	हिमांशु गौरव सिंह	दिल्ली
3	अर्चित बुबना	दिल्ली
4	गिलेला आकाश रेड्डी	हैदराबाद
5	बत्तीपति कार्तिकेया	हैदराबाद

हिमांशु गौरव सिंह।

अर्चित बुबना। (दोनों फाइल)

जोनवार टॉपर्स छात्र

जोन	नाम
बॉम्बे	गुप्ता कार्तिकेय चंद्रेश
दिल्ली	हिमांशु गौरव सिंह
गुवाहाटी	प्रदीप्ता पराग बोरा
कानपुर	ध्रुव अरोड़ा
खड़गपुर	गुड़ीपेटी अनिकेत
हैदराबाद	गिलेला आकाश रेड्डी
रुड़की	जयेश सिंगला

जोनवार टॉपर्स छात्राएं

जोन	नाम
बॉम्बे	शबनम सहाय
दिल्ली	अनन्या गुप्ता
गुवाहाटी	आकृति
कानपुर	वलाया
खड़गपुर	अंजेलीना शकेबा
हैदराबाद	सुरअपानैनी साई
रुड़की	तनु गोयल

अमृतसर से टोरंटो के लिए सीधी उड़ान 27 सितंबर से

जासं, अमृतसर : लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा प्रत्याशी रहे नागरिक विमानन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुनगरी को तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि अमृतसर से टोरंटो के लिए सीधी उड़ान इस वर्ष 27 सितंबर से शुरू होगी।

हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार दोपहर ट्विटर व फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। पुरी ने लिखा- नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर, 2019 से एयर इंडिया की श्री अमृतसर साहिब से दिल्ली होते हुए टोरंटो के लिए सप्ताह में तीन दिन सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ होगा। यह गुरु नगरी के वासियों व उन श्रद्धालुओं की बड़े समय से मांग थी कि जो उत्तर अमेरिकी देशों से श्री हरमंदिर साहिब व दुर्ग्याणा मंदिर मत्था टेकने आते हैं। मुझे खुशी है कि मैं संगत की इस छोटी सी सेवा में अपना योगदान दे पाया। यह गुरु नगरी के विकास की यात्रा का शुभारंभ है।' पुरी अमृतसर से लोकसभा चुनाव हार गए हैं।

श्रद्धालुओं को वीजा नहीं देने पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

जेएनएन, अटारी

▸ श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाने जा रहे थे पाकिस्तान

▸ 87 श्रद्धालुओं को पाबंदी वाला वीजा देने से बढ़ी समस्या

पाकिस्तान स्थित गुरुधामों के दर्शन करने के लिए जाने वाले 87 श्रद्धालुओं को वीजा नहीं देने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और तत्काल बगैर पाबंदियों वाला वीजा जारी करने को कहा है।

भारत की तरफ से 230 श्रद्धालुओं ने आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तान उच्चायोग ने विभिन्न कारणों से सौ श्रद्धालुओं को वीजा नहीं दिया। 87 श्रद्धालुओं को पाबंदियों वाला वीजा दे दिया, जिसमें उन्हें सिर्फ रेल मार्ग से जाने की अनुमति है। पाकिस्तान के बदले रवैये से अटारी सीमा पर पहुंचे 130 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न राज्यों से आए इन श्रद्धालुओं को आखिर में अटारी सीमा से वापस लौटना पड़ा।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन श्रद्धालुओं को वीजा देने से मना कर दिया है, वे जत्था का हिस्सा थे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा धार्मिक भावनाओं और भारतीय श्रद्धालुओं के प्रति दिखाए गए अनादर पर अपनी चिंता जाहिर की है।

जत्थे की अगुआई कर रहे परमजीत सिंह जिजेआनी ने बताया कि श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाने के लिए पाकिस्तानी उच्चायोग ने 130 श्रद्धालुओं को वीजा दिया था। भारत की तरफ से 230 श्रद्धालुओं ने आवेदन किया था, लेकिन सौ श्रद्धालुओं को विभिन्न कारणों से वीजा नहीं दिया गया था। जत्थे में बच्चों सहित 60 से 70 वर्ष के बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये सभी अटारी रेलवे स्टेशन के गेट पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते रहे। बाद में वे निराश होकर लौट आए।

अधिकारियों का कहना है कि पाक से मिला वीजा वाघा बॉर्डर के रास्ते का नहीं है। वहीं, अमृतसर रेलवे स्टेशन के निदेशक अमृत सिंह का कहना था कि अटारी-वाघा के माध्यम से पाक जाने वाले जत्थे को स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए विभागीय सूचना व आदेश नहीं थे। इस कारण जत्थे को रोक दिया गया।

अमरनाथ यात्रा में लंगर सामग्री पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

जासं, जम्मू : एक जुलाई से आरंभ हो रही अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी स्थित पवित्र गुफा तक लंगरों-भंडारों की व्यवस्था करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को राशन पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर में जीएसटी लागू होने के बावजूद प्रवेश द्वार लखनपुर में वस्तुओं पर टोल टैक्स लगता है, लेकिन लंगर-भंडारों का आयोजन करने वाली संस्थाओं को इस टैक्स से मुक्त रखा गया है। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को राशन पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए उन्हें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि उन्हें लंगर-भंडारा आयोजित करने की अनुमति प्राप्त है।

तैयारी

रावघाट परियोजना अंतर्गत 235 किलोमीटर तक बिछेगी रेल लाइन, इसमें पांच किलोमीटर का दायरा धुर नक्सल बेल्ट में, दल्ली राजहरा से रावघाट के बीच 95 किलोमीटर पटरी बिछाने में 631.78 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान

कमांडो की निगहबानी में नक्सलगढ़ में बिछेगी रेल लाइन

श्रीशंकर शुक्ला, रायपुर

देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित बस्तर में परिवहन सुविधाओं के विकास का काम करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यहां नक्सली सड़क और पुल निर्माण का कार्य नहीं होने दे रहे हैं। रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी रावघाट रेल परियोजना भी यहीं प्रस्तावित है। नक्सल हिस्सा की वजह से इस परियोजना का काम अटका पड़ा था, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरा करने के लिए कमर कस ली है। अब स्पेशल कमांडो की निगरानी में यहां रेल लाइन विस्तार का काम चलेगा।

छत्तीसगढ़ में पहली बार आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) के कमांडो बस्तर में रेल लाइन का काम पूरा करने के लिए मोर्चे पर उतरेंगे। रावघाट रेल परियोजना के तहत 235 किलोमीटर में पटरी बिछाने का काम चल रहा है। यह दो हिस्से में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टियर डिवीजन के अंतर्गत बस्तर रेल लाइन प्राइवेट द्वारा जगदलपुर से रावघाट तक 140 किलोमीटर और दल्लीराजहरा से रावघाट तक रेल विकास निगम द्वारा पटरी बिछाने का काम किया जा रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने दल्ली राजहरा से केंवटी तक 43 किलोमीटर तक पटरी बिछाने का काम कर लिया है। रेलवे ने केंवटी तक ट्रेन का परिचालन भी शुरू कर दिया है। आरवीएनएल ने केंवटी के आगे काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों आरपीएफ डीजी जगदलपुर दौरे पर आए थे। डीजी ने नक्सली वारदातों को देखते हुए रेल लाइन पर आरपीएफ की चार कंपनी की तैनाती को हरी झंडी दी।

इस तरह बिछाई जाएगी रेल पटरी। जागरण आर्काइव

> सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी रावघाट परियोजना अंतर्गत पटरी बिछाने का काम चल रहा है। सुरक्षा के लिए पहली बार आरपीएफ कमांडो तैनात किए जाएंगे। कमांडो की चार कंपनियां आ रही हैं, जिनमें तीन कंपनियां ईस्ट कोस्ट के वाल्टियर डिविजन में तथा एक कंपनी रायपुर मंडल अंतर्गत भानुप्रातपुर, केंवटी आदि जगहों पर तैनात की जाएगी।
>
> **-अनुराग मीणा, मंडल सुरक्षा आयुक्त, रायपुर**

किरंदुल, बचेली, दंतेवाड़ा में होगी तैनाती : आरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि ईस्ट कोस्ट रेलवे अंतर्गत वाल्टियर डिवीजन में किरंदुल, दंतेवाड़ा, बचेली, कामालूर आदि नक्सल इलाकों में पटरी बिछाने का काम होगा इसलिए आरपीएफ की तीन कंपनियां तैनात होंगी। एक कंपनी रायपुर मंडल अंतर्गत भानुप्रतापपुर, केंवटी आदि नक्सल इलाकों में तैनात की जाएगी। एक कंपनी में 120 कमांडो होते हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार आठ माह के भीतर तड़ोके और अंतागढ़ तक पटरी बिछाने का लक्ष्य रखा गया है।

कांकेर में जवानों को मिलेगी जंगल वार की ट्रेनिंग : दिल्ली से आने वाली आरपीएफ की कंपनी को कांकेर में जंगल वार की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग करीब 45 दिनों की होगी। इसके बाद कमांडो को नक्सल इलाकों में तैनात किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि सितंबर में कमांडो को मोर्चा लेने के लिए तैनात कर दिया जाएगा।

इतनी लागत से हो रहा काम : योजना के पहले चरण में दल्लीराजहरा से रावघाट के बीच दक्षिण की ओर 95 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा रही है। प्रस्तावित नई रेल लाइन बैलाडीला और रावघाट माइंस को भिलाई से जोड़ेगी। इसके निर्माण में 631.78 करोड़ रपये लागत आने का अनुमान है। इसी तरह रावघाट से जगदलपुर के बीच 140 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसकी लागत 664.31 करोड़ रुपये है।

2006 के मालेगांव विस्फोट के चार आरोपितों को मिली जमानत

मुंबई, प्रेट्र / एएनआइ : वर्ष 2006 में हुए मालेगांव विस्फोट के चार आरोपितों को बांबे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में चारों पर लगाए गए आरोपों को सही मानने का कोई आधार नहीं दिखता। वर्ष 2013 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद चल रहे आरोपितों की जमानत अर्जी विशेष अदालत ने वर्ष 2016 में खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस आइए महंती और एएम बदर की पीठ ने धन सिंह, लोकेश शर्मा, मनोहर नरवारिया और राजेंद्र चौधरी को जमानत दे दी। पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ताओं को 50 हजार रुपये नकद पर जमानत दी जाती है। सुनवाई के दौरान उन्हें हर दिन विशेष अदालत में पेश होना होगा।'

हाई कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि विशेष अदालत को सुरक्षा एजेंसियों (एटीएस और सीबीआइ) द्वारा पूर्व में दाखिल रिपोर्टों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। पीठ ने कहा, एटीएस के आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन लोगों को शुरू में अभियुक्त बनाया गया था, उन्होंने दंगा भड़काने के लिए मालेगांव में कई बैठकें की थीं। महाराष्ट्र एटीएस ने शुरुआती जांच में अल्पसंख्यक समुदाय के नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआइ ने भी उन्हीं के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।

एनआइए ने पलट दी थी एटीएस और सीबीआइ की जांच रिपोर्ट : एटीएस और सीबीआइ की जांच के विपरीत तीसरी एजेंसी एनआइए ने बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों को हमले के लिए दोषी पाया। उसने पूर्व के नौ आरोपितों से केस वापस लेते हुए धन सिंह, लोकेश शर्मा, मनोहर नरवारिया और राजेंद्र चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया। सभी हिंदू संगठन अभिनव भारत से जुड़े थे। विशेष अदालत ने भी वर्ष 2016 में एनआइए के रुख को सहमति दे दी। इन चारों के अलावा एनआइए ने चार अन्य लोगों पर आरोप लगाया है जो फरार हैं। इस विस्फोट में 37 लोग मारे गए थे।

7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है बेंगलुरु के कोडिगेहाली में एक महिला को पोल से बांध कर प्रताड़ित करने पर। महिला पर कर्ज का पैसा नहीं लेने का है आरोप। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जानकारी सामने आई।

एईएस से आठ और बच्चों की मौत, 31 भर्ती

प्रकोप जारी ▶ बिहार में अब तक 85 बच्चों की जा चुकी है जान, अकेले मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में 76 की मौत

एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में कुल 227 बच्चों को कराया जा चुका है भर्ती

जासं, मुजफ्फरपुर

एईएस (एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम) से पीड़ित आठ बच्चों की मौत शुक्रवार को हो गई। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पांच और केजरीवाल अस्पताल में तीन बच्चों की मौत हो गई। दोनों जगहों पर कुल 31 नए बीमार बच्चों को भर्ती किया गया है। इस बीमारी से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में अब तक 76 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे बिहार में 85 बच्चों की जान गई है। मुजफ्फरपुर के दोनों अस्पतालों में अब तक 227 बच्चों को भर्ती कराया गया है।

एक-एक बच्चे की जिंदगी महत्वपूर्ण, बचाने की पूरी कोशिश : स्वास्थ्य मंत्री : स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एक-एक बच्चे की जिंदगी महत्वपूर्ण है। सरकार लगातार इसकी निगरानी कर रही है। बच्चों को बचाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। जून की शुरुआत से पीड़ितों की संख्या बढ़ी है। इसे देखते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। एसकेएमसीएच की दूसरी आइसीयू में भी अस्थाई पीआइसीयू खोली गई है। सदर अस्पताल में दस बेड बढ़ाए गए हैं। केजरीवाल अस्पताल में भी 27 के अलावा अतिरिक्त 15 बेड की व्यवस्था कराई गई है। पीएचसी में भी इलाज की व्यवस्था की गई है। 15 जूनियर रेजीडेंट काम कर रहे हैं। एसकेएमसीएच में छह एंबुलेंस भेजे जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि मामले को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन व राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को भी सारी जानकारी दी गई है। दो दिन पहले केंद्रीय टीम यहां आई थी। उसकी सलाह पर जागरूकता अभियान तेज किया गया है। गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की गई है।

मंत्री ने वायरस के कारण बीमारी होने की बात से फिर इन्कार किया। कहा, कई कारणों से यह बीमारी हो रही। इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल तय है, उसके अनुसार ही बच्चों का इलाज किया जा रहा है। 12 जिले इसकी जद में हैं। इनके डीएम को एडवाइजरी प्रधान सचिव स्तर से जारी की जाएगी। इस वर्ष 22 मई से मरीजों का आना शुरू हुआ। जून के पहले सप्ताह से इसकी संख्या बढ़ गई है। अब तक 57 बच्चों की मौत हुई है।

बच्चों की स्थिति की समीक्षा के बाद एसकेएमसीएच से बाहर निकलने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का जूनियर डॉक्टरों ने घेराव किया। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों से मारपीट को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की।

मुजफ्फरपुर में बीमार बच्चों का हाल जानने पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय। जागरण

सेवा करते-करते आंखों के सामने मर जाते हैं बच्चे, कलेजा फट जाता है...

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

वह बच्चों की मौत को काफी करीब से देखती हैं। मां की चीत्कार के दर्द को महसूस करती हैं। पिता को अंदर ही अंदर टूटते देखती हैं। लगता है कलेजा फट जाएगा। आंसू निकल आते हैं। एसकेएमसीएच में बच्चों के लिए कहर बने एईएस पीड़ितों की सेवा कर रहीं प्रशिक्षु नर्स इस दर्द का बयां कर रही हैं। वह दिन-रात मौत के दर्द को महसूस करती हैं। बीमार बच्चों के पास मां को तड़पते देखती हैं। उसे बचाने के लिए पिता को भागते-दौड़ते देखती हैं। जब से यह बीमारी बच्चों के लिए कहर बनी है, ड्यूटी में तैनात नर्स या बिना वेतन का काम करने वाली प्रशिक्षु नर्स अपनी जिम्मेदारी को इबादत समझ कर कर रही हैं। 12 से 16 घंटे तक ड्यूटी कर रही हैं।

भावुक होकर प्रशिक्षु नर्स करुणम कुमारी कहती हैं कि जिस दिन बच्चों की मौत हो जाती है, खाना नहीं खा पाती हूं। देखभाल के बाद भी उनकी मौत अंदर से तोड़ देता है। मगर, तुरंत दूसरे बच्चों की देखभाल में लग जाती हूं। सबलोग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। रीना कुमारी, ममता कुमारी, दीपा कुमारी, रेखा कुमारी, काजल कुमारी आदि ने भी कहा कि सभी बच्चे बीमारी से ठीक होकर घर चले जाएं, भगवान से यही प्रार्थना है।

एसकेएमसीएच की पीआइसीयू में बच्चों की देखभाल कर रही प्रशिक्षु नर्स। जागरण

साहेब, मेरे बच्चे ने पांच दिन से आंख नहीं खोला... : एसकेएमसीएच की पीआइसीयू-3 में बेड संख्या पांच पर तीन वर्ष का आयुष बेसुध पड़ा है। उसने पांच दिन से आंख नहीं खोली है। उसके माथे को सहला रही मां सुनीता देवी की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। उनकी गोद में करीब एक वर्ष का दूसरा बेटा है। जो बार-बार रोता है। उसे चुप कराती हैं। पिता राकेश कुमार बेटे को एकटक देख रहे हैं। अनजाने से डर ने माता-पिता की भूख-प्यास को खत्म कर दिया है। उन्हें सिर्फ अपने बच्चे की चिंता है। रोते हुए सुनीता देवी कहती हैं कि पांच दिन हो गए साहेब, मेरे बच्चे ने आंख तक नहीं खोली है।

राजनाथ ने वन रैंक वन पेंशन की समीक्षा को कमेटी बनाई

- रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की
- सैन्य अफसरों के साथ पाक व चीन से लगी सीमा के हालात पर चर्चा की

नई दिल्ली, एएनआइ/प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के अगले रिवीजन को लागू करने की प्रक्रिया पर काम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा उन्होंने सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। इस दौरान देश की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की समीक्षा करने के साथ ही पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा के हालात पर भी चर्चा की।

रक्षा मंत्रालय के शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार ओआरओपी की पेंशन रिवीजन को लागू करने के लिए उसकी प्रक्रिया और व्यवस्था पर चर्चा की। इसके अलावा, पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इन मामलों में तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को कमेटी में शामिल किया जाएगा। कमेटी इस पर रिपोर्ट एक महीने में दे देगी।

इसके अलावा, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजनाथ ने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अन्बू और सभी जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ के साथ बैठक की। बैठक में पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को लेकर भी चर्चा हुई।

रक्षा मंत्रालय के जारी बयान के अनुसार बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि वह हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसकी क्षमताएं लगातार बढ़ती रहें। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के संयुक्त कामकाज पर गौर करना हमारा प्रमुख ध्येय है।

सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय तेज गति से सशस्त्र सेनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सभी रैंक के लोगों की प्रेरणा और उनके उच्च नैतिक बल को सुनिश्चित किया जाएगा।

डीआरडीओ के कामकाज की भी हुई समीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस रीसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) के मुख्यालय का दौरा करके सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के संबंध में उसके कामकाज की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय महत्व की फ्लैगशिप परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। रक्षा मंत्री ने रोडमैप ऑफ डीआरडीओ नाम की एक स्मारिका भी जारी की है। इसमें डीआरडीओ के अगले दस साल के लक्ष्यों का ब्योरा दिया गया है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ.जी.सतीश रेड्डी ने सिंह को एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इसमें हाल की उपलब्धियों के साथ ही जारी परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा दिया गया है।

'ऑपरेशन थंडर' में रेल टिकट दलालों पर गिरी गाज

- 141 शहरों से 387 दलाल गिरफ्तार, 33 लाख रुपये के 22 हजार टिकट जब्त
- सवा तीन करोड़ रुपये मूल्य के टिकटों की कालाबाजारी की बात कुबूली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेल सुरक्षा बल ने अवैध तरीकों का इस्तेमाल कर ट्रेन टिकट कंफर्म कराने वाले दलालों के राष्ट्रव्यापी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में गुरुवार को देश के लगभग डेढ़ सौ शहरों में अलग-अलग जगहों पर छापे मार कर पौने तीन सौ दलालों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पचास हजार यात्रियों से संबंधित 32 लाख रुपये से अधिक कीमत के बाइस हजार से ज्यादा टिकट जब्त किए गए। सबसे ज्यादा दलाल कोलकाता और बिलासपुर में पकड़े गए हैं।

ऑपरेशन थंडर : रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में 'ऑपरेशन थंडर' के तहत गोपनीय अभियान में डाले गए इन छापों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से रेल टिकट आरक्षण प्रणाली में दलालों की घुसपैठ की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। कुछ मामलों में कुछ अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए देश भर में इसके विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

करोड़ों के टिकट बेच चुके : इसके तहत गुरुवार (13 जून) को देश भर के 141 नगरों में 276 स्थानों पर छापे मारे गए। इस कार्रवाई में कुल 375 मामलों के तहत 387 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 32.99 लाख रुपये मूल्य के 22,253 टिकट बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इन दलालों ने इससे पहले भी लगभग 3.24 करोड़ रुपये मूल्य के टिकटों का अवैध कारोबार किया था। इन सभी के यूजर आइडी को रद करने के साथ-साथ सभी जब्त टिकटों को भी निरस्त किया जा रहा है। ये टिकट जिन पचास हजार से अधिक यात्रियों के लिए जारी किए गए थे, उन्हें अब वैध तरीके से पुनः टिकट लेने होंगे। सबसे ज्यादा 51 मामले कोलकाता में दर्ज हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बिलासपुर रहा जहां 41 केस दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार गोरखपुर में 32, इलाहाबाद में 25, दिल्ली-एनसीआर में 30 जबकि पटना में 17 मामले दर्ज किए गए हैं।

गर्मियों का फायदा : कुमार के अनुसार स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां तथा शादी-ब्याह का मौसम होने के कारण पिछले लगभग एक महीने से ट्रेनों में आरक्षण को लेकर अत्यधिक मारामारी है। ऐसे में अराजक तत्वों के सक्रिय होने की हमें लगातार सूचनाएं मिल रही थीं, जो टिकट काउंटर एवं ई-टिकटिंग सुविधा का दुरुपयोग करते हुए फर्जीवाड़ा कर ऊंचे दामों पर रेल टिकटों की कालाबाजारी करते हैं और आम जन को टिकटों की उपलब्धता से वंचित करते हैं।

दलालों का तरीका : आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक आरक्षित टिकट हासिल करने के लिए टिकट दलाल विभिन्न तरीकों से आइआरसीटीसी की वेबसाइट को हैक करते हैं। टिकट दलाल कई नकली पर्सनल आइडी बनाकर रखते हैं। सुबह दस बजे आम यात्रियों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा ओपन होती है। जबकि सवा दस बजे से एजेंट की आइडी ओपन होती है। करीब सवा 11 बजे से स्लीपर के रिजर्वेशन टिकट एजेंट बना सकते हैं। पंद्रह मिनट के इस अंतर में ही एजेंट फर्जी पर्सनल आइडी से धड़ाधड़ टिकटों की बुकिंग करते हैं। इसके लिए हाईस्पीड इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। जिस बीच आपका कर्सर घूम रहा होता है, उसी दौरान ये लोग कई टिकट बुक करा चुके होते हैं। इसी वजह से आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है।

हमसफर एक्सप्रेस में छह यात्रियों से डकैती

जासं, मथुरा : उत्तर प्रदेश में कासगंज के पास रामनगर-बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस में गुरुवार देर रात आधा दर्जन बदमाशों ने डकैती डाली। उनसे मोबाइल और अन्य सामान लेकर डकैत आउटर पर उतरकर फरार हो गए। ट्रेन मथुरा पहुंची तो एक पीड़ित ने तहरीर दी। रामनगर-बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस गुरुवार रात करीब दो बजे कासगंज से रवाना हुई थी। ट्रेन के चलते ही आधा दर्जन बदमाशों ने एक बोगी में आधा दर्जन से ज्यादा यात्रियों के मोबाइल और अन्य सामान छीन लिए। मथुरा जंक्शन पर यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 4.15 बजे पहुंची। यहां यात्री सुभाषचंद्र जैसवाल निवासी गांव मल्ला, हल्द्वानी ने जीआरपी में मोबाइल छीनने की तहरीर दी है।

एसएसआइ नरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना कासगंज क्षेत्र की है, इसलिए विवेचना वहीं ट्रांसफर की जाएगी। जीआरपी इंस्पेक्टर पीपी सिंह का कहना है कि अभी तक की पड़ताल में सामने आया है ट्रेन की रफ्तार धीमी होने पर यह घटना घटी।

हड़ताली डॉक्टरों ने ममता के सामने रखीं छह शर्तें

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

हड़ताली डॉक्टरों को चेताने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर डॉक्टरों को मनाना की कोशिश की, मगर वह हड़ताल पर अडिग हैं। उन्होंने हड़ताल से हटने के लिए ममता बनर्जी के सामने माफी मांगने समेत छह शर्तें रखी हैं। इनमें ममता का एनआरएस अस्पताल आकर उनसे मिलना, हमले में जख्मी डॉक्टर परिबाह मुखर्जी को देखने जाना, एसएसकेएम अस्पताल में दिए गए बयान को वापस लेना एवं अस्पतालों में डाक्टरों की पर्याप्त सुरक्षा का लिखित रूप से आश्वासन देना प्रमुख हैं। इसबीच राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए शुक्रवार देर शाम राजभवन बुलाया।

डॉक्टरों के समर्थन में आया बुद्धिजीवी वर्ग : जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में बुद्धिजीवी वर्ग भी आगे आया है। बुद्धिजीवियों ने आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को कोलकाता में जुलूस निकाला। इस दौरान चर्चित फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन, अभिनेता कौशिक सेन, संगीतकार देवज्योति मिश्रा समेत समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों ने एनआरएस अस्पताल जाकर आंदोलनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की। अपर्णा सेन ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बिना किसी शर्त के डॉक्टरों से बातचीत करनी चाहिए।

दूसरी ओर, ममता ने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर विरोधी दल भाजपा और माकपा पर फिर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों दल डॉक्टरों को भड़का कर मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने एक बार फिर आंदोलनकारी डॉक्टरों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। पश्चिम बंगाल प्रशासन की ओर से संकेत मिले हैं कि सरकारी डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सामूहिक रूप से इस्तीफा देना वैध नहीं है। किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति के समय व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाता है, इसलिए उनका व्यक्तिगत इस्तीफा ही वैध होगा।

कोलकाता में चिकित्सकों से हुई मारपीट की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में डॉक्टरों ने विरोध का अनूठा ढंग अपनाया और हेलमेट पहनकर चिकित्सीय कार्य को अंजाम दिया। संजय यादव

एयरक्राफ्ट एएन-32 का कॉकपिट वायस रिकॉर्डर मिला

ईटानगर, प्रेट्र : बचाव दल को दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट एएन-32 का कॉकपिट वायस रिकॉर्डर (सीवीआर) तथा फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर (एफडीआर) मिल गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल रूसी मूल का यह एयरक्राफ्ट कुछ दिन पहले लापता हो गया था। काफी प्रयास के बाद उसके मलबे को खोजा जा सका। बचाव दल को शुक्रवार को दुर्घटनास्थल से एयरक्राफ्ट के सीवीआर और एफडीआर मिल गए।

शिलांग स्थित भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता विंग कमांडर रत्नाकर सिंह ने बताया कि खराब मौसम और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बचाव दल के लोग वायुसेना जांबाजों के शवों को खोजने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। गुरुवार को बचाव दल की मदद करने को तीन और स्थानीय पर्वतारोही उनके साथ जुड़ गए। वायुसेना ने गुरुवार को कहा था कि इस एयरक्राफ्ट में सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई है। तीन जून को यह एयरक्राफ्ट असम के जोरहाट से उड़ा था और उसके कुछ देर बाद ही उसका संपर्क टूट गया था।

चक्रवात वायु का खतरा टलने के बाद गुजरात में लोगों का घर लौटना शुरू

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो

गुजरात पर छाया चक्रवात का खतरा पूरी तरह टल गया है, राहत शिविरों में रह रहे करीब पौने तीन लाख लोगों को अब वापस घर भेजा जा रहा है। लेकिन प्रभावित 10 क्षेत्रों में अभी एनडीआरएफ की टीम को तैनात रखा गया है।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार सुबह गांधीनगर में राज्य आपदा केंद्र में हालात की समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, मुख्य सचिव डॉ. जेएन सिंह सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि गुजरात अब पूरी तरह सुरक्षित है। चक्रवात अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन अब राहत स्थलों पर रखे गए लोगों को घर भेजने लगा है।

उन्होंने कहा कि सरकार राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को अगले तीन दिनों तक दैनिक खर्च के लिए लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके तहत वयस्कों को प्रतिदिन के हिसाब से 60 रुपये तथा किशोरों को 45 रुपये की नकद सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हालात पर नजर रखने के लिए सौराष्ट्र और कच्छ के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए सभी मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'स्कूल और कॉलेज कल से अपने नियत समय पर शुरू हो जाएंगे। राहत और बचाव अभियान की निगरानी के लिए तटीय जिलों में नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को भी वापस आने का निर्देश दे दिया गया है। उन इलाकों में आज से सड़कों पर बस सेवा शुरू हो गई है।'

'वायु' के चलते महाराष्ट्र में देर से आ सकता है मानसून

मुंबई, एएनआइ : मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि चक्रवाती तूफान वायु के चलते महाराष्ट्र में मानसून के आने में देरी हो सकती है। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (आरडब्ल्यूएफसी) के निदेशक विश्वंभर ने कहा कि दक्षिणी-पश्चिम मानसून पर चक्रवात का बहुत गहरा असर पड़ा है। अगर आने वाले दिनों में इसका असर खत्म नहीं होता है तो महाराष्ट्र में मानसून कम से कम एक हफ्ते की देरी से आएगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि चक्रवात के चलते तटवर्ती आंध्र प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। इसके अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैयकल में धूलभरी आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है।

डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : हमले के विरोध में देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। याचिका में देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। साथ ही कोलकाता मेडिकल कालेज में डॉक्टर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दाखिल की है। याचिका में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुरक्षा कर्मी तैनात करने की मांग के अलावा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश और नियम तय किए जाने की भी मांग की गई है।

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टरों को दिया सुरक्षा का भरोसा

- ममता बनर्जी को डॉक्टरों से सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत की दी नसीहत
- अस्पतालों में सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय से करेंगे बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया, लेकिन साथ ही उन्हें हड़ताल में संयम बरतने की भी अपील की। डॉक्टरों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ मुलाकात के दौरान हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमले की निंदा की।

डॉक्टरों के साथ मुलाकात के बाद हर्षवर्धन ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आंदोलन को सद्भावपूर्ण माहौल में समाप्त करने और डॉक्टरों को सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित कराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी से बातचीत करने का भरोसा दिया। हर्षवर्द्धन ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल से देश भर में मरीजों को कठिनाई उठानी पड़ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अस्पतालों में सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए वह गृह मंत्रालय से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से भी विचार-विमर्श कर ऐसी व्यवस्था विकसित करने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को टाला जा सके।

पहल

शिक्षाविद विजय हीर ने गलतियों को इंगित करते हुए एनसीईआरटी को भेजी थी रिपोर्ट, अब पुस्तक निर्माण समिति व संशोधन समिति कर रही है रिपोर्ट का अध्ययन

एनसीईआरटी की किताबों से हटेंगी गलतियां

जागरण संवाददाता, हमीरपुर

देश में पढ़ाई जा रही एनसीईआरटी की किताबों में कई वर्षों से जारी गलतियों में अब सुधार होगा। शिक्षाविद विजय हीर की रिपोर्ट को एनसीईआरटी दिल्ली ने स्वीकार करते हुए कई संशोधनों के लिए हामी भरी है और कुछ संशोधन करने के लिए पुस्तक निर्माण समिति व संशोधन समिति को हीर की रिपोर्ट देने का जिक्र अपने पत्र में किया है। सामाजिक शिक्षा विभागाध्यक्ष प्रो. गौरी श्रीवास्तव ने हीर को भेजे पत्र में इसकी पुष्टि की है।

देश के करोड़ों विद्यार्थी इस सत्र में कक्षा छह के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक के पेज 21, 22 व सातवीं कक्षा की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक सहित दसवीं की किताबों में अनुसूचित जाति के लिए अब भी दलित शब्द ही प्रयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट सहित भारत सरकार के सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय ने सभी विभागों को दलित शब्द भविष्य में प्रयोग न करने के आदेश गत वर्ष दिए थे और इसके लिए अनुसूचित जाति शब्द को ही धारा 341 के अंतर्गत मान्य किया गया था, लेकिन एनसीईआरटी ने किताबों से इसे आज तक नहीं हटाया।

विजय हीर फाइल

मैं इससे पूर्व भी तीन हजार से अधिक संशोधन विभिन्न पुस्तकों में सफलतापूर्वक करा चुका हूं। किताबों को सही तथ्यों से लैस करने की मुहिम अपने दम पर वर्ष 2002 से चला रहा हूं। इन संशोधनों में से अधिकांश स्वीकृत होने की आशा है, जिससे अगले सत्र में विद्यार्थी बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
-विजय हीर, शिक्षाविद

इन त्रुटियों को किया उजागर : इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का द्वितीय वृतांत वर्ष 1358 में लिखित इंगित किया है, मगर वर्ष 1356 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पृथ्वीराज तृतीय के काल को अपनी ही किताबों में कहीं 1168-1192 तो कहीं सन 1175-1192 दर्शाया है। जमाली कमाली मस्जिद वर्ष 1520 में निर्मित बताई है जबकि मुख्य स्रोत इसे वर्ष 1528-29 में बनाया हुआ दर्शाते हैं। मानचित्रों में तेलंगाना का नाम तेलंगाणा लिखा है। दसवीं की आपदा प्रबंधन पुस्तक में कुंभकोणम कांड में मृतकों की संख्या 94 की बजाय 93, पेज 33 पर 25 हजार की जगह 30 हजार मृत्यु होने का डाटा भी हीर ने आधिकारिक स्रोतों से जांचने के लिए कहा है। सातवीं के इतिहास में पेज 69 पर ग्रीक भविष्यवक्ता व संगीतज्ञ को ग्रीक भगवान लिख दिया है व इसी किताब में पेज 28 पर कोस्टारिका को उत्तरी अमेरिका की बजाय दक्षिणी अमेरिका में सबसे स्वस्थ राष्ट्र बताया है। दसवीं की विज्ञान की पुस्तक के पेज 88 पर हाइड्रोजन अणु की परिधि 53 की जगह 37 पिकोमीटर बताई गई है और नौवीं के अंग्रेजी विषय की किताब के पेज 54 पर कनाडा की लेखिका जेन गोडिसो को महिला की अपेक्षा पुरुष इंगित करते हुए पहला प्रश्न पूछा गया है।

कोलकाता में डॉक्टरों से मारपीट के आरोपित बोले-मामला इतना बिगड़ जाएगा, पता न था

- एनआरएस अस्पताल में इलाज के दौरान मोहम्मद शाहिद की मौत के बाद से शुरू हुआ है बवाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कोलकाता के नील रतन सरकार (एनआरएस) अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद देशभर में बवाल मचा हुआ है। जिस मोहम्मद शाहिद की मौत के बाद यह बवाल शुरू हुआ, उसके परिजनों को उम्मीद भी नहीं थी कि मामला इस कदर बिगड़ जाएगा। जिन पर डॉक्टरों से मारपीट का आरोप है, वह भी मानते हैं कि उनसे गलती हुई है। हालांकि, अब वह चाहते हैं कि हड़ताल से किसी और की जान नहीं जानी चाहिए।

नील रतन सरकार अस्पताल से मात्र दो किलोमीटर दूर टेंगरा के बीबी बागान लेन स्थित जामा मस्जिद के पास शाहिद अपने दो बेटों व एक बहू के साथ रहते थे। पिछले सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। मौत के बाद परिजनों ने वहां कार्यरत डॉक्टरों के साथ हाथापाई की। इसमें एक जूनियर डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके बाद राज्य के साथ देशभर में डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई।

शाहिद के छोटे बेटे मोहम्मद साबीर ने संवाददाताओं से बातचीत में स्पष्ट कहा-माना सारी गलती हमारी है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी मामला इतनी दूर चला जाएगा। उसके सुर में सुर मिलाते हुए स्थानीय नागरिकों ने भी कहा कि जो होना था हो गया, अब इसकी वजह से अन्य रोगियों की मौत नहीं होनी चाहिए। बड़ा बेटा मोहम्मद इसराइल जामा मस्जिद में इमाम है। इलाके के लोग भी डरे हुए हैं। स्थानीय एक नागरिक ने कहा, अस्पतालों में जो हो रहा है, उससे बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ बड़ा हादसा हो गया तो शायद हम यहां रह नहीं पाएंगे।

बातचीत के दौरान सबीर ने अपने पिता के इलाज में भयानक लापरवाही का भी आरोप लगाया। उसने यहां तक कहा कि डॉक्टरों ने उसके पिता की लाश को घंटों रोके रखा। यही नहीं देह छोड़ने के एवज में उनके सामने माफी मांगने की शर्त रखी गई। स्थानीय थाने की पुलिस भी डॉक्टरों को समझाने पहुंची, लेकिन वे नहीं माने। सबीर का दावा है कि उसके बाद ही उसके परिजनों को गुस्सा आ गया, जिसमें उन्होंने पत्थरबाजी की।

राज्यपाल बोले, फोन नहीं उठा रही हैं ममता

जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने ममता बनर्जी को बुलावा भी भेजा है।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 15 जून 2019

दैनिक जागरण

कमजोर लोग किस्मत में यकीन करते हैं

पाकिस्तान को खरी-खरी

शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना यह कहकर उसे कठघरे में ही खड़ा किया कि आतंकवाद को समर्थन और संरक्षण देने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। उन्होंने इसी मंच से आतंकवाद से मुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी देशों से एकजुट होने की भी अपील की। पता नहीं उनकी इस अपील का कितना असर पड़ेगा, लेकिन यह स्पष्ट होना अच्छा है कि भारतीय नेतृत्व पाकिस्तान से संपर्क-संवाद कायम करने का इच्छुक नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी यह अनिच्छा चीनी राष्ट्रपति के समक्ष भी व्यक्त की, जो यह चाह रहे थे कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए। हालांकि इस संगठन के घोषणा पत्र में सभी तरह के आतंकवाद और खासकर सीमापार आतंकवाद से भी लड़ने की जरूरत जताई गई, लेकिन यह कहना कठिन है कि चीनी नेतृत्व पाकिस्तान को इसके लिए राजी करना पसंद करेगा कि वह आतंकी संगठनों को पालने-पोसने से बाज आए। आज यदि पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाने में कोई बड़ी बाधा है तो वह चीन का रवैया ही है। यह अच्छा है कि चीन के इस रवैये के बावजूद भारत पाकिस्तान को अलग-थलग करने के अपने अभियान को सफलता से आगे बढ़ाने में सक्षम है। इस अभियान को एक उल्लेखनीय सफलता तब मिली थी जब पाकिस्तान में पल रहे आतंकी सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी लगी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने शपथ ग्रहण समारोह में इमरान खान को निमंत्रित नहीं किया तब दुनिया को यही संदेश दिया कि भारत पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं।

भले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान एक अर्से से दोनों देशों के बीच शांति-सहयोग और बातचीत की महत्ता का बखान करने में लगे हुए हों, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है जो भारत के लिए खतरा बने हुए हैं और जो कश्मीर में आतंकवाद भड़का रहे हैं। बीते दिनों अनंतनाग में हुआ आतंकी हमला यही बता रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान इस मुगालते से भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं कि कश्मीर में हस्तक्षेप करना उसका कथित नैतिक अधिकार है। वह जब तक इस मुगालते से बाहर नहीं निकलता तब तक उससे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान से बातचीत करने में यह खतरा भी है कि वह फिर से धोखा दे सकता है। वह बातचीत के बहाने धोखा देने की अपनी पुरानी फितरत से अभी भी बुरी तरह ग्रस्त है। ऐसे में उसे बार-बार यह बताने की जरूरत है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उस पर भरोसा किया जा सके। इमरान खान कहें कुछ भी, वह अपनी सेना की कठपुतली ही हैं। हाल के समय में पाकिस्तान ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश खूब की है कि वह आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है, लेकिन एफएटीएफ की मानें तो वह खानापूरी ही कर रहा है। इन स्थितियों में भारत को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि पाकिस्तान को एफएटीएफ से कोई राहत न मिलने पाए।

2021 की चिंता

लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली बड़ी कामयाबी से तृणमूल प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव की चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद से एक बार फिर उन्होंने पार्टी नेताओं को भाजपा के खिलाफ सड़क पर ही नहीं, बल्कि घर-घर जाकर संपर्क अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। लोकसभा में हुई हार की समीक्षा के लिए ममता ने पार्टी के नव निर्वाचित सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की नवान्न सभागार में बैठक बुलाई थी। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में ममता ने बंगाल में भाजपा के उभार को रोकने के लिए कई आंदोलनों की रूप रेखा तैयार की। ममता भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे का जवाब बांग्ला सांस्कृतिक पहचान को उभार कर देने की योजना बनाई है। चुनाव में हुई चूक पर विस्तार से चर्चा करते हुए पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का निर्देश दिया। ममता ने कहा है कि उनकी पार्टी घर-घर जाकर लोगों से बात करेगी और सरकार के कामों को बताएगी। भाजपा बंगाल के बारे में लगातार झूठी खबरें फैला रही है, हम इसके खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए डोर-टू-डोर कैंपेन चलाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार पंचायत चुनाव से लेकर आम चुनाव तक, जहां भी भाजपा विजयी हुई है, वहां माकपा एवं उनके सहयोगी दलों का सफाया हो गया है। ऐसे में तृणमूल को कमजोर कहना गलत है। हम आज भी विधानसभा में पूर्ण बहुमत में हैं। अब भाजपा हिंसक राजनीति के सहारे और लोगों को बरगला कर राज्य को गुजरात बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान पर गर्व है और हमारी पार्टी पूरे राज्य में सांस्कृतिक अभियान चलाएगी। इसके लिए हमने जय हिंद वाहिनी का गठन किया है। परंतु लोगों में तृणमूल के प्रति जिन कारणों से गुस्सा बढ़ रहा है वे हैं सिंडिकेट और अवैध वसूली तथा बढ़ती हिंसा। इसे लेकर ममता को आवश्यक कदम उठाने होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति नहीं बदलेगी।

दक्षेस से बेहतर है बिम्सटेक

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

आशंकाओं से भरे दक्षेस के स्थान पर पीएम मोदी का बिम्सटेक देशों पर दांव लगाना भारत के लिए कई मोर्चों पर फायदेमंद हो सकता है

अवधेश राजपूत

यह अच्छा हुआ कि शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह संदेश देने में संकोच नहीं किया कि आतंकवाद का साथ छोड़े बगैर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह वही मोदी हैं जिन्होंने पांच साल पहले बतौर प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। उनमें पाकिस्तान भी शामिल था, मगर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने बंगाल की खाड़ी के लिए बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्सटेक के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मॉरीशस के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए, क्योंकि मोदी पाकिस्तान को इससे दूर रखना चाहते थे। इसलिए इस्लामाबाद को सीधे तौर पर खारिज करने के बजाय मोदी ने कूटनीतिक दांव खेलकर बिम्सटेक के नेताओं को बुलाया। दक्षेस में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। वहीं बिम्सटेक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव को छोड़कर दक्षेस के सभी सदस्य देश हैं। उनके स्थान पर इसमें म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ा गया है।

1985 में बांग्लादेश की पहल पर सात देशों ने मिलकर दक्षेस की स्थापना की थी। 2007 में अफगानिस्तान को आठवें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दक्षेस के लक्ष्य स्पष्ट थे। इसका मकसद दक्षिण एशियाई लोगों का कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार करना था। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को तेजी देने के साथ ही सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना भी इसके एजेंडे में था। कुल मिलाकर इस संगठन का मकसद दक्षिण एशियाई देशों में परस्पर विश्वास का भाव बढ़ाकर सर्वांगीण विकास में जुटना था, मगर अपने 34 वर्षों के उथल-पुथल भरे इतिहास में दक्षेस अपने इन प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा। कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों और प्रोफेसरों के लिए रोजगार का अवसर बनाने के सिवाय दक्षेस जुबानी जमाखर्च के अड्डे से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। ऐसा इसलिए, क्योंकि दक्षेस के दो सबसे बड़े सदस्य देश भारत और पाकिस्तान में हमेशा तनातनी रही। मोदी सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में दक्षेस की एक बैठक तक नहीं हुई, क्योंकि मोदी ने तब तक पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया जब तक वह अपनी धरती पर चलने वाले आतंकी संगठनों पर कार्रवाई नहीं करता। इस तरह दक्षेस ने अपनी प्रासंगिकता खो दी।

मोदी ने अपना ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व पर केंद्रित किया है जिसमें आसियान देश शामिल हैं। पाकिस्तान के अड़ियल रवैये ने पश्चिम एशिया और चारों ओर जमीन से घिरे मध्य एशियाई देशों और यहां तक कि अफगानिस्तान से भारत के सड़क संपर्क में अवरोध पैदा कर दिए हैं। इसका समाधान भारत को ईरान के साथ मिलकर निकालना पड़ा। उसने चाहबार में एक अत्याधुनिक बंदरगाह विकसित किया। उसे रेल और सड़क के माध्यम से मध्य एशिया तक जोड़ा गया है। इसे इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का नाम दिया गया है।

यह साफ है कि दूसरे कार्यकाल में मोदी ने 'एक्ट ईस्ट' नीति को अपनी प्राथमिकता में रखा है। बिम्सटेक देशों की 160 करोड़ की आबादी दुनिया की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। इनका कुल जीडीपी 2.5 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर की है। किर्गिस्तान फिलहाल शंघाई सहयोग संघठन का अध्यक्ष देश है जो बिश्केक में इसकी मेजबानी कर रहा है। बिश्केक में भी मोदी ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रहने के संकेत दिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को यह संदेश देने में लगे हुए हैं कि भारत की 'पड़ोसी प्रथम' की नीति में इस्लामाबाद कहीं नहीं है। बिम्सटेक देशों में भारत ने अभी तक अपनी सॉफ्ट पावर ही इस्तेमाल की है। वहीं चीन ने अपनी वित्तीय ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन देशों में बुनियादी ढांचे और तकनीकी नेटवर्क विकसित किया है। मगर चीनी अर्थव्यवस्था में सुस्ती और अमेरिका के साथ उसके व्यापार युद्ध ने भारत को एक बढ़िया अवसर प्रदान किया है कि वह अपनी खोई जमीन हासिल करे। अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने बिम्सटेक देशों को चीन के जाल में न फंसने से बचाने के लिए तमाम प्रयास किए। ऐसे में मोदी के शपथ ग्रहण में इन देशों के नेताओं को मिले न्योते के खास मायने हैं। 2015-16 में भारत-नेपाल सीमा पर की गई नाकेबंदी ने नेपाली राष्ट्रवादियों का मिजाज बिगाड़ दिया था। वे लंबे अर्से से चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की हिमायत करते आए हैं। मोदी ने सांस्कृतिक समीपता के माध्यम से नेपाल को साधा।

चूंकि कोलकाता के रूप में भारत नेपाल को सबसे करीबी बंदरगाह मुहैया कराता है तो इससे उसे प्राकृतिक मोर्चे पर बढ़त हासिल होती है, क्योंकि चीन का सबसे नजदीकी बंदरगाह नेपाल से 3,000 किलोमीटर दूर है। इस मामले में चीन की काट जरूरी थी, क्योंकि नेपाल और चीन के बीच एक रेल लाइन के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वहीं चीन-क्विंगल-तिब्बत रेलमार्ग के जरिये हजारों चीनी पर्यटक नेपाल जा रहे हैं। बांग्लादेश भारत का निकट सहयोगी रहा है, लेकिन हाल में चीन के साथ उसकी नजदीकी बढ़ी है। हालांकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में उसने चीनी निवेश के लिए लाल कालीन जरूर बिछाई, लेकिन भारत की संवेदनाओं से ढाका भलीभांति परिचित है। वर्ष 2016 में बांग्लादेश चीन द्वारा बंदरगाह विकसित करने के प्रस्ताव को भारत की असहजता के बाद खारिज कर चुका है। वहीं श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में फंसने के कारण हंबनटोटा बंदरगाह नहीं बचा पाया। हालांकि हालिया आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका की भारत से नजदीकी बढ़ी है। एलटीटीई और भारतीय शांति सेना को लेकर कुछ ऐतिहासिक अनबन ने दोनों देशों के रिश्तों को जटिल बना दिया था, लेकिन श्रीलंका को लुभाने के लिए भारत पुरजोर प्रयासों में जुटा है जिसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं।

म्यांमार और थाईलैंड भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम एशिया से होने वाला चीन का अधिकांश तेल आयात मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। चीन इस मार्ग का विकल्प तैयार करना चाहता है। भारत ने अपनी अंडमान एवं निकोबार कमान (एएनसी) को इसके मुहाने पर तैनात कर रखा है। ऐसे में चीन को आशंका है कि भारत के साथ तनाव बढ़ने पर एएनसी इस मार्ग पर उसकी राह रोक सकती है। एएनसी की काट तलाशने के लिए बीजिंग ने बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के बंदरगाह क्याउफाउ में चीन-म्यांमार तेल एवं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को युनान प्रांत में कनमिंग से जोड़ा है। भारत थाईलैंड को अपने पाले में लाने की कोशिश करता रहा है। 2018 में उसे इसका फल भी मिल गया जब थाई प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन की प्रस्तावित नहर उनकी प्राथमिकता नहीं। बिम्सटेक देशों में भूटान ही भारत का इकलौता और घोषित मित्र है। वह भारत के भौगोलिक दायरे के साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी करीब है। चीन भले ही बिम्सटेक का सदस्य न हो, लेकिन इस क्षेत्र में सक्रिय जरूर है। नई मोदी सरकार अपने पड़ोस में चुनौती को समझते हुए उसे सुलझाने के प्रति गंभीर है।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

कलासाधक से बढ़कर थे कारनाड

गोपालकृष्ण गांधी

कारनाड ने न सिर्फ भाषाओं को आपस में जोड़ा, बल्कि पीढ़ियों को भी जोड़ने का काम किया

मशहूर कन्नड़ लेखक, रंगकर्मी और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से नवाजे गए गिरीश कारनाड अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका अपनी मूल भाषा यानी कन्नड़ और उसके साहित्य से गहरा जुड़ाव रहा। वह सोचते थे तो कन्नड़ में और लिखते भी थे कन्नड़ में। हम कह सकते हैं कि वह कन्नड़ के रवींद्रनाथ टैगोर थे। उनकी इसी खासियत के चलते मैं पिछले साल उनके पास एक मशविरे के लिए गया था। बात कुछ ऐसी है कि हम गांधीजी के हरिजन पत्रिका में 1928 में ईश्वर के बारे में लिखे आलेख के बारे में तो जानते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है, लेकिन उस आलेख में उन्होंने एक और बात लिखी थी, जो कम ही लोगों को ज्ञात है। गांधीजी ने उस आलेख में मैसूर के कुछ गरीब किसानों के साथ अपनी बातचीत का उल्लेख किया था।

किसानों से बातचीत में गांधीजी ने पूछा, मैसूर पर किसका शासन है? उन्हें उत्तर मिला, देवता का! मैं यह जानने को उत्सुक था कि किसानों ने वास्तव में क्या कहा होगा। लिहाजा मैंने कारनाड से पूछा कि 1927 के मैसूर में गरीब किसानों ने वास्तव में किसी देवता के लिए मूलतः कन्नड़ में क्या शब्द इस्तेमाल किए होंगे? याव्दो देवरु या फिर वारो देवरु इसका सही अनुवाद हो सकता है, उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने जो शब्द सुझाए हैं वे कुछ ज्यादा ही साहित्यिक हैं और किसी किसान के लिहाज से जटिल लगते हैं। फिर उन्होंने री-टेक के अंदाज में कहा-हो सकता है उन्होंने सिर्फ देवरु या हद से हद आ देवरु कहा हो, जो निराशा, नाउम्मीदी को दर्शाता है। यही तो मुझे जानना था। कारनाड जानते थे कि शब्द महज शब्द नहीं होते। शब्द वास्तव में बोलने वाले के दिमाग, दिल और रूह की स्थिति के बारे में भी कुछ कहते हैं। स्पष्ट तौर पर किसानों द्वारा गांधीजी को दिए गए जवाब में एक तरह की निराशा की झलक थी। कारनाड द्वारा की गई इस व्याख्या से मुझे न सिर्फ समानार्थी शब्द मिला, बल्कि नब्बे साल पहले मैसूर के किसानों की अंदरूनी स्थिति की झलक भी मिली।

आज भारत में ऐसे कम ही लोग होंगे जो एक से ज्यादा भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी न सिर्फ सहजतापूर्वक, बल्कि उत्तम ढंग से लिख और बोल सकते हैं। हम ऐसे बहुभाषी लोग हैं जिनकी एक भाषा में प्रवीणता है और कुछ अंग्रेजी एवं कुछ हिंदी भी जानते हैं। हालांकि यह कोई ऐसी बात नहीं जिस पर विलाप किया जाए, लेकिन हकीकत यही है कि इसके नतीजतन हम अलग-अलग भाषा, संस्कृति और ज्ञान के शिकंजे में जकड़कर रह गए हैं। एक भारत दूसरे भारत से अनजान है, भारतीय अपने साथी-भारतीयों से अजनबी हैं। गिरीश को अपनी कन्नड़ भाषा से प्यार था और वह इसे अपनी पीढ़ी के किसी भी अंग्रेजीदां, दुनिया घूमने वाले, बेंगलुरु-बेस्ड विचारकों से कहीं बेहतर जानते थे। मुझे यकीन है कि उन्हें कन्नड़ गुणन सारणी भी याद होगी, जो किसी के भी मातृभाषा ज्ञान को परखने की तयशुदा कसौटी है। उन्होंने जब ययाति लिखा तब वह 23 साल के थे। तुगलक उन्होंने 26 साल की उम्र में लिखा। ये नाटक काफी सफल रहे और इसके बाद उन्होंने एक ऐसा नाटक लिखा, जिसने न सिर्फ उन्हें एक गंभीर बल्कि सर्वकालिक भारतीय नाटककारों में शुमार कर दिया। यह नाटक था हयवदन, जो वैसे तो थॉमस मन की कथा ट्रांसपोज्ड हेड्स पर आधारित था, लेकिन मूलतः प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कथासरिता सागर की एक गाथा से प्रेरित था।

कारनाड ने न सिर्फ भाषाओं को आपस में जोड़ा, बल्कि पीढ़ियों को भी जोड़ने का काम किया। गिरीश कारनाड हमारे दौर के एक ऐसे अजीम शख्स थे, जिनका मानना था कि कला, कुछ लीन या प्रभुत्ववादी वर्गों का खिलौना नहीं है। वह समूचे समाज की संपत्ति है। उन्होंने फोक और क्लासिकल, निम्न और उच्च कला के भेद को मिटा दिया, लेकिन कला के दार्शनिक होने से भी बढ़कर वह मानवीय स्थिति के दार्शनिक थे। दर्शन में समाज का चिंतन प्रमुख रहा है। कारनाड एक समाज-दार्शनिक थे। हमें आज अपने देश में सामाजिक दार्शनिकों की जरूरत है। हमें ऐसे दार्शनिक चाहिए, जो हमारे बारे में कड़वी हकीकत बयान कर सकें कि हम कमजोरों (बच्चे, महिलाएं, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शारीरिक-मानसिक रूप से निःशक्त, ट्रांसजेंडर्स आदि) के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जरा देखें कि हम निःशक्तों के लिए या नौकरों के लिए कैसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई कलाकार मरता है तो कला रोती है। जब कोई दार्शनिक मरता है तो विचार रोते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा कलाकार मरता है, जो दार्शनिक भी हो तो जिंदगी रोती है। कारनाड के निधन ने हमें दरिद्र बना दिया है।

(लेखक पूर्व राजनयिक-राज्यपाल हैं और वर्तमान में अध्यापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं की खोज

हम प्रायः मनीषियों से सुनते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वरन हमारे भीतर छिपा हुआ है। हमें उसकी खोज के लिए स्वयं के भीतर उतरना होगा। बात हमें प्रिय भी लगती है, किंतु हम भीतर कैसे उतरें? हमारी समझ में नहीं आता। कारण यह कि हमने जो कुछ पाया बाहर पाया। प्राण वायु के साथ-साथ भोजन, हवा, समस्त भौतिक उपलब्धियां हमें बाहर से मिलीं तो फिर अपने भीतर कैसे उतरें? स्वयं में उस परम को कैसे खोजें? हम आंखें बंद करते हैं तो घबराहट होती है, क्योंकि अंधेरे के सिवा अपने भीतर कुछ नजर नहीं आता। भीतर की अतृप्ति, एक विचित्र सी रिक्तता हमें घबराहट से भर देती है। तब हम या तो परमात्मा को पाने का ख्याल छोड़कर किसी नई भौतिक उपलब्धि की वहिर्यात्रा पर निकल जाते हैं अथवा अन्य कर्मकांडों में उलझ कर मन से लड़ने लगते हैं, जो कि एक नहीं अनंत जन्मों का भटकाव साबित होता है। ऐसा स्वाभाविक है। कारण यह कि परमात्मा से हमारा कभी मिलन ही नहीं हुआ। उसे हम जानते ही नहीं फिर भी अक्सर कहते हैं कि हम मानते हैं। जब सूर्य, चंद्र यहां तक कि अदृश्य वायु को हम नहीं कहते कि इन्हें हम मानते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि हम जानते हैं। कारण यह कि वे हमारे अनुभव में आ चुके हैं, जबकि हमारा परमात्मा का अनुभव कभी हुआ नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम परमात्मा को जानें कैसे? सीधा उत्तर उतना ही असंभव है जैसे हम हवा को मुट्ठी में बांधने का प्रयास करें।

परमात्मा को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। हमें प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए। सूर्य पर दृष्टि जमाएं। रात्रि को हम सो जाते हैं। सोते वक्त हमें अपनी पद, प्रतिष्ठा, बैंक बैलेंस यहां तक कि नाम तक का बोध नहीं होता। स्वप्न में मैं हूं (साक्षी) का बोध मौजूद रहता है और हम कभी राजा कभी भिखारी बने दौड़ते रहते हैं, किंतु अगर नींद स्वप्न रहित हो तो आंख खुलने पर हमें नाम, पद, धन, यश सब याद हो जाता है और हम अहंकार से भर उठते हैं। आईने के सामने खड़े होकर स्वयं को देखें। किंतु शारीरिक परिवर्तन को अपना परिवर्तन मानने के बजाय भीतर उस तत्व को खोजें जो अभी भी अपरिवर्तित है। बौद्धिक एवं शारीरिक विकास से दूर वही साक्षी परमात्मा हमारा असली स्वरूप है।

रंजना गोंडवी

तथ्य-कथ्य | **लोकसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों की जीत का प्रतिशत** (आंकड़े फीसद में)

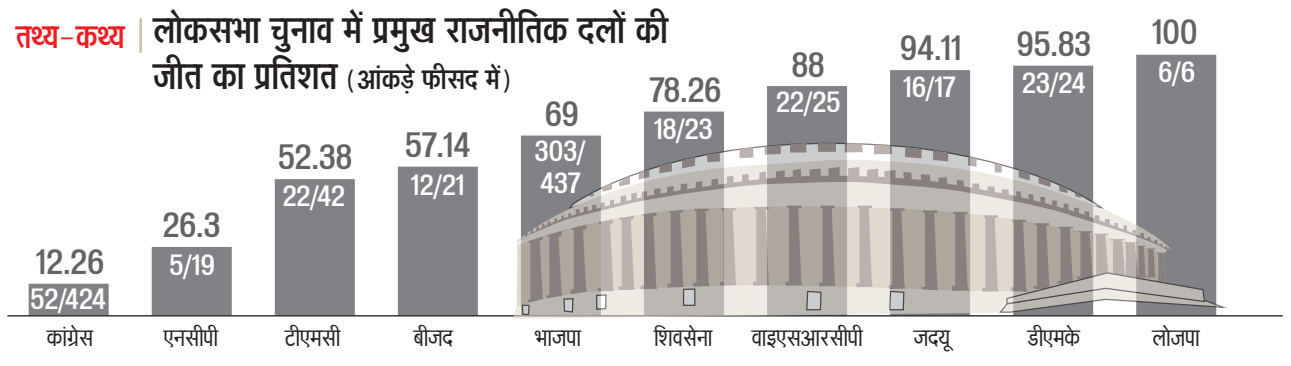

दर्शकों को रिझाती टेक्नोलॉजी

डॉ. महेश परिमल

आजकल क्रिकेट मैचों को रोचक बनाने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है

क्रिकेट में अब केवल दो कैमरों से काम नहीं चलता, अब तो पूरे मैदान में दर्जन से ज्यादा कैमरे लगे होते हैं, जो हर एंगल से बॉल को आते-जाते दिखाते हैं। यही नहीं, अब तो क्रिकेट में बेईमानी जैसी कोई बात ही नहीं रही। सब कुछ कैमरे में कैद होने लगा है। बॉल के साथ छेड़छाड़ हो या प्रतिस्पर्धी टीम के खिलाड़ी से बहस। सब कुछ कैमरा अपनी आंखों से देखकर हमें दिखा रहा है। इस बार वर्ल्ड कप में स्पाइडर कैमरे का इस्तेमाल बड़ी शिद्दत से हो रहा है। अपने नाम के अनुसार यह कैमरा मैदान में उड़ता रहता है। यह कैमरा रिमोट से संचालित होता है। उसे ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाएं-बाएं किया जा सकता है। इसके कारण दर्शकों को मैदान का बहुत ही सुहावना दृश्य दिखाई देता है। जो इसके पहले नहीं दिखता था।

वैसे तो यह एक ड्रोन कैमरे की तरह ही है। यह सीमित क्षेत्र की छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी अपनी नजर रखता है। इस कैमरे को चलाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। खिलाड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सभी खिलाड़ी ट्रैकिंग डिवाइस पहनकर मैदान में उतरते हैं। इसमें खिलाड़ियों की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहती हैं। इसका विश्लेषण कर क्रिकेट विशेषज्ञ बता सकते हैं कि कौन-सा खिलाड़ी कौन-सा काम सही तरीके से कर सकता है। डीआरएस यानी डिसिजन रिव्यू सिस्टम अब नया नहीं है। अंपायर का निर्णय यदि संदेहास्पद लगे या अंपायर को ही खुद समझ में न आए तो वे डीआरएस का इस्तेमाल करते हैं। डीआरएस में बॉल का रास्ता देखा जाता है, ताकि एलबीडब्ल्यू जैसे फैसले के समय सच्चा अंदाज लगाया जा सके। बॉल के बैट से टच होने की आवाज आई या नहीं, यह जानने के लिए माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल में लाई जाती है। इससे गलत फैसलों की संख्या में कमी आई है।

कई बार डीआरएस पर भी संदेह की अंगुलियां उठने लगती हैं, ऐसे में एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है, उसे कहते हैं स्निकोमीटर। बैट से बॉल यदि जरा भी टच करे या फिर बॉल की सिलाई भी यदि बैट से टच हुई हो तो इन हालात में आउट-नॉट आउट का फैसला देना मुश्किल हो जाता है। इस हल्के से स्पर्श को स्निक कहा जाता है। इसी स्निक को मापने के लिए इस मीटर को विकसित किया गया है। टेक्नोलॉजी की तरह ही डाटा का भी अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा है। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें किस बल्लेबाज ने किस गेंदबाज के सामने, किस बॉल पर, किस समय, किस ओवर में, किस कोने से रन बनाए, कब आउट हुआ, किस प्रकार की बॉल के समय अधिक आउट हुआ आदि सारी जानकारी तुरंत टीवी के स्क्रीन पर आ जाती है।

जिंग बेल्स यानी स्टंप पर रखी चमकदार गिल्लियां, यदि वे अपने स्थान से हटती हैं, तो लाइट जल जाती है। इससे यह पता चल जाता है कि खिलाड़ी आउट है या नहीं। इसी तरह स्पीड मापने के लिए स्पीड गन, अंपायर की टोपी पर लगाया जाने वाला अंपायर कैम, सुपर स्लो-मोशन आदि कई टेक्नोलॉजी के कारण यह खेल और भी रोचक हो गया है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

राजनीति में जनसेवा का अभाव

दलों के बंधन में जकड़ा लोकतंत्र शीर्षक से लिखे अपने लेख में योगेंद्र नारायण ने हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को पार्टी हाईकमान के हाथों की कठपुतली बताया है। हालांकि मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दलों के बंधन से ज्यादा निजी स्वार्थ में जकड़ा हुआ है। हमारे यहां अधिकांश लोग राजनीति में अपने निजी स्वार्थ के लिए ही आते हैं, देशसेवा और जनसेवा के लिए नहीं। अगर देश की राजनीति में शत प्रतिशत लोग देशसेवा और जनसेवा की मंशा से आए होते तो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख पर दाग न लगा होता और न ही देश विभिन्न समस्याओं के मकड़जाल में उलझा होता। कुछ जनप्रतिनिधियों को पार्टी हाईकमान की अंगुलियों पर इसलिए नाचना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पार्टी हाईकमान के खिलाफ जाने पर अपनी कुर्सी जाने का डर रहता है। वहीं कुछ जनप्रतिनिधि पार्टी हाईकमान के हाथों की कठपुतली इसलिए भी बनते हैं, क्योंकि हाईकमान उनके दोषों और गलतियों पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश करता है। जाहिर है देश की राजनीति में जब तक शत प्रतिशत लोग देशसेवा-जनसेवा के लिए नहीं आएंगे और मौजूदा सत्ताधारी-राजनेता अपने दिल-दिमाग में ऐसी भावना नहीं भरेंगे, तब तक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र विभिन्न व्याधियों में जकड़ा रहेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पच नहीं रही प्रचंड जीत

'छल भरी राजनीति का तिरस्कार' शीर्षक से संपादकीय पेज पर प्रकाशित प्रदीप सिंह का आलेख लोकसभा चुनावों के परिणामों के पश्चात राजनीतिक और बौद्धिक विरोधियों के स्वप्न लोक में रहने और दिवा स्वप्न देखने का सटीक विश्लेषण किया है। यह आश्चर्य की बात है कि अब भी विरोधियों को नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत पच नहीं रही है। वास्तविकता तो यह है कि जहां एक ओर मोदी की स्वच्छ छवि, कुशल नेतृत्व, अमित शाह की विलक्षण सांगठनिक क्षमता और अपने कर्मठ और उत्साही कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने 'सबका साथ सबका विकास' नारा देकर भारतीय जन-मानस में गहरी पैठ की है वहीं दूसरी ओर सभी विरोधियों का एकमात्र नारा था 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' यहां तक कि कल तक एक-दूसरे का मुंह तक न देखने वाले राजनीतिक दलों ने भी अल्पकालिक स्वार्थी गठबंधन बनाकर मोदी को पानी पी-पी कर कोसा। वे व्यक्ति, धर्म और जाति विशेष का विष और कीचड़ फैलाते रहे किंतु वह उन पर ही गिरा व कमल और प्रखर रूप से प्रस्फुटित हुआ। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इस चुनाव में मतदाताओं का विश्वास नहीं पा सकी और पूरे चुनाव के दौरान भटकी रही। कांग्रेस अपना स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर सकती थी, लेकिन उसके नेताओं, विशेषतया अध्यक्ष, ने जिस प्रकार चुनावों में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उससे उन्हें लाभ की अपेक्षा हानि ही हुई।

trchamoli@rediffmail.com

नापाक हरकतें

खस्ताहाल इमरान सरकार द्वारा सीधे मोदी सरकार से बार-बार बातचीत की गुहार लगाना, बिश्केक के एससीओ सम्मेलन में पाक द्वारा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मोदी सरकार पर द्विपक्षीय बातचीत का दबाव बनवाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल दो टूक-नहीं सुधर रहा पाकिस्तान कह कर हाल फिलहाल बातचीत नहीं करने का सख्त संदेश दे दिया। क्योंकि गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी। वैसे द्विपक्षीय बातचीत नहीं होने के अच्छे भले कारण हैं जैसे पुलवामा हमले के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बावजूद भी पाक द्वारा पोषित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा व जैश ए मुहम्मद पर कोरी दिखावे की कार्रवाई करना, बॉर्डर पर सीज फायर का बार-बार उल्लंघन कर भारी गोलाबारी करना, कश्मीर को अशांत करने के लिए आइएसआइ द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों व फिदायीन दस्ते भेजना, विभिन्न क्षेत्रों में सेनाओं पर हमले करवाना आदि बहुत से कारण हैं। दूसरा अगर भविष्य में कोई बातचीत का माहौल बनता भी है तो भारत सरकार किससे बात करे कठपुतली सरकार से या आतंकवादियों से या फिर पाक सेनाध्यक्ष से? यकीनन पहले पाक को अपने घर को सुधारना ही होगा।

दीपक

500 मिलीग्राम से जहां कम है पानी में टीडीएस की मात्रा, घरों में सप्लाई होने वाला ऐसा जल पीने लायक है। इस आशय का दिशानिर्देश एनजीटी द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार को जारी किया गया है।

आजकल

आसान नहीं उच्च शिक्षा में सुधार की राह

दर्शनी प्रिय
स्वतंत्र टिप्पणीकार

किसी भी राष्ट्र की आधारशिला शिक्षा के मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। बुनियादी शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रत्येक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना है और इसे हासिल किए बगैर न तो वह सार्वभौमिक रूप से विकास के मानदंडों पर खरा उतर सकता है, और न ही वह वैश्विक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आज देश उच्च शिक्षा के संस्थानों और प्राध्यापकों की भारी कमी झेल रहा है। शिक्षा और शैक्षिक व्यवस्थाएं हाशिये पर हैं। नए संस्थानों का निर्माण और नए पदों का सृजन लगभग बंद है। लगातार गिरता शिक्षा का स्तर यह सोचने पर बाध्य करता है कि आगामी दशक में हम किस तरह विकसित देशों की कतार में शामिल हो पाएंगे

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए स्वीकृत प्राध्यापकों के कुल पदों के 30 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन (वर्ष 2017-18) के आकड़ों के अनुसार देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े शिक्षकों के 30 प्रतिशत पद हैरानी में डालने वाले हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी और आधारभूत सुविधाओं की कमी के चलते हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन सरीखे देशों में भारतीय छात्रों का पलायन तेजी से हुआ है। यूनेस्को के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2013 तक विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की कुल संख्या 1,81,872 थी। एसोचैम के मुताबिक एक बड़ी राशि देश से बाहर इस मद में जा रही है जिसे हम अपने प्रयासों से कम कर सकते हैं। बड़े स्तर पर पलायन भारतीय शैक्षिक संस्थानों की क्षमता और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विश्व की बड़ी शैक्षिक आधारभूत अवसंरचना वाला देश जहां 700 से अधिक विश्वविद्यालय और 40,000 कॉलेज की भारी भरकम संख्या है और जिसमें लगभग हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, वहां इतने व्यापक स्तर पर छात्रों का पलायन देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश अपने यहां प्रतिभा पलायन रोकने में सक्षम नहीं है, यह बात बहुत चौंकाती है। एक अनुमान के अनुसार आनेवाले दशक में लगभग एक करोड़ भारतीय छात्रों के देश से पलायन करने की संभावना है।

व्यावसायिक शिक्षण संस्थान

व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में भी कमोबेश यही स्थिति है। सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हमारे आइटी पेशेवरों में रोजगार की योग्यता संबंधी कमी और विश्वविख्यात आइएमडी बिजनेस स्कूल स्विट्जरलैंड द्वारा प्रकाशित ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2018 की रिपोर्ट से चिंताजनक संकेत मिले हैं। आइएमडी बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट में भारत 63 देशों की सूची में पिछले वर्ष के मुकाबले 51वें से फिसलकर दो पायदान नीचे 53वें स्थान पर पहुंच गया है। परेशानी की बात यह है कि शैक्षणिक प्रणाली की गुणवत्ता और विकास के मामले में भारत इस सूची में काफी पीछे है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि भारत में 91 फीसद आइटी पेशेवर नौकरी संबंधी योग्यता के मापदंड पर खरे नहीं उतरते।

यह बात परेशान करती है कि शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता पर सरकारी एजेंसियों का कोई ध्यान नहीं है। और यदि छिटपुट प्रयास हो भी रहे हैं तो वे शिक्षा की मौजूदा दशा सुधारने में नाकाफी हैं। विश्व के 100 शीर्ष विश्वविद्यालय में से 46 अति प्रभावशाली विश्वविद्यालय अकेले अमेरिका में है। एशियाई देशों के खाते में मात्र 11 विश्वविद्यालय है। इस प्रतिस्पर्धा में चीन हमें कड़ी टक्टर दे रहा है। न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन हर साल एक बड़ी रकम मानव संसाधन में निवेश कर रहा है। दूसरी ओर भारत में उच्च शिक्षा हेतु पंजीयन कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम यानी महज 11 फीसद है। इस अनुपात को 15 फीसद तक ले जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को लगभग 2,26,410 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।

एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नए भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में देखें तो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को शुरू करने की सबसे कठिन शर्तें हैं। हालांकि यह काफी हद तक संसाधन और निवेश जुटाने, भूमि संबंधी मानदंड एवं अन्य शर्तों से संबंधित है। उच्च शिक्षा के लिए एक सामान्य विनियामक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि संस्थानों के अलगाव और एकाकीपन को खत्म किया जा सके। इन तमाम चुनौतियों से निपटने के अतिरिक्त सरकार को उच्च शिक्षा के मौजूदा संकटग्रस्त स्थिति से उबरने के लिए उच्च संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरना होगा। साथ ही विश्वस्तरीय संस्थागत सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास भी सुनिश्चित करने होंगे ताकि छात्रों को अध्ययन और विकास का उचित माहौल मिल सके जिससे वे ज्ञान व कौशल से लैस होकर वैश्विक परिदृश्य में पूरी धमक के साथ उतर सकें। उन्नत संसाधनों तथा योग्य प्राध्यापकों से ही छात्रों का समग्र विकास संभव है। भारत को यदि शिक्षा के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना है तो उसे शिक्षण संस्थानों के प्रति छात्रों के आकर्षण का बनाए रखना होगा। शिक्षा के प्रतिष्ठित और मानक संस्थानों को पुनर्जीवित कर उन्हें एक नया स्वरूप देना होगा। इस दिशा में की गई प्रत्येक सार्थक पहल छात्रों की उन्नति में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

पाठ्यक्रमों में समयानुकूल परिवर्तन वक्त की जरूरत

योजना आयोग के सदस्य और पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति नरेंद्र जाधव का मानना है कि कई विश्वविद्यालयों में पिछले 30 वर्षों से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव ही नहीं किया गया है। बकौल जाधव जमीनी हकीकत से परे पुराने पाठ्यक्रम शिक्षक और उच्च शिक्षा को नष्ट करने के लिए काफी हैं। ऐसा नहीं है कि इसे सुधारने के प्रयास नहीं किए जा रहे। पिछले चार सालों में सात आइआइटी, सात आइआइएम, 14 एम्स या तो स्थापित किए गए हैं या स्थापनाधीन हैं, परंतु शुरू नहीं हो पाए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च को पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा सरकारी सहायता निधियों का आबंटन प्राप्त हुआ है, लेकिन ये शिक्षा संस्थान ज्ञान प्रदाता की अपनी भूमिका में नाकाम साबित हुए हैं। भारी भरकम बजट अनुदान प्राप्त करने वाले ये संस्थान सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। भले ही शिक्षा की वर्तमान दशा में क्रमिक परिवर्तन हेतु सरकार द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, मसलन ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की ओर बढ़ना, सर्वशिक्षा अभियान का दायरा आठवीं कक्षा से बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक करना, शिक्षा बजट में दस फीसद की वृद्धि, शैक्षिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि का आवंटन और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप योजना की शुरुआत आदि। लेकिन उचित क्रियान्वयन, अनुरक्षण और विकास की मंद गति के चलते हालात जस के तस बने हुए हैं।

सरकार लगातार उच्च शिक्षा पर जोर देती रही है यह उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे शीर्ष पर है, लेकिन एचईएफए हायर एजुकेशन फाइनांसिग एजेंसी जैसे संस्थानों के बजट में 650 करोड़ रुपये की कटौती कर शिक्षा संबंधी उसकी अदूरदर्शिता को दर्शाती है। यह वही एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 2107 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों की आधारभूत संरचना विकास के लिए की गई थी। कुछ वर्ष पहले समृद्ध राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ा चुके हमारे पड़ोसी चीन की भी कमोबेश यही स्थिति थी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता और गुणवत्ता जैसे पक्षों पर ध्यान देने और दो महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिये उसने खुद को शीघ्र ही इस स्थिति से उबार लिया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य 21वीं सदी तक चीनी विश्वविद्यालयों को विश्व स्तर पर खड़ा करना है। भारत को चीन से सबक लेते हुए अपनी तकनीकी कुशलता में विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्षमतावर्धन, उच्च कौशल प्रशिक्षण, उन्नत शैक्षिक विकल्पों की खोज, प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन और आधारभूत संरचना सहित प्रयोगशालाओं की मौजूदा आदि में सुधार के जरिये खुद को इस स्थिति से उबारने में तेजी से पहल करनी होगी।

रोजगारपरक उच्च शिक्षा से तरक्की करेगा देश

आज देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी समीक्षा शोध निधियों की कमी है जिससे शोध की गुणवत्ता पर काफी असर पड़ रहा है। उच्च शिक्षा के खाली पदों को भरने के साथ ही शिक्षण केंद्रों में आधारभूत संरचना का त्वरित विकास, योग्य फैकल्टी की भर्ती सहित भारी फीस आदि में कटौती भी सरकार की अन्य शीर्ष चुनौती है। युवाओं की फौज को नवाचार और कौशलयुक्त ज्ञान देकर डिग्री के साथ-साथ उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से लैस करना ताकी वे स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों, सांध्यकालीन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स इत्यादि के माध्यम से इस जरूरत को पूरा करने के तरीकों पर विचार किया जा सकता है। देश भर में पैरा-टीचर्स, शिक्षाकर्मी, शिक्षामित्र आदि व्यवस्था को बंद कर उनकी जगह स्थायी शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाए।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव का प्रारूप

हाल में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप में सकारात्मक पहल करते हुए कई आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जिसमें सरकार द्वारा देश भर में 50 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। देश भर में नए तकनीकी और मानविकी विश्वविद्यालय शुरू करने संबंधी विषय को प्रमुखता से रखा गया है। बावजूद इसके कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बदलाव की आवश्यकता है, यथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मजबूत बनाना, उत्कृष्ट विद्यार्थियों को शिक्षण पेशे में प्रवेश करने को प्रोत्साहित करने के लिए मेरिट आधारित छात्रवृति देना। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को समान प्रोत्साहन और सशक्तीकरण, नए संस्थागत ढांचे का विकास, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करना, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा हेतु एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र आदि कई ऐसे कार्य हैं जिस पर सरकारी नीतियों में बदलाव की जरूरत है।

तकनीकी शिक्षा से मुमकिन व्यापक बदलाव

पेशेवर शिक्षा के क्षेत्र में नए और उभरते हुए संकायों पर रणनीतिक रूप से जोर देना होगा। भारत को उन सभी तकनीकी क्षेत्रों में बढ़त लेने का प्रयास करना चाहिए जो वर्तमान में तेजी से विकसित हो रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, थ्रीडी तकनीक, बिग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग, जीनोमिक स्टडीज, बायो-टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस और विज्ञान के ऐसे ही कई क्षेत्र। इन विषयों को और ऐसे ही कई अन्य विषयों को विज्ञान की तीनों राष्ट्रीय अकादमियों और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के सहयोग से पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। इसके लिए कार्यरत और सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों और अभियंताओं को इन तकनीकी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

खरी-खरी

गर्दभ थेरेपी से तनाव मुक्त जीवन

दीपक गिरकर

आजकल विदेशों में तनाव से मुक्ति के लिए गर्दभ थेरेपी का काफी प्रचार-प्रसार हो रहा है। इस थेरेपी से बहुत सारे लोगों को तनाव से मुक्ति मिली है। बताया जाता है कि कुछ दिन गधों के साथ रहने से सभी प्रकार के मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं और गर्दभ थेरेपी लेने वाला व्यक्ति तरोताजा महसूस करने लगता है। गधा किसी डॉक्टर से कम नहीं है। इस नई चिकित्सा पद्धति में गधे को अवसाद, दुख, अकेलापन और चिंता परेशानी दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बेहद कारगर माना जा रहा है। विदेशों में इस थेरेपी का उपयोग कैंसर मरीजों के लिए भी किया जा रहा है।

हमारे देश में भी गुजरात के अहमदाबाद में 'डंकी असिस्टेड थेरेपी' नाम की एक संस्था है जिसमें गर्दभ थेरेपी से कई लोगों को तनाव से मुक्ति मिली है। इस थेरेपी में अस्वस्थ व्यक्ति को गधों के बीच रखा जाता है, उनके साथ संवाद कराया जाता है और गधों पर सवारी कराई जाती है।

हमारे देश में तो यह थेरेपी काफी प्राचीन है। बचपन में जब स्कूल में हमारे शिक्षक हमारे सहपाठियों के कान मरोड़कर कहते थे 'तुम गधे के गधे रहोगे' तब हमारा और हमारे साथियों का सारा तनाव दूर हो जाता था, क्योंकि पूरी कक्षा के छात्र जोर से हंसते थे और जब शिक्षक हमें कक्षा से बाहर निकाल देते थे तब हमारा अधिकांश समय गधों के साथ ही व्यतीत होता था। होली के त्यौहार पर धुलेंडी के दिन हमारी मित्रमंडली गधों पर बैठकर ही नगर भ्रमण करती थी। घर में भी हमारा यही हाल था। अभिभावक हमारे कान मरोड़कर कहते थे 'तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे।' मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी प्रसन्नता का राज गधे ही हैं। गधों में सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। एक गधा दूसरे गधे की आवाज दूर से आसानी से सुन सकता है। इसलिए गधा किसी भी बात को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। इसलिए तो गधे पूर्ण रूप से तनावमुक्त रहते हैं।

यदि किसी कारणवश आपके दिमाग का दही हो गया हो तब भी यह गर्दभ थेरेपी बेहद उपयोगी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के सभी शहरों और कस्बों में गर्दभ थेरेपी के केंद्र उसी प्रकार खुल सकते हैं जिस प्रकार आज तनाव से मुक्ति के लिए योगा केंद्र खुले हैं। जानकारी मिल रही है कि देश के कई शहरों में ये केंद्र शुरू भी हो रहे हैं।

ट्वीट-ट्वीट

हड़ताल हल नहीं। सच बात है, लेकिन मरीज की जान चली जाए तो डॉक्टर का सिर तोड़ देना कौन सा हल है? क्या उससे मरीज की जान वापस आ जाती है? या बदला पूरा करके तसल्ली मिल जाती है मरीज के परिवार को?
रोहित सरदाना@sardanarohit

शिखर धवन की जगह पर एहतियातन रिषभ पंत को भेजना सही कदम है। ऐसे देश में जहां मौसम का मिजाज बहुत अस्थिर है वहां बैकअप खिलाड़ी को पहले से भेजने में ही भलाई है, ताकि वह हालात के हिसाब से ढल जाए।
अयाज मेमन@cricketwallah

अगर दस मिनट के शॉवर में 264 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है तो दिल्ली जैसे शहर में यदि दस लाख लोग भी शॉवर लेते होंगे तो कितना पानी खर्च होता होगा। क्या यह पानी की बर्बादी नहीं? क्या हम हर घर से शॉवर नहीं हटा सकते। आखिर लोगों को कुछ त्याग क्यों नहीं करना चाहिए?
देविंदर शर्मा@Devinder_Sharma

जल संरक्षण को सर्वत्र मिले उच्च प्राथमिकता

विनोद कुमार यादव
स्वतंत्र टिप्पणीकार

संपूर्ण विश्व जल संकट से जूझ रहा है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में पानी की कमी महसूस की जा रही है। हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में पानी खारा नहीं है और जिन रिहायशी क्षेत्रों में टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां जल शोधन संयंत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए।

एनजीटी द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए आदेश में कहा गया है कि जिन जगहों पर पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम है, वहां घरों में सप्लाई होने वाले नल का पानी पीने लायक होता है। ऐसे इलाकों में आरओ सिस्टम के इस्तेमाल पर एनजीटी द्वारा चिंता जाहिर करना जायज है। इस सिस्टम के तहत पानी की शुद्धिकरण प्रक्रिया में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। जबकि करोड़ों भारतवासी ऐसे भी हैं, जिन्हें पानी मयस्सर नहीं हो पाता। आरओ एक ऐसे सिस्टम के अंतर्गत काम करता है, जिसमें पानी के शुद्धिकरण के लिए रिवर्स ओस्मोसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पर्यावरणविदों के मुताबिक, इस सिस्टम में 100 लीटर पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया में मात्र 40 लीटर पानी ही शुद्ध किया जा सकता है, यानी 60 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। स्पष्ट तौर पर जिन इलाकों में सप्लाई होने वाले पानी के टीडीएस का मानक स्तर सही है, वहां आरओ का इस्तेमाल बेशकीमती जल संसाधन की बर्बादी का खास कारण है। एनजीटी ने केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए कहा है कि उसका यह भी फर्ज है कि वो लोगों को मिनरल वाटर से होने वाले नुकसानों के बारे में भी आगाह करे, क्योंकि आरओ पानी से जिंक की मात्रा को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिससे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पाचनतंत्र समेत शरीर की प्रतिरोधी क्षमता भी क्षीण हो जाती है। सवाल इस बात का है कि पर्यावरण सुरक्षा, पेयजल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन

व स्वास्थ्य मूल्यांकन जैसे गंभीर मुद्दों पर एनजीटी जैसे प्राधिकरण को सरकार के लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है, जबकि केंद्र सरकार के पास इन विभागों के अलग-अलग मंत्रालय भी हैं।

पर्यावरण संरक्षण एवं जलप्रबंधन सरकार के प्राथमिक एजेंडे में होने चाहिए और इस संबंध में एक स्पष्ट कार्ययोजना जमीनी स्तर पर लागू की जानी चाहिए। शिथिल जलप्रबंधन के अलावा इंसानी लापरवाही की वजह से भी देश के दूर-दराज क्षेत्रों की बात तो छोड़िए राजधानी की अनेक पुनर्वास कॉलोनियों में भी गर्मी के मौसम में लोगों के लिए पानी की भारी किल्लत हो जाती है। राजधानी की पॉश कॉलोनियों में अमूमन यह भी देखने में आता है कि कुछ संभ्रांत लोग शुद्ध पेय जल से अपनी गाड़ियां धोते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो रुटीन में पेयजल की सप्लाई से ही सुबह-शाम घर के बाहर जल छिड़काव करते हैं। इससे बहुत अधिक मात्रा में पीने के पानी का दुरुपयोग होता है। जिस जल से हजारों जरूरतमंदों की प्यास बुझाई जा सकती है, वह नालियों में बहकर व्यर्थ चला जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर यह भी देखा गया है कि लोग लापरवाही की वजह से पानी की टोंटी खुली छोड़ देते हैं, जिससे यह बेशकीमती जल व्यर्थ बहता रहता है, इस तरह की लापरवाही के लिए प्रशासन की ओर से लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।

विश्व स्तर पर जल संकट से जुड़ी गंभीर खबरे आ रही हैं, दुनिया के तमाम मुल्क अपने-अपने तरीके से इस समस्या से निजात पाने की कोशिश में लगे हैं। हाल ही में भीषण सूखे की मार झेल रहे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में व्यापक जल प्रतिबंधों को लागू किया गया है, इन प्रतिबंधों के तहत वहां की न्यू साउथ वेल्स सरकार ने नल खुला छोड़ने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। इसके साथ-साथ यदि कोई गमलों व बगीचे में पाइप द्वारा पानी का छिड़काव करता हुआ मिला तो उसे भी जुर्माना देना होगा। जल-संरक्षण के निमित्त बनाए गए नियमों के अंतर्गत यदि घरों में उल्लंघन हुआ, यानी किसी घर में नल खुला छोड़ने पर उसके मकान- मालिक को जुर्माने के तौर पर 220 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने होंगे। यदि कोई कारोबारी इस नियम को तोड़ता है तो उसे 550 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा करने होंगे। सिडनी की तर्ज पर कुछ इस तरह के जल प्रतिबंध से संबंधित नियमों को लागू करने की कवायद हमारे देश की राजधानी सहित सभी प्रमुख शहरों के लिए भी चलनी चाहिए। जितना पानी जीवन के लिए आवश्यक है, उसकी उपलब्धता हर किसी के लिए सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है, इसके लिए सावधानीपूर्वक जल-प्रबंधन करना होगा। जलसंकट को ध्यान में रखते हुए इस तरह के नियमों को अमल में लाना जरूरी है। साथ ही साथ पेयजल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों व महिलाओं की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या शिखर धवन के बैकअप के तौर पर रिषभ पंत सही विकल्प हैं?

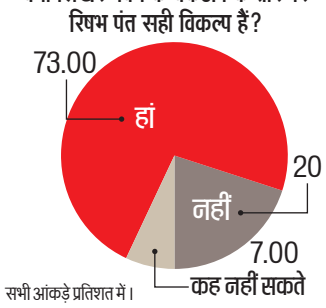

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

कोलकाता में हुई मारपीट की घटना के विरोध में डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

हो सकती है दोस्ती यदि नीयत हो साफ,
आतंकी 'एक्सपोर्ट' पर रोक लगाओ आप।
रोक लगाओ आप रुके 'नापाक' तिजारत,
तब आगे का प्लान मियां कुछ सोचे भारत।
गर हाफिज के साथ रहेगी खिचड़ी पकती,
कह देता हूं साफ दोस्ती 'ना' हो सकती।
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

जीएसटी में सुधार की उम्मीद!

अभिषेक राजा
वस्तु एवं सेवा कर विशेषज्ञ

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पर बीते चुनाव में बहुत चर्चा हो चुकी है। इसमें कई व्यावहारिक खामियां सामने आई हैं जिनका समाधान होना चाहिए ताकि यह सभी के लिए सुगम हो सके

हालिया संपन्न चुनाव प्रचार के दौरान जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर में सुधार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चर्चा में रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' से संबोधित किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में वस्तु एवं सेवा कर में सुधार का वादा किया, किंतु उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। तो क्या जनता को लगता है कि जीएसटी में सुधार की जरूरत नहीं है या यह पूरी तरह सही है? हमें इसके बारे में व्यापक तौर पर जानना चाहिए।

चूंकि जीएसटी के नियम व कानून समग्र तौर पर जीएसटी परिषद यानी काउंसिल पर ही आधारित हैं, लिहाजा जीएसटी काउंसिल की सरंचना कुछ इस प्रकार है कि बिना केंद्र सरकार की सहमति के कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इस परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री और केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री भी इसके सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। केंद्र सरकार को एक तिहाई मतदान का अधिकार है और शेष दो तिहाई मतदान का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। लेकिन किसी भी विषय पर अगर मतदान की आवश्यकता होती है, तो विषय के पक्ष में 75 प्रतिशत मत होने चाहिए, जबकि राज्य सरकारों के पास 67 प्रतिशत मत और केंद्र सरकार को 33 प्रतिशत मतदान का अधिकार है। मतलब अगर सभी राज्य सरकारें किसी एक बात पर एकमत भी हो जाएं तो भी बिना केंद्र सरकार की सहमति के कुछ नियम लागू नहीं करा सकती। बहुत सारे पहलू हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

छोटे व्यापारियों के लिए त्रैमासिक कर भुगतान : छोटे व्यापारियों के लिए त्रैमासिक कर रिटर्न जीएसटी आर वन भरने का प्रावधान तो है, किंतु जीएसटी आर थ्री बी मासिक का नहीं। यानी छोटे व्यापारी को जीएसटी की संक्षिप्त विवरणी मासिक भरनी होती है और कर भी मासिक जमा करना होता है। त्रैमासिक महज औपचारिक बन कर रह गया है। सरकार को इनकी संक्षिप्त विवरणी को त्रैमासिक में परिवर्तित कर देना चाहिए, जिससे छोटे व्यापारी समग्र लाभ से वंचित न रहें।

रिटर्न संशोधन प्रणाली : जीएसटी दुनिया का शायद पहला ऐसा कानून है जिसमें रिटर्न को संशोधित करने का प्रावधान नहीं है। यह अपनेआप में एक समस्या है। यह एक नया कानून था और रिटर्न भरने में गलती होने की संभावना भी रहती है। इसलिए रिटर्न संशोधित करने का प्रावधान भी होना चाहिए।

संचार प्रौद्योगिकी की सरल रचना : चार मई 2018 को जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि जीएसटी की संचार प्रौद्योगिकी की रचना को सरल किया जाएगा, किंतु आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ समय पहले सरल रिटर्न के नाम भी बताए गए थे जिसे एक अप्रैल 2019 से लागू होना था, किंतु आज तक पुरानी रिटर्न ही चल रही है। सरकार को इस पर अतिशीघ्र काम करना चाहिए।

दरों में कटौती : जीएसटी की दरें 0 प्रतिशत, पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा उपकर को भी इसमें शामिल किया गया है। सोना, चांदी और हीरे की दरों का अलग से मूल्यांकन किया जाता है। माल की खरीद-बिक्री वाले मुद्रायोजन विक्रेता की दरें एक से दो प्रतिशत तक हैं और सेवा विक्रेता की छह प्रतिशत हैं। जीएसटी को सरल बताकर प्रचारित तो किया जा रहा है, लेकिन कर पर ही इतनी दरें निर्धारित कर दी गई हैं कि यह एक सरल कर प्रणाली के बजाय कठिन कर प्रणाली बनकर उभर आई है।

लघु व्यापारी को अंतर राज्य बिक्री की छूट : परिषद बैठक के दौरान इसमें पंजीकरण हेतु उसी राज्य में कारोबार करने की सीमा 20 या 40 लाख निर्धारित की गई है। लेकिन अगर अंतर राज्य व्यापार एक रुपये का भी है तो पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें लघु व्यापारी अंतर राज्य व्यापार करने में असमर्थ हैं। सरकार को लघु व्यापारियों को छूट देकर उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

दंड एवं शुल्क : जनता को जुलाई 2017 में जीएसटी अपनाने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, परिणामस्वरूप बहुत लोग रिटर्न वक्त रहते भर न सके। वक्त की पाबंदी में रिटर्न फाइल न करने पर व्यापारियों पर लंबित व शुल्क के प्रावधान जारी किए जाते हैं। भारत सरकार ने 31 मार्च 2019 तक देर से रिटर्न दर्ज कराने पर भी कोई दंड संहिता का प्रयोग नहीं किया। फिर भी सभी व्यापारियों ने रिटर्न दर्ज नहीं कराई। क्या अब भी सरकार को एक और मौका ऐसे व्यापारियों को देना चाहिए?

ई-वे-बिल प्रणाली में संशोधन : देश भर में कर की चोरी पर रोक लगाने के लिए ई-वे-बिल का कानून बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ई-वे-बिल पड़ताल अधिकारी छोटी-छोटी गलती को नजरअंदाज करने की अवधारणा के विरुद्ध हैं। अक्सर छोटी-मोटी गलतियां होने पर भी वे व्यापारी पर दंड व शुल्क लगा देते हैं। ई-वे-बिल को आसान बनाया जाना चाहिए।

कंपोजीशन योजना : हाल ही में सेवा प्रदाता के लिए कंपोजीशन योजना का प्रमोचन किया गया था जिसमें कर की दर छह प्रतिशत तक निर्धारित की गई थी। सर्विस प्रोवाइडर के लिए यह दर काफी अधिक है। इस योजना के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवा का उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रावधान के परिवर्तन से सर्विस प्रोवाइडर को भी काफी राहत मिलेगी। जीएसटी का आकलन एक आर्थिक कानून के रूप में किया गया है, न कि अपराध-संबंधी कानून के रूप में। जब तक कर में धोखाधड़ी या हेराफेरी न हो, तब तक जेल के प्रावधान पर पाबंदी होनी चाहिए।

यदि कारोबारी कोई एक रिटर्न नहीं दाखिल कर पाया हो तो उसे अगले माह तक का समय मिलना चाहिए। साथ ही दंड व शुल्क के मौजूदा प्रावधान में भी बदलाव होना चाहिए। केंद्र की नई सरकार के वित्त मंत्री को जीएसटी से जुड़ी इन सभी समस्याओं व कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि कारोबारियों के लिए यह ज्यादा से ज्यादा सुगम हो सके।

कॉरपोरेशन बैंक ने कर्ज दर 0.05 फीसद घटाई

नई दिल्ली : कॉरपोरेशन बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक साल के लिए फंड की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.05 फीसद कटौती की है। अब यह दर 8.85 फीसद रह गई। बैंक ने बीएसई को दी गई जानकारी में कहा कि इसी तरह बैंक ने छह महीने के लिए एमसीएलआर 8.85 से घटाकर 8.80 फीसद कर दिया है। अन्य अवधि के कर्ज के लिए एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। (एजेंसी)

नागरिक विमानन क्षेत्र ने पिछले कुछ समय के दौरान गलतियां की हैं। हम उन गलतियों में सुधार करेंगे और यह सेक्टर जल्द उबरेगा।
— हरदीप सिंह पुरी
नागरिक विमानन मंत्री

सेंसेक्स 39,452.07 ▼ 289.29	निफ्टी 11,823.30 ▼ 90.75	सोना ₹ 33,870 प्रति दस ग्राम ▲ ₹300	चांदी ₹ 38,400 प्रति किलोग्राम ▲ ₹550	$ डॉलर ₹ 69.80 ▲ ₹0.30	क्रूड (ब्रेंट) $ 61.76 प्रति बैरल

राहत ▶ मई में रह गई 2.45 फीसद, निर्यात में भी दर्ज की गई 3.93 फीसद वृद्धि दर

22 महीनों के निचले स्तर पर थोक महंगाई

सब्जियों, ईंधन और बिजली की महंगाई दरों में दर्ज की गई कमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर है। मई में थोक महंगाई दर में गिरावट आई है, जबकि निर्यात बढ़ा है। खाद्य वस्तुओं के दाम में गिरावट के चलते थोक महंगाई दर घटकर मई में 2.45 फीसद रह गई है 22 महीनों का निचला स्तर है। थोक महंगाई दर में गिरावट के बाद एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। मई में निर्यात में 3.93 फीसद की वृद्धि हुई है। हालांकि मई में निर्यात घाटा भी बढ़कर 15.36 अरब डॉलर हो गया है।

थोक महंगाई दर इस साल अप्रैल में 3.07 तथा पिछले साल मई में 4.78 फीसद थी। थोक महंगाई दर का ताजा स्तर जुलाई, 2017 के बाद सबसे कम है। उस समय यह 1.88 फीसद थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मई में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 6.99 फीसद रही जबकि अप्रैल में यह 7.37 फीसद थी। हालांकि मई में प्याज की महंगाई दर बढ़कर 15.89 फीसद हो गई जबकि अप्रैल में यह -3.43 फीसद थी। दलहन की महंगाई दर मई में बढ़कर 18.36 फीसद हो गई है, जबकि अप्रैल में यह 14.32 फीसद थी।

जुलाई, 2017 के बाद मई में सबसे कम रही थोक महंगाई दर। फाइल

सब्जियों के थोक भाव घटे : सब्जियों की महंगाई दर मई में घटकर 33.15 फीसद के स्तर पर आ गई, जबकि अप्रैल में यह 40.65 फीसद थी। आलू की महंगाई दर -23.36 फीसद रही जबकि अप्रैल में यह -17.15 फीसद थी। इसी तरह वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने से ईंधन और बिजली श्रेणी की महंगाई दर घटकर 0.98 फीसद आ गई, जो अप्रैल में 3.84 फीसद थी। मैन्यूफैक्चर्ड आइटम की महंगाई दर भी मई में घटी और यह अप्रैल के 1.72 फीसद से घटकर 1.28 फीसद पर आ गई। इस बीच सरकार ने थोक महंगाई दर का मार्च का आंकड़ा भी 3.18 फीसद से संशोधित कर 3.10 फीसद कर दिया है।

खुदरा महंगाई भी काबू में : दो दिन पहले ही सरकार ने खुदरा महंगाई का आंकड़ा जारी किया था। खुदरा महंगाई दर मई में बढ़कर 3.05 फीसद पर पहुंच गई है जो कि सात माह का उच्च स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) अपनी मौद्रिक नीति तय करते वक्त खुदरा महंगाई को ही संज्ञान में लेता है। छह जून को आरबीआइ ने रेपो दर में कटौती का फैसला किया था। केंद्रीय बैंक ने इस साल फरवरी से लेकर अब तक तीन बार रेपो दर में कटौती की है।

विदेश व्यापार का आंकड़ा भी संतोषजनक : इस बीच सरकार ने विदेश व्यापार के आंकड़े भी जारी किए हैं। केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के बढ़िया प्रदर्शन से मई में निर्यात 3.93 फीसद बढ़कर 30 डॉलर हो गया। इस अवधि में आयात में 4.31 फीसद की वृद्धि हुई और यह 45.33 अरब डॉलर रहा। इस तरह मई में व्यापार घाटा बढ़कर 15.36 अरब डॉलर हो गया। पिछले वर्ष मई में यह 14.62 अरब डालर था। मई में कच्चे तेल का आयात 8.23 फीसद बढ़कर 12.44 अरब डॉलर मूल्य तथा गैर-तेल आयात 2.9 फीसद बढ़कर 32.91 डॉलर मूल्य का रहा। मई में सोने के आयात में 37.43 फीसद की वृद्धि हुई और यह 4.78 अरब डॉलर रहा। कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-मई महीनों में निर्यात में 2.37 फीसद की वृद्धि हुई और यह 56 अरब डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान आयात में 4.39 फीसद वृद्धि हुई और यह 86.75 अरब डॉलर रहा। इस तरह चालू वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों में व्यापार घाटा 30.69 अरब डालर रहा है। निर्यात के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए फियो के प्रेसिडेंट गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि निर्यात वृद्धि की यह दर वैश्विक कारोबार में मामूली वृद्धि के अनुकूल है। हालांकि अमेरिका और चीन में चल रहे कारोबारी युद्ध और ईरान में हो रही गतिविधियां वैश्विक कारोबार की दिक्कतों को और बढ़ा रही हैं।

मारुति सुजुकी ने लांच की बीएस-6 वर्जन वाली वैगनआर

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कंपैक्ट कार मॉडल वैगनआर का बीएस-6 वर्जन लांच किया है। दिल्ली-एनसीआर में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.10 लाख से 5.91 लाख रुपये तक रखी गई है। देश के अन्य हिस्सों में यह कार 5.15 लाख रुपये से 5.96 लाख रुपये तक में मिलेगी। यह कार 1.2 लीटर इंजन क्षमता के साथ लांच की गई है।

▶ दिल्ली में दाम 5.91 लाख रुपये तक होगा दाम, देश के अन्य हिस्सों में 5.96 लाख में मिलेगा

कंपनी ने एक लीटर इंजन क्षमता वाले वैगनआर मॉडल के दाम में भी इजाफा किया है। नई दरों के मुताबिक अब एक लीटर क्षमता वाली वैगनआर की कीमत 4.34 लाख रुपये से 5.33 लाख रुपये तक होगी। इसी क्षमता वाली वैगनआर के लिए अन्य शहरों में ग्राहकों को 4.39 लाख रुपये से 5.38 लाख रुपये तक चुकाने होंगे। बढ़ी दरें शुक्रवार से लागू हो गई हैं।

कंपनी ने कहा कि प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट के पेट्रोल और डीजल वर्जन भी अब एआईएस-145 सुरक्षा मानकों से लैस होंगे। दिल्ली-एनसीआर में स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 5.14 लाख रुपये से 8.89 लाख रुपये तक होगी। एंट्री लेवल की ऑल्टो की सीएनजी वर्जन भी लांच किया गया है। यह दिल्ली में 4.10 लाख से 4.14 लाख रुपये में उपलब्ध होगा।

29 अमेरिकी उत्पादों पर भारत में आयात शुल्क बढ़ने तय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ अमेरिका द्वारा जीएसपी रियायतें वापस लेने के बाद भारत की कार्रवाई

▶ बढ़ी हुई दरें रविवार से होंगी प्रभावी, भारत को होगा 1,500 करोड़ का फायदा

भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर रविवार से आयात शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है। अमेरिका द्वारा पिछले वर्ष स्टील व एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले के बाद भारत ने प्रतिक्रिया के तहत इन अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने का फैसला किया था। लेकिन बाद में इसकी समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई। वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके लिए जल्द अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

अमेरिका से आयातित जिन उत्पादों पर शुल्क में वृद्धि की योजना है, उनमें अखरोट, बादाम और दालें शामिल हैं। आयात शुल्क में वृद्धि के बाद भारत को इनके आयात से 21.70 करोड़ डॉलर (करीब 1,500 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

भारत के इस फैसले से अमेरिकी अखरोट पर आयात शुल्क मौजूदा 30 फीसद से बढ़कर 120 फीसद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चना और मसूर दाल पर शुल्क 30 फीसद से 70 और अन्य दालों पर 40 फीसद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बोरिक एसिड समेत कुछ अन्य रसायनों पर भी आयात शुल्क बढ़ेगा। अमेरिकी सेब, नाशपाती और कुछ स्टील उत्पादों पर भी आयात शुल्क की दर बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने अमेरिका को 47.9 अरब डॉलर का निर्यात किया था। जबकि अमेरिका से आयात 26.7 अरब डॉलर का हुआ।

सूत्र बताते हैं कि भारत ने अमेरिका को आयात शुल्क की दर में वृद्धि करने के अपने इस निर्णय से अवगत करा दिया है। अमेरिका ने पिछले वर्ष मार्च में स्टील पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25 फीसद और एल्यूमीनियम उत्पादों पर 10 फीसद कर दिया था। भारत इन दोनों उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है, इसलिए अमेरिका के इस कदम से उसे सालाना 24 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका ने जीएसपी के तहत भारत को मिल रही कारोबारी रियायतें भी वापस ले लीं। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ही भारत की तरफ से अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क को और नहीं टालने का फैसला किया गया।

भारत को बड़ा फायदा होने की उम्मीद। फाइल

एनडीटीवी मामले में रॉय दंपती पर सेबी ने लगाई पाबंदियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को एनडीटीवी लिमिटेड के तीन मुख्य प्रमोटर्स प्रणय रॉय, राधिका रॉय और उनकी होल्डिंग कंपनी को पूंजी बाजार में प्रवेश करने से दो साल की रोक लगा दी। इसके साथ ही दोनों व्यक्तियों को इस दौरान कंपनी में बोर्ड या शीर्ष प्रबंधन में कोई पद लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया।

▶ प्रणय रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग दो साल तक पूंजी बाजार में नहीं कर सकते प्रवेश

▶ रॉय दंपती दो साल तक कंपनी के बोर्ड या शीर्ष प्रबंधन में कोई पद भी नहीं ले सकते

सेबी के मुताबिक तीनों प्रमोटर्स ने तीन लोन के बारे में अल्पमत शेयरधारकों को अंधेरे में रखकर कई नियमों का उल्लंघन किया था। नियामक ने इस उल्लंघन के लिए रॉय दंपती और आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर सख्त कार्रवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि दंपती एक साल के लिए बाजार में सूचीबद्ध किसी अन्य कंपनी में भी बोर्ड या प्रबंधन में कोई पद नहीं ले सकते हैं। इन तीन लोन में से एक लोन आइसीआइसीआइ बैंक से लिया गया था, जबकि दो लोन विश्वप्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) से लिए गए थे। दिल्ली की थोक व्यापार कंपनी वीसीपीएल की स्थापना 2008 में हुई थी। कथित तौर पर वीसीपीएल का स्वामित्व बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ से नहाटा ग्रुप के हाथ में चला गया। नहाटा ग्रुप से ही अंबानी की कंपनी ने टेलीकॉम कारोबार में फिर से प्रवेश करने के लिए इन्फोटेल ब्रॉडबैंड खरीदी थी।

पिछले साल सेबी ने वीसीपीएल को एनडीटीवी के लिए ओपन ऑफर लाने का आदेश दिया था, क्योंकि वीसीपीएल ने 2009 में 350 करोड़ रुपये के कन्वर्टिबल लोन के जरिये एनडीटीवी की 52 फीसद हिस्सेदारी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह राशि वीसीपीएल ने आरआइएल की एक सहायक कंपनी से ली थी। सेबी के सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं। इन आदेशों में आरआरपीआर, प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर खरीद, बिक्री करने या प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कारोबार करने या प्रतिभूति बाजार से जुड़ने पर रोक भी शामिल हैं।

विमानन मंत्री को जेट मामला सुलझने की उम्मीद

नई दिल्ली, रायटर : नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जेट एयरवेज की समस्याओं का निदान कर लिया जाएगा। संकटग्रस्त विमानन कंपनी के बारे में नई सरकार का यह पहला बयान है। मंत्री ने एक कार्यक्रम के बाद कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। माना जा रहा है कि मंत्री जेट एयरवेज का जिक्र कर रहे थे।

▶ कहा - इस सेक्टर में पहले हुई गलतियों को अब सुधारा जाएगा

▶ जेट एयरवेज के बारे में नई सरकार का यह पहला बयान है

जेट एयरवेज को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में लाने या नहीं लाने पर 20 जून को होगी सुनवाई। फाइल

गौरतलब है कि भारतीय विमानन क्षेत्र कई समस्याओं से गुजर रहा है। पिछले साल एयर इंडिया को बेचने की एक कोशिश विफल हो चुकी है। पुरी ने कहा कि हमने अतीत में नागरिक विमानन क्षेत्र में कुछ गलतियां की हैं, जिन्हें ठीक किए जाने की जरूरत है।

कर्ज नहीं चुका पाने और टिकट की कीमतों पर प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण जेट एयरवेज को अप्रैल में संचालन बंद करना पड़ा था। इसके कारण हजारों कर्मचारी सड़क पर आ गए। विमानन क्षेत्र में किराया आसमान पर पहुंच गया। जेट एयरवेज के लिए खरीदार खोजने की कोशिशें अब तक सफल नहीं हो पाई हैं। कंपनी के कर्मचारी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। चुनाव में जीत मिलने के बाद से सरकार ने मोटे तौर पर इस मामले में चुप्पी साध रखी है।

गौरतलब है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) अगले सप्ताह गुरुवार को जेट एयरवेज के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी के एक मामले की सुनवाई करेगा। जेट एयरवेज के परिचालन कर्जदाता शमन व्हील्स और गग्गर एंटरप्राइजेज ने सोमवार को कंपनी के विरुद्ध एनसीएलटी में याचिका दाखिल की थी और कंपनी पर बैंक्रप्सी प्रक्रिया चलाए जाने की मांग की थी।

एयर इंडिया की 27 सितंबर से अमृतसर-दिल्ली-टोरंटो उड़ान : नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया 27 सितंबर से अमृसर-दिल्ली-टोरंटो उड़ान शुरू करेगी। मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि कंपनी सप्ताह में तीन उड़ानें संचालित करेगी। इसकी शुरुआत 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर होगी।

प्राइवेट ऑपरेटर्स की एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी योजना अटकी

नई दिल्ली : जेट एयरवेज के कर्मचारियों को सुरक्षा से जुड़े कार्य पर बहाल करने की प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की योजना अटक गई है। नागरिक विमानन मंत्रालय मार्च 2019 की अधिसूचना के स्पष्टीकरण पर विचार कर रहा है। अधिसूचना में सुरक्षा से जुड़े कार्यों को सिर्फ विमानन कंपनी के लिए ही आरक्षित किया गया था। एक प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर जेट एयरवेज के कर्मचारियों को बहाल कर विमान सुरक्षा की एक नई कारोबारी इकाई बनाना चाह रहा था। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स अधिसूचना का गलत आशय निकाल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि सिर्फ विमानन कंपनियां ही एयरक्राफ्ट सुरक्षा का काम कर सकती हैं। यदि जरूरत हुआ तो हम इस पर एक स्पष्टीकरण जारी करेंगे।

पारस्परिक आधार पर डाटा आदान-प्रदान को तैयार : प्रसाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइटी और टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा कानून तैयार कर लिया है और यह प्रस्तावित कानून दूसरे देशों में पारस्परिक आधार पर डाटा के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि लोग यूरोपीय डाटा सुरक्षा कानून से संतुष्ट नहीं हैं और वे देख रहे हैं कि भारत में इस पर किस तरह का कानून बनता है।

प्रसाद ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत अपनी डाटा संप्रभुता कायम रखेगा। इस पर समझौता नहीं होगा। भारत एक विशाल देश है। यहां बड़े स्तर पर डाटा का सृजन हो रहा है। मैं मानता हूं कि डिजिटल दुनिया में कुछ हद तक डाटा का आदान-प्रदान जरूरी है, लेकिन वह पारस्परिक और आपसी समझ के आधार पर होगा। व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक-2018 का मसौदा सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण इस समिति के अध्यक्ष थे। भारत पिछले कुछ समय से डाटा के लोकलाइजेशन की वकालत करता रहा है।

स्टील उद्योग से मिलेंगे ओडिशा में रोजगार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ओडिशा के विकास, समृद्धि और वहां रोजगार सृजन में स्टील उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से शुक्रवार को हुई एक मुलाकात में उन्होंने राज्य में स्टील उद्योग के विकास और उसे स्टील के सहायक उद्योग के हब के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा की।

प्रधान ने पटनायक के साथ हुई मुलाकात में राज्य के विकास में केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर काम करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ओडिशा को स्टील उद्योग की सहायक इकाइयों के वैश्विक हब के तौर पर विकसित करना चाहता है। पिछले कुछ समय के दौरान ओडिशा में स्थापित स्टील कंपनियों ने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है। प्रधान ने पटनायक को तूफान से पीड़ित राज्य के विकास और पुनरुद्धार के लिए सेल की तरफ से एकत्र की गई तीन करोड़ रुपये की राशि का एक चेक भी सौंपा।

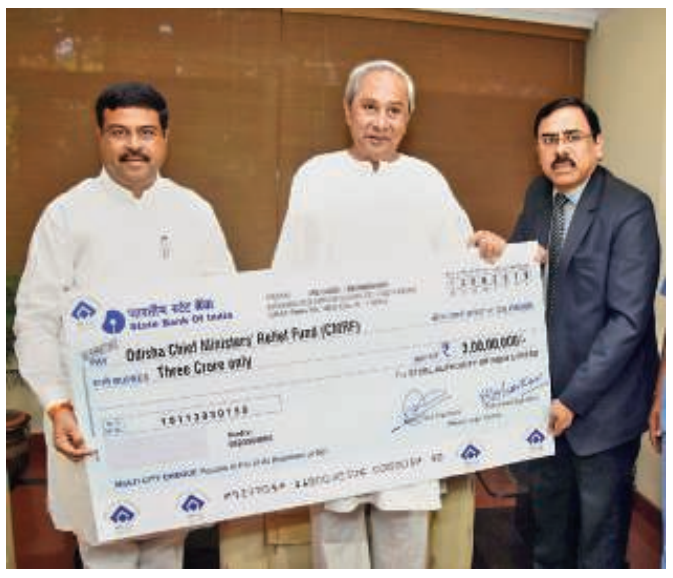

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुलाकात की। इस दौरान प्रधान ने उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए तीन करोड़ रुपये का चेक सौंपा। जागरण

भारत ने पाकिस्तान को छुआरा निर्यात की दी इजाजत

इस्लामाबाद, एएनआइ : भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने पाकिस्तान को अटारी सीमा पर पड़े छुआरे के दोबारा निर्यात करने की इजाजत दे दी है। इस वर्ष फरवरी में कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान आयातित उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 200 फीसद कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान से भारत आ रही वस्तुओं की खेप अटारी चेक पोस्ट पर ही पड़ी रह गई थी। भारत से मिली इजाजत के बाद अटारी सीमा पर पड़ी छुआरे की खेप अब भारत को निर्यात की जा सकेगी।

पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सामानों की यह खेप 16 फरवरी से ही सीमा पर अटकी पड़ी थी, क्योंकि भारतीय निर्यातकों ने सामानों के क्लीयरेंस से इन्कार कर दिया था। पुलवामा हमले के भाद भारत ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा भी छीन लिया।

आइएलएफएस जैसा हो सकता है कई इन्फ्रा कंपनियों का हश्र : पीसीजी रिसर्च

मुंबई, आइएएनएस : इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली उत्पादन और निर्माण क्षेत्र की कई दिग्गज कंपनियों की वित्तीय हालत खराब हो सकती है और उन्हें आइएलएंडएफएस जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पीसीजी रिसर्च की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कंपनियों ने इतना अधिक कर्ज ले रखा है कि कभी भी इन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

▶ इन कंपनियों ने इतना कर्ज ले रखा है कि कभी भी इन्हें कारोबार बंद करना पड़ सकता है

▶ दो गुना का कर्ज-इक्विटी अनुपात सुरक्षित होता है, जबकि इन कंपनियों ने 26 गुना तक कर्ज ले रखा है

रिपोर्ट के मुताबिक केसोराम इंडस्ट्रीज, जेपी एसोसिएट्स, एडलैब्स एंटरटेनमेंट, अशोका बिल्डकॉन, बॉम्बे डाइंग, इमामी रियल्टी और सद्भाव इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों ने इतना कर्ज ले रखा है कि इनका वहन नहीं किया जा सकता है। इन कंपनियों ने 26 गुना से 10 गुना तक कर्ज ले रखा है, जबकि कर्ज-इक्विटी का सुविधाजनक अनुपात स्तर करीब 2:1 है। कर्ज के ऊंचे स्तर के कारण ये कंपनियां डिफॉल्ट कर सकती हैं। इसके कारण उनका कारोबार भी बंद हो सकता है। क्षमता से अधिक कर्ज ले चुकी अन्य प्रमुख कंपनियों में जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर का कर्ज-इक्विटी अनुपात 8.7 गुना, अडानी पावर का 5.52 गुना और अडानी ग्रीन का 5.34 गुना है। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के दीपक जसानी ने कहा कि किसी भी कंपनी की सेहत के लिए 2:1 से अधिक का कर्ज-इक्विटी अनुपात (डी/ई) अच्छा नहीं होता है। यह इस बात का संकेतक है कि कंपनी या तो संकटग्रस्त है या फिर जल्द ही यह संकट में आने वाली है।

रिपोर्ट में ऐसी 51 कंपनियों की सूची जिनका डी/ई 2गुना से अधिक है। इनमें प्रमुखता से उषा मार्टिन, एचसीएल इन्फोसिस्टम, नेटवर्क 18 मीडिया, अंसल प्रोपर्टीज, दिलीप बिल्डकॉन, जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, होटल लीला पैलेस, फोर्ब्स एंड कंपनी भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि आइएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का डी/ई 2017-18 में 6.8 गुना था। इस समूह पर 91,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है और इसकी कई सहायक इकाइयों द्वारा डिफॉल्ट करने के बाद सरकार ने पिछले साल समूह के बोर्ड को हटाकर एक नया बोर्ड गठित कर दिया था। आइएलएंडएफएस समूह का संकट सामने आने के बाद इसका असर कई अन्य कंपनियों पर भी पड़ा है।

फाइल

सुस्ती

सेंसेक्स 289.29 अंकों की गिरावट के साथ 39,452.07 पर बंद, निफ्टी 90.75 अंकों के नुकसान के साथ 11,823.30 पर स्थिर

लगातार तीसरे दिन शेयर बाजारों में गिरावट

मुंबई, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने और ऊंचे भाव पर हुई मुनाफावसूली के कारण देश के शेयर बाजारों में शुकव्रार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 289.29 अंकों की गिरावट के साथ 39,452.07 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 90.75 अंकों की गिरावट के साथ 11,823.30 पर बंद हुआ। सप्ताहभर के कारोबार में सेंसेक्स में 163.83 अंकों और निफ्टी में 47.35 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक में सर्वाधिक 4.36 फीसद गिरावट रही। दूसरी ओर लार्सेन एंड टुब्रो में सर्वाधिक 0.80 फीसद तेजी रही। बीएसई पर जेट एयरवेज 10.77 फीसद गिरकर 82.05 रुपये पर बंद हुआ, जो इसका ऐतिहासिक निचला स्तर है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 4.10 फीसद लुढ़का। अडानी गैस में 3.20 फीसद तेजी रही। कंपनी को लेकर यह चर्चा है कि फ्रांस की कंपनी टोटल एसए इसमें 30 फीसद हिस्सेदारी लेने जा रही है।

सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के रियल्टी सेक्टर में सर्वाधिक 2.11 फीसद गिरावट रही। दूसरी ओर एक मात्र सेक्टर पूंजीगत वस्तु में 0.21 फीसद तेजी रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 1.02 फीसद और स्मॉलकैप में 0.76 फीसद गिरावट रही। चीन में औद्योगिक विकास दर मई में गिरकर 17 वर्षों से अधिक के निचले स्तर पर आ जाने से अंतरराष्ट्रीय विकास को लेकर चिंता बढ़ गई। इसके कारण निवेश के सुरक्षित साधनों की मांग बढ़ गई। दो ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ने और अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण भी बाजार में गिरावट का माहौल रहा। एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में निक्केई में तेजी रही, जबकि शंघाई, हांगकांग और सियोल के बाजारों में गिरावट रही। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुझान देखा गया।

फिलहाल बाजार को नहीं मिल रही दिशा। फाइल

रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस में लगातार गिरावट जारी

नई दिल्ली : बीएसई पर रिलायंस कैपिटल में 9.30 फीसद और रिलायंस होम फाइनेंस में 4.35 फीसद गिरावट रही। पीडब्ल्यूसी ने दोनों कंपनियों के सांविधिक ऑडिटर के रूप में इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद दोनों कंपनियों के शेयरों में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही है। पूंजी बाजार नियामक सेबी और कंपनी मामलों के मंत्रालय ने ऑडिटर के इस्तीफे को गंभीरता से लिया है और शेयर बाजारों को इससे संबंधित सभी जरूरी सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए कहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सेबी, मंत्रालय और शेयर बाजार इस मामले में ऑडिटर और दोनों कंपनियों से अतिरिक्त सूचनाओं की भी मांग कर सकते हैं।

सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ने से सोना 300 रुपये चढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुरक्षित निवेश साधन के रूप में मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 300 रुपये उछलकर 33,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के द्वारा खरीदारी बढ़ाए जाने से चांदी भी 550 रुपये उछलकर 38,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय सराफा बाजार में ज्वेलरों की लिवाली बढ़ने और विदेशी बाजारों के मजबूत रुझानों के कारण सोने के भाव में तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 1,358 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर पहुंच गया, जो अप्रैल 2018 के बाद का सर्वोच्च स्तर है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च प्रमुख हरीश वी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विकास दर घटने की भविष्यवाणी, व्यापार युद्ध से जुड़े तनाव में बढ़ोतरी और अमेरिका में मुख्य नीतिगत ब्याज दर घटने की उम्मीद के कारण निवेशकों ने सोने में पूंजी लगाना सही समझा। आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता के समय आम तौर पर सोने में तेजी दर्ज की जाती है। न्यूयॉर्क में सोने में 1,356.70 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी में 15.11 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 300 रुपये उछलकर 33,870 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही मजबूती के साथ 33,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी 26,700 रुपये प्रत्येक के भाव पर कायम रही। चांदी हाजिर 550 रुपये उछलकर 38,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

वीकली डिलीवरी भी 614 रुपये उछलकर 37,439 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 80,000 रुपये खरीद और 81,000 रुपये बिक्री के स्तर पर कायम रही।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष के लिए पांच जुलाई को आम बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में देश की विकास दर और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी।

सूत्रों का कहना है कि पीएम के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की संभावित बैठक के चलते ही जीएसटी काउंसिल की 20 जून की प्रस्तावित बैठक को एक दिन के लिए टाला गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक अब 21 जून को होगी। पीएम के साथ बैठक में वित्त मंत्रालय के प्रत्येक विभाग के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राजस्व बढ़ाने और विकास दर को ऊपर उठाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। विकास दर वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च, 2019) में घटकर 6.8 फीसद रह गई, जो पांच साल में न्यूनतम है। बैठक में मोदी सरकार के 100 दिनों के एजेंडा पर भी चर्चा हो सकती है।

24 पुलिसकर्मी घायल हो गए अमेरिका के टेनेसी प्रांत के मेंफिस शहर में एक बवाल के दौरान। यहां यूएस मार्शल सर्विस के एजेंट की ओर से चलाई गई गोली से एक अश्वेत की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसक क्षड़पें हुईं।

न्यूज गैलरी

दो लाख डॉलर से ज्यादा में नीलाम हुआ हैंडबैग

लंदन : दुनिया के सबसे महंगे हैंडबैग्स में शुमार हर्मीस बिर्किन का एक हैंडबैग 'क्रिस्टी' की नीलामी में 2,06,111 अमेरिकी डॉलर में बिका। 'द 2015 हिमालय निलोटिकस क्रोकोडाइल बिर्किन 35' की अनुमानित कीमत 88,793 से 1,14,162 डॉलर रखी गई थी। इस नीलामी के साथ ही यह हैंडबैग दुनिया का दूसरा सबसे महंगा हैंडबैग बन गया है। इस नीलामी में 41 देशों से लोगों ने बोली लगाई। इन हैंडबैग्स का नाम अभिनेता और गायक जेन बिर्किन के नाम पर रखा गया है। सबसे महंगे हैंडबैग का रिकॉर्ड भी इसी कंपनी के नाम पर है। (एएनआइ)

विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे दुशांबे, विश्वास बढ़ाने पर चर्चा

दुशांबे : एशिया में आपसी विश्वास बढ़ाने वाले तरीकों पर विचार के लिए हो रहे सम्मेलन में हिस्सा लेने ताजिकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को अपने बांग्लादेशी और बहरीनी समकक्षों से मिले। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन और बहरीन के विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अहमद बिन मुहम्मद अल खलीफा से मिलकर उन्हें शानदार अनुभव हुआ। विश्वास बढ़ाने वाले इस पांचवें सम्मेलन में एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने पर चर्चा होगी। (प्रेट्र)

क्राइस्टचर्च मस्जिद हमले के आरोपी ने जुर्म नहीं कुबूला

वेलिंगटन : न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च मस्जिदों में 51 लोगों की हत्या करने वाले शख्स ब्रेंटन टेरेंट ने अपना जुर्म नहीं कुबूल किया। शुक्रवार को हाई कोर्ट में पेश आरोपित टेरेंट पर हत्या और आतंकवाद समेत 92 मामले हैं। उसने गत 15 मार्च को दो मस्जिदों में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 51 लोगों की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने टेरेंट के खिलाफ ट्रायल अगले साल मई में शुरू करने का आदेश सुनाया। उसकी रिमांड अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई। सुनवाई के दौरान उसे कई बार कुटिल मुस्कान के साथ देखा गया। (रायटर)

ह्वाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स देंगी इस्तीफा

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ह्वाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स इस महीने के अंत में इस्तीफा दे देंगी। ट्रंप ने गुरुवार को एक ट्वीट के जरिये इसकी घोषणा की। ट्वीट में ट्रंप ने कहा, 'वह असाधारण प्रतिभा वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि वे आर्कन्सा प्रांत के गवर्नर पद के लिए खड़ी होंगी।' 36 वर्षीय सैंडर्स ने एक बार कहा था कि यह ईश्वर की मर्जी है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनें। सांडर्स के पिता माइक हुकाबी भी आर्कन्सा प्रांत के गवर्नर रह चुके हैं। (प्रेट्र)

ओमान की खाड़ी में टैंकरों में धमाका ईरान ने कराया : ट्रंप

दी सफाई ▸ ईरान बोला– होर्मुज की सुरक्षा का जिम्मा हमारा

वाशिंगटन, रायटर/एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का ओमान की खाड़ी में दो टैंकरों पर हुए रहस्यमय विस्फोट में हाथ नहीं होने का दावा खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि तेहरान ने ही यह पूरी घटना लिखी थी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। होर्मुज के पास गुरुवार को दो तेल टैंकरों पर हुए हमले में हमारा कोई हाथ नहीं था।

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ जाने के बीच ट्रंप ने तेहरान की पहले दी गई धमकी को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा था कि संघर्ष हुआ तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर देगा। यही समुद्री मार्ग दुनिया में तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। फॉक्स न्यूज टेलीविजन को दिए गए साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'वे इसे बंद नहीं करने जा रहे।' ईरान के सरकारी रेडियो ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसवी के हवाले से कहा, 'जलडमरूमध्य की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमने बहुत थोड़े समय में उन टैंकरों के चालक दल को बचाया। जाहिर तौर पर इस तरह की घटनाओं के लिए ईरान पर आरोप लगाना अमेरिका के लिए सबसे आसान है।

पोंपियो ने दी चेतावनी : अमेरिका ने तेल टैंकरों पर हुए हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी विदेश माइक पोंपियो ने कहा कि इसके ठोस साक्ष्य हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि उनका देश क्षेत्र में तैनात अपने सुरक्षा बलों और सहयोगी देशों की सुरक्षा करेगा। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस घटना को उठाएगा। ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद जारिफ ने कहा, 'अमेरिकी प्रशासन बगैर सच जाने या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के ही ईरान के खिलाफ आरोप लगा रहा है।'

रूस ने जल्द निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी दी

मास्को : रूस ने ओमान की खाड़ी में दो तेल टैंकरों पर हमले का जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर आरोप लगाने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से दूर ही रहना चाहिए। हम हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं भले ही इसके पीछे किसी का हाथ हो।

अमेरिका– ईरान गतिरोध को टालने में विफल रहे एबी

टोक्यो, आइएएनएस : जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध और तनाव टालने में विफल रहे। दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के प्रयास में जापान के प्रधानमंत्री दो दिनों की तेहरान यात्रा पर आए हुए थे। लेकिन ईरान ने मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एबी ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का यह प्रयास इसलिए किया क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों देशों के साथ जापान के दोस्ताना संबंध है। इसी वर्ष जापान और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 90 साल पूरे हुए हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने ईरान के शीर्ष नेताओं से जेल में बंद अमेरिकी कैदियों की रिहाई की अपील की। तेहरान यात्रा के दौरान उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और मुल्क के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात की। एबी के स्वदेश लौटने पर जापान की क्योडो समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अमेरिका–मेक्सिको सीमा के पास मिला भारतीय लड़की का शव

ह्यूस्टन, प्रेट्र : अमेरिकी अधिकारियों को मेक्सिको की सीमा के पास सात साल की एक लड़की का शव मिला है। माना जा रहा है कि यह लड़की भारतीय थी। अधिकारी इसे अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने से जुड़ा मामला मानकर जांच-पड़ताल में जुटे हैं।

अमेरिका की कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) एजेंसी के अनुसार, एरिजोना प्रांत के ल्यूकविले शहर से 27 किलोमीटर दूर यह शव मिला। सीबीपी के गश्ती दल के प्रमुख रॉय विलेरियल ने कहा, 'हमारी संवेदनाएं लड़की के परिवार के साथ हैं। यह बेवजह की मौत उन गिरोहों के कारण हुई लगती है जो अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं।' यह लड़की चार लोगों के साथ यात्रा कर रही थी। मानव तस्करों ने उन्हें सीमा पर छोड़ दिया था और किसी खतरनाक जगह से अमेरिका में दाखिल होने को कहा था। अमेरिकी गश्ती अधिकारियों को भारत की दो महिलाओं से पूछताछ में यह जानकारी मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि वे अमेरिका में कैसे दाखिल हुईं और किस तरह एक महिला और दो बच्चे उनसे बिछड़ गए। अधिकारियों ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेने के बाद लापता लोगों की तलाश शुरू की। कुछ घंटे बाद ही लड़की का शव बरामद किया गया। बाकी लोगों की तलाश में हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। इस दौरान सीबीपी के अधिकारियों को दो लोगों के पैरों के निशान मिले। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस समूह के बाकी दो लोग वापस मेक्सिको की सीमा में चले गए।

असांजे के प्रत्यर्पण का मामला अब 2020 में तय होगा

लंदन, प्रेट्र : विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण से संबंधित सुनवाई को ब्रिटिश कोर्ट ने फरवरी 2020 तक के लिए टाल दिया है। अमेरिका की अर्जी पर हो रही सुनवाई में शुक्रवार को असांजे की लंदन जेल से वीडियो लिंक के जरिये पेशी हुई। अमेरिका ने असांजे पर कंप्यूटर हैक कर गोपनीय दस्तावेज चुराने और उन्हें सार्वजनिक कर राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है।

वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हुई सुनवाई में चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बथनॉट ने आदेश दिया कि असांजे के प्रत्यर्पण से संबंधित सुनवाई 25 फरवरी, 2020 को शुरू होगी और उसे पांच दिन में पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट के इस आदेश से असांजे को अमेरिका को सौंपे जाने का मामला टल गया है। ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जावीद ने बुधवार को असांजे के प्रत्यर्पण आदेश पर दस्तखत कर इस संभावना को हवा दे दी थी कि शुक्रवार की सुनवाई में अगर कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया तो असांजे को अपील का समय न देते हुए उन्हें अमेरिकी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

लंदन की जेल से वीडियो लिंक के जरिये पेश हुए असांजे ने अमेरिका के आरोपों को गलत बताया। कहा कि विकिलीक्स ने किसी कंप्यूटर या वेबसाइट को हैक नहीं किया। वह सिर्फ प्रकाशक है जिसने अपना काम करते हुए जानकारियों को सार्वजनिक किया। असांजे के वकील मार्क समर्स ने कहा, यह पत्रकार के अधिकारों पर हमले का मामला है। अमेरिका अपने कृत्य सार्वजनिक होने से बौखला उठा है और उसने असांजे को गलत मामलों में फंसा दिया है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जिस समय अमेरिका की प्रत्यर्पण संबंधी अर्जी पर सुनवाई हो रही थी उस समय कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में असांजे समर्थक एकत्रित होकर उनके साथ न्याय होने के लिए नारे लगा रहे थे। असांजे जमानत शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लंदन जेल में 50 हफ्तों के कारावास की सजा भुगत रहे हैं। वह फिलहाल बीमार हैं।

अमेरिका की अर्जी पर ब्रिटिश कोर्ट ने दिया फैसला

इससे पहले अमेरिका का पक्ष रखते हुए वकील बेन ब्रैंडन ने कहा, यह अमेरिकी इतिहास का गोपनीय दस्तावेजों की चोरी और उन्हें सार्वजनिक करने का सबसे बड़ा मामला है। यह पूरी साजिश अमेरिका की पूर्व आर्मी इंटेलीजेंस एनालिस्ट चेलिसा मैनिंग के साथ मिलकर असांजे ने रची और उसे अंजाम दिया। मैनिंग ने पूछताछ में पेंटागन के कंप्यूटर का पासवर्ड क्रैक करने की जानकारी दी है। इसके चलते तमाम लोगों को खतरा पैदा हो गया है।

स्विट्जरलैंड में समान वेतन व सम्मान के लिए महिलाओं ने की हड़ताल

जेनेवा, एपी : समान वेतन के लिए हुए पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन के 28 साल बाद स्विट्जरलैंड की महिलाएं फिर आंदोलनरत हैं। शुक्रवार को महिलाओं ने अपना कामकाज छोड़कर हड़ताल की।

लैंगिक समानता, यौन उत्पीड़न और हिंसा की रोकथाम के साथ इस बार महिलाएं 'अधिक समय, अधिक धन और अधिक सम्मान' की मांग कर रही हैं। लुसाने शहर में गुरुवार आधी रात को सैकड़ों महिलाओं ने मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने अपने अंतःवस्त्र जलाकर रोष भी प्रकट किया।

स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार वहां प्रति व्यक्ति आय 76,800 डॉलर (करीब 53 लाख रुपये) है। लेकिन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी कम वेतन मिलता है। कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता से उपजी इसी नाराजगी के कारण देश में फिर महिलाएं आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन में शामिल महिलाएं घरेलू सहायिकाओं, शिक्षिकाओं और देखभाल का काम करने वाली महिलाओं के लिए ज्यादा वेतन की मांग कर रही हैं।

स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में शुक्रवार को हड़ताल के दौरान मार्च निकालतीं महिलाएं। एएफपी

इस आंदोलन को 'पर्पल वेव' कहा जा रहा है क्योंकि अपने प्रदर्शन के लिए महिलाओं ने बैंगनी (पर्पल) रंग चुना है। इससे पहले देश में महिलाओं को मताधिकार मिलने के 20 साल और लैंगिक समानता कानून बनने के दस साल बाद 14 जून, 1991 को महिलाएं असमानता के खिलाफ सड़कों पर उतरी थीं और प्रदर्शन किया था।

डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली प्राइमरी बहस में बिडेन समेत 20 उम्मीदवार

द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन : अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए सांसदों और नेताओं में होड़ लगी थी। इस बार रिकार्ड तोड़ 23 नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए पार्टी में अपनी दावेदारी पेश की थी।

इसी के चलते सबकी निगाहें पहली बहस में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर टिकी हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी (डीएनसी) ने गुरुवार को प्राइमरी बहस के लिए चयनित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। 26 और 27 जून को मियामी में होने वाली इस बहस में पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन समेत 20 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इस बहस में शामिल होने के लिए सभी दावेदारों को अपने लिए 65 हजार लोगों से चंदा इकट्ठा करना था और पिछले दिनों हुए तीन मतदान में एक फीसद समर्थन जुटाना था। चुने गए सभी 20 दावेदार अपने लिए चंदा और समर्थन दोनों ही जुटाने में कामयाब रहे। इन सभी को अब दो समूहों में बांटा जाएगा।

भारतवंशी कमला हैरिस भी शामिल : पहली प्राइमरी बहस के लिए चयनित उम्मीदवारों में भारतवंशी सीनेटर कमला हैरिस का भी नाम शामिल है। इसके अलावा पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड और न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो भी पहली बहस में हिस्सा लेकर अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे।

अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन का फाइल फोटो। एएफपी

बढ़ती जाएंगी चुनौतियां : 2020 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी का नाम तय करने से पहले कई दौर की बहस कराई जाएगी। डीएनसी ने आने वाली प्राइमरी बहस के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। सितंबर में होने वाली तीसरी प्राइमरी बहस में शामिल होने के लिए सभी दावेदारों को अपने लिए कम से कम एक लाख 30 हजार समर्थकों से चंदा जुटाना होगा।

ब्रिटिश पीएम की दौड़ से हटे स्वास्थ्य मंत्री मैट

लंदन, रायटर : ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने प्रधानमंत्री टेरीजा मे का उत्तराधिकारी और सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी का प्रमुख बनने की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। उनके मैदान छोड़ते ही पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन की दावेदारी और मजबूत हो गई है।

पीएम पद का दावेदार चुनने के लिए गुरुवार को पार्टी सांसदों के बीच हुई वोटिंग में 114 मत हासिल कर बोरिस सबसे आगे निकल गए थे। पहले दौर की वोटिंग के बाद दस में से तीन दावेदार बाहर हो गए थे। मैट के हटने के बाद अब मैदान में बोरिस और मौजूदा विदेश मंत्री जेरेमी हंट समेत सिर्फ छह दावेदार बचे हैं। 18, 19 और 20 जून की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री पद के अंतिम दो दावेदार चुन लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की रेस से खुद को बाहर करते हुए मैट ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की समस्या यानी ब्रेक्जिट का हल निकालने वाला उम्मीदवार खोज रही है। ब्रेक्जिट समझौता कराने में असफल रहने के कारण ही टेरीजा ने पिछले माह पीएम पद छोड़ने का एलान कर दिया था। बिना किसी समझौते के भी 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट कराने के अपने बयान के कारण बोरिस विरोधियों के निशाने पर हैं। इस मामले में सार्वजनिक बहस से किनारा करने के लिए जेरेमी ने सवाल खड़े किए हैं।

नेपाल ने अमेरिका से हथियार खरीदने की कानूनी बाधा दूर की

काठमांडू, आइएएनएस : अमेरिका से हथियार खरीदने में आड़े आ रही कानूनी बाधा को नेपाल ने हटा दिया है। नेपाल, अमेरिका से छह हजार से ज्यादा उन्नत राइफलें खरीदने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन तीन किश्तों में भुगतान का कानून अमेरिका के साथ हुए इस सौदे के आड़े आ रहा था। नेपाल की कैबिनेट ने अब एक मुश्त भुगतान की अमेरिका की शर्त को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता बाबू राम गौतम ने इसकी पुष्टि की है।

नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल बिग्यान देव पांडेय ने कहा कि कानूनी बाधा हटने से हथियारों के सौदे में तेजी आएगी। 219 करोड़ रुपये के इस सौदे को लेकर नेपाल में अमेरिकी दूतावास की प्रवक्ता एंड्रिया डी आर्मेंट ने कहा कि भुगतान होते ही हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

माओवादियों से निपटने के लिए नेपाल की सेना को पहली बार 2003 में अमेरिका से एम-16 राइफलें मिली थीं। इसके लिए 2002 में नेपाल की तत्कालीन शेर बहादुर देउबा सरकार ने अमेरिका से 17 हजार राइफलें खरीदने का करार किया था। अब नेपाल फिर से अमेरिका से नए हथियार लेने जा रहा है।

भारत से रक्षा सहयोग की सीमा को तय कर सकता है एस–400 सौदा

- रूसी एयर डिफेंस सिस्टम सौदे पर अमेरिका ने चेताया
- कहा– यह सौदा भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग पर गंभीर असर डाल सकता है
- भारत ने रूस से पांच अरब डॉलर का सौदा 2018 में किया है।

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है लेकिन रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौदे को लेकर उसे आपत्ति है। अमेरिका इस सौदे को भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग में सीमा के तौर पर देख रहा है।

ट्रंप प्रशासन की ओर से यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के उस वक्तव्य के हफ्ते भर बाद आया है जिसमें कहा गया था- एस-400 सौदा भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग पर गंभीर असर डाल सकता है।

एस-400 रूस का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें दुश्मन की मिसाइल या विमान को 400 किलोमीटर दूरी पर ही नष्ट किया जा सकता है। चीन इस सिस्टम की खरीद के लिए 2014 में ही सौदा कर चुका है जबकि भारत ने पांच अरब डॉलर का सौदा 2018 में किया है।

अमेरिकी विदेश विभाग की वरिष्ठ अधिकारी एलिस जी वेल्स ने एशिया मामलों की उप संसदीय समिति को बताया कि हाल के वर्षों में अमेरिका ने भारत के साथ अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास किए हैं। ट्रंप प्रशासन भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। हम भारत के साथ अलग तरह का रक्षा सहयोग करने को तैयार हैं जिसमें उसे बड़े रक्षा सहयोगी के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। भारत को यह दर्जा अमेरिकी संसद ने दिया है। एलिस ने एस-400 की खरीद से अमेरिका के साथ भारत के संबंध पर पड़ने वाले असर के बारे में भी उप समिति को विस्तार से बताया।

अधिकारी ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने अमेरिका, जापान और फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत भेजे थे। हम कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और चतुष्पक्षीय सैन्य सहयोग कर रहे हैं। दस साल पहले अमेरिका जिन हथियारों को देने के बारे में भारत से बात नहीं करता था, उन्हें देने के बारे में आज कर रहा है। अमेरिका भारत के साथ रक्षा सहयोग को विस्तार देना चाहता है। लेकिन एस-400 सिस्टम की खरीद को लेकर हमें गंभीर आपत्ति है।

चुनाव में धांधली की सुनवाई पर जकार्ता में भारी फोर्स तैनात

जकार्ता, एएफपी : इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद पर जोको विडोडो की जीत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को चुनाव में धांधली की शिकायत पर होने वाली सुनवाई के लिए राजधानी जकार्ता को छावनी में तब्दील कर दिया गया।

राष्ट्रपति के चुनाव में 17 अप्रैल को जोको विडोडो को विजयी घोषित किया गया है। उन्हें 55.5 फीसद वोट मिले हैं। इसके बाद से राजधानी जकार्ता में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो अब हिंसक रूप ले चुका है। इसमें आठ लोगों की जान चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 44.5 फीसद वोट पाकर हारे प्रत्याशी पूर्व जनरल प्रोबोवो सुबियांतो ने धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में चुनाव निरस्त करने की याचिका दायर की है, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। पुलिस विभाग के प्रवक्ता डेडी प्रायस्टो का कहना है कि हिंसा की आशंका को देखते हुए 32 हजार पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है। चुनाव कार्यालय के अधिकारियों और चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि सुबियांतो को कोर्ट में हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने 2014 के चुनाव में हार के बाद भी कोर्ट में अपील की थी।

फलस्तीन ने भारतवंशी को शीर्ष सम्मान से नवाजा

भारतीय मूल के शेख मुहम्मद मुनीर अंसारी को 'स्टार ऑफ यरुशलम' मेडल से सम्मानित करते राष्ट्रपति महमौद अब्बास। प्रेट्र

यरुशलम, प्रेट्र : भारत और फलस्तीन के रिश्ते प्रगाढ़ बनाने के लिए फलस्तीन ने भारतवंशी शेख मुहम्मद मुनीर अंसारी को प्रतिष्ठित 'स्टार ऑफ यरुशलम' अवार्ड से नवाजा है। 91 वर्षीय अंसारी के सम्मान में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत और फलस्तीन के नागरिकों के मधुर रिश्तों को और बेहतर करने पर जोर दिया। वर्ष 1928 में फलस्तीन में पैदा हुए अंसारी यरुशलम स्थित एक मध्यकालीन सराय इंडियन हॉसपाइस के निदेशक हैं। यह सराय 12वीं सदी के भारतीय सूफी संत बाबा फरीद से जुड़ी है। कहा जाता है कि यरुशलम की यात्रा के दौरान बाबा फरीद यहीं ठहरे थे। यह सराय यरुशलम जाने वाले भारतीयों के बीच काफी मशहूर है। 1924 में भारत के एक प्रतिनिधि के तौर पर अंसारी के पिता ने सराय की देखरेख शुरू की थी। भारतीय सरकार ने इस इमारत की मरम्मत भी करवाई है। भारत सरकार ने भी 2011 में मुनीर अंसारी को प्रवासी दिवस सम्मान प्रदान किया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स से

दूरदराज वाले इलाकों में आइएस आतंकियों से जूझ रहे अमेरिकी सैनिक, दावा है कि जल्द ही इस आतंकी संगठन का सफाया किया जाएगा

अफगानिस्तान में आइएस बन रहा चुनौती

- तालिबान का सामना कर रहे अमेरिका से सामने आई नई परेशानी
- पूर्वी अफगानिस्तान में यह आतंकी संगठन अपना दबदबा बनाए हुए है

काबुल : अफगानिस्तान में वर्षों से तालिबान से जूझ रहे अमेरिका के लिए अब आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) चुनौती बनता जा रहा है। दो साल पहले अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के अधिकारियों ने कहा था कि अमेरिकी बल अफगानिस्तान के दूरदराज वाले इलाकों में पहुंच गए हैं और जल्द ही आइएस का सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पूर्वी अफगानिस्तान में अमेरिकी बल अब भी आइएस से जूझ रहे हैं।

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार में देह बाला गांव के पास की एक सैन्य चौकी पर पहुंचे न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर को अमेरिकी सैनिकों ने बर्फ से ढके पहाड़ को दिखाते हुए कहा कि इसकी घाटी से आइएस का इलाका शुरू होता है। यहां पर यह आतंकी संगठन बढ़ रहा है। इसे तस्करी और अन्य तरीकों से धन मिल रहा है।

अफगानिस्तान के इस पूर्वी हिस्से में आइएस के आतंकी हमले कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी सेना सिर्फ उन्हें रोके रख सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी और अफगान बल इन पर दबाव बनाए रखने के लिए गश्त कर रहे हैं और छापे मार रहे हैं। इस इलाके में आतंकियों के सफाये में मौसम भी आड़े आ रहा है।

तालिबान से ज्यादा आइएस आतंकियों को भुगतान : अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान के मुकाबले आइएस आतंकियों को हर माह ज्यादा भुगतान होता है। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में आइएस आतंकियों को सैकड़ों डॉलर तक मिल रहे हैं।

अमेरिका–तालिबान में समझौता होने पर आइएस बढ़ा सकता है प्रभाव

अमेरिका के छह मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि अमेरिका और तालिबान के बीच अगर कोई शांति समझौता हो जाता है तो इस्लामिक स्टेट अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान में 18 साल से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए पिछले कुछ माह से अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता चल रही है। हालांकि अब तक इनका सकारात्मक परिणान नहीं आया है। इन अधिकारियों ने यह चिंता भी जताई कि आइएस अफगानिस्तान की सीमा से बाहर भी आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है।

2015 में हुआ उभार

अफगानिस्तान में आइएस आतंकियों का उभार 2015 में उस समय हुआ जब पाकिस्तान तालिबान के कुछ पूर्व आतंकियों ने आइएस सरगना अबू बकर अल-बगदादी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। इसके बाद पूरे अफगानिस्तान में इस आतंकी संगठन का फैलाव हो गया। आइएस का हालांकि अब सीरिया और इराक से सफाया हो गया है। अधिकारियों के अनुसार, अफगानिस्तान में करीब तीन हजार आइएस आतंकियों के होने का अनुमान है।

नेपाल में मुसलमानों ने की सनातन हिंदू संस्कृति के संरक्षण की मांग

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल की काठमांडू घाटी में सैकड़ों वर्षों से रह रहे मुसलमानों ने स्थानीय नेवार समुदाय की सनातन हिंदू संस्कृति के संरक्षण की मांग का समर्थन किया है। दरअसल, सरकार ने सार्वजनिक और निजी न्यासों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिसके बाद से यह मांग की जा रही है।

स्थानीय मुसलमानों के समूह नेवार मुस्लिम सोसाइटी के सदस्यों ने सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति के संरक्षण की मांग को लेकर काठमांडू में निकाली गई रैली में हिस्सा लिया। समूह ने कहा, 'कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से संसद में रखे गए विधेयक को समर्थन मिलता है तो सनातन हिंदू धर्म खतरे में पड़ सकता है।' केपी शर्मा ओली नीत कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने गुथी (न्यास) अधिनियम को संशोधित करते हुए सभी सार्वजनिक और निजी गुथियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इसमें एक शक्तिशाली आयोग के तहत सभी धार्मिक स्थलों को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है।

पाकिस्तान में जरदारी की बहन भी हुई गिरफ्तार

- मामला फर्जी बैंक अकाउंट से धन देश से बाहर भेजने का

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बहन फरयाल तालपुर (61) को भी गिरफ्तार कर लिया। फरयाल की गिरफ्तारी फर्जी बैंक अकाउंट के जरिये धन को गैरकानूनी तरीके से देश से बाहर भेजने के आरोप में की गई है। भाई जरदारी और बहन फरयाल के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज हैं। इन मामलों में 15 करोड़ रुपये का अवैध लेन-देन पकड़ में आया है।

इससे पहले नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो ने सोमवार को जरदारी को गिरफ्तार किया था। जरदारी विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह अध्यक्ष भी हैं। सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरदारी और उनकी बहन फरयाल की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने जरदारी और फरयाल को गिरफ्तार करने की ब्यूरो को अनुमति दे दी थी। आदेश मिलने के कुछ घंटे बाद ही ब्यूरो ने जरदारी को गिरफ्तार कर लिया था। अब भाई और बहन के पास अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार बचा है। ब्यूरो शनिवार को फरयाल को अकाउंटबिलिटी कोर्ट में पेश करके उन्हें रिमांड पर लेने का प्रयास करेगा। रिमांड पर लेकर ब्यूरो उनसे आरोपों के संबंध में पूछताछ करेगा। फरयाल को ब्यूरो के दफ्तर में नहीं लाया गया है। इस्लामाबाद स्थित फरयाल के आवास को ही उप कारागार का दर्जा देकर उन्हें वहीं रखा गया है। डॉक्टरों को उप कारागार में बुलाकर फरयाल के स्वास्थ्य की जांच कराई गई है। जरदारी के बेटे और पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सरकार की मनमानी के आगे पार्टी नहीं झुकेगी। वह पूरे हौसले से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेगी। फरयाल तालपुर को गिरफ्तार कर सरकार ने जता दिया है कि उसकी नजर में महिलाओं की इज्जत नहीं है।

ये भी जानिए
इंग्लैंड की ओर से विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट। रूट के तीन शतक हो गए हैं। उन्होंने केविन पीटरसन को पछाड़ा, जिनके नाम दो शतक हैं।

भारतीय कप्तान विराट कोहली • फाइल फोटो, एएफपी

दांव पर डेढ़ अरब उम्मीदें

दोनों देशों की जनता के जज्बात का मुकाबला है भारत-पाकिस्तान के बीच मैच

विश्व कप में दैनिक जागरण
अभिषेक त्रिपाठी • मैनचेस्टर

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ओवल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से हारने के बाद कहा था कि ये सिर्फ एक मैच है और उसे उसी तरह लेना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई आम क्रिकेट मुकाबला नहीं है। यह दो देशों की डेढ़ अरब जनता के जज्बातों का मुकाबला है और भारतीय टीम को भी यह समझ लेना चाहिए कि भारत के सवा अरब लोग चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं, बल्कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में पाकिस्तान की हार चाहते हैं।

बहुत बड़ा मुकाबला : इन दोनों टीमों की भिड़ंत पर देश की जनता की ही नहीं वहां के हुक्मरानों की भी नजर रही है। 2004 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान जा रही थी तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने कप्तान सौरव गांगुली को एक बल्ला दिया, जिस पर लिखा था खेल ही नहीं दिल भी जीतिए। 2005-06 में विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी के प्रदर्शन से खुश होकर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने उनसे कहा था कि आप कभी ये लंबे बाल मत कटवाएं। हालांकि उसके बाद ही धौनी ने लंबे बालों को छोटा करा लिया था।

टीम इंडिया है मजबूत : इसमें कोई शक नहीं कि इस मैच में विराट की कप्तानी वाली दुनिया की दूसरे नंबर की टीम भारत का पलड़ा भारी रहेगा, जबकि सरफराज के नेतृत्व वाली सातवें नंबर की पाकिस्तानी टीम को संभलकर रहना होगा। भारतीय टीम शुक्रवार को ही मैनचेस्टर पहुंची है, जबकि पाकिस्तान ने यहां इंडोर स्टेडियम में अभ्यास किया। शनिवार को दोनों टीमों की यहां अभ्यास करने की योजना है। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक दो जीत हासिल कर चुका है और बारिश के कारण उसका एक मैच रद हुआ, जबकि पाकिस्तान को एक जीत और दो हार मिली हैं। बारिश के कारण उसे भी एक मैच में अंक बांटने को मजबूर होना पड़ा। शिखर धवन की चोट के कारण भारतीय टीम केएल राहुल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरेगी। तीसरे नंबर पर उसके पास दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज विराट कोहली हैं। मध्य क्रम में केदार जाधव, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक या विजय शंकर मजबूती देंगे। वहीं, पाकिस्तान के पास मध्य क्रम में मुहम्मद हफीज, शोएब मलिक और कप्तान सरफराज अहमद के रूप में अनुभव का भंडार है। टीम के पास इमाम उल हक और फखर जमां जैसे ओपनर हैं। तीसरे नंबर पर बाबर आजम जैसा बल्लेबाज है। ये तीनों इंग्लैंड के खिलाफ चले थे और वही मैच पाकिस्तान जीता था।

भारत के लिए खतरा हैं हफीज और मलिक: इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा बेहतर खेलते हैं। पाकिस्तान के सभी प्रमुख गेंदबाजों का भारत के खिलाफ औसत उनके करियर औसत से भी खराब है। मुहम्मद आमिर का करियर औसत 29.91 है, जबकि भारत के खिलाफ उनका औसत 42.8 है। यानी आमिर भारत के खिलाफ खेलते हुए 42 रन देने के बाद एक विकेट ले पाते हैं। आमिर की ओवरऑल इकोनॉमी 4.78 है, जो भारत के खिलाफ 4.98 हो जाती है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों में मुहम्मद हफीज और शोएब मलिक ही ऐसे हैं, जिनका भारत के खिलाफ औसत उनके करियर औसत से ज्यादा है। इन दो खिलाड़ियों ने अपने ओवरऑल करियर के मुकाबले भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया है। हफीज ने भारत के खिलाफ 11 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 48.6 की औसत के साथ 486 रन बनाए हैं। उनका करियर औसत 33.19 का है। मलिक का करियर औसत 34.71 है, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ खेले 41 मैचों में 48.16 के औसत से 1782 रन बनाए। टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा चार शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी मलिक ही हैं। मलिक और हफीज का टीम इंडिया के खिलाफ स्ट्राइक रेट भी अपने ओवरऑल स्ट्राइक रेट से ज्यादा है।

भुवी रहे हैं पाकिस्तान के लिए खतरनाक: भुवनेश्वर कुमार, मुहम्मद शमी और कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ प्रति ओवर कम रन देते हैं। शमी 3.82, भुवी 4.18 और कुलदीप 4.33 की इकोनॉमी रेट से रन देते हैं। यह उनके ओवरऑल इकोनॉमी रेट से कम है। अगर इस टीम के खिलाफ गेंदबाजी औसत की बात की जाए तो केदार जाधव सबसे बेहतर हैं। पाक के खिलाफ एक विकेट लेने में वह औसतन 17.5 रन खर्च देते हैं, जबकि अन्य टीमों के खिलाफ उनका औसत 35.81 है। शमी का ओवरऑल गेंदबाजी औसत 26.11 है, लेकिन पाक के खिलाफ वह 21.4 रनों के अंतराल में विकेट चटका लेते हैं। भुवी पाक के खिलाफ 23 रन के गेंदबाजी औसत से विकेट लेते हैं, जबकि अन्य टीमों के खिलाफ उनका यह औसत 34.98 है।

धौनी का जवाब नहीं: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 35 मैचों में 55.9 की औसत से 1230 रन बनाए हैं, जबकि उनका करियर औसत 50.53 है। धौनी के 10 में से दो शतक पाकिस्तान के खिलाफ हैं। दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या का भी पाकिस्तान के खिलाफ औसत अपने करियर औसत से बेहतर है। वर्तमान भारतीय टीम में धौनी के अलावा विराट (2) और रोहित (1) ही हैं, जिन्होंने पाक के खिलाफ शतक जड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली का औसत उनके करियर औसत से कम हो जाता है। विराट और धौनी का पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक रेट भी अपने करियर स्ट्राइक रेट से ज्यादा है।

बारिश बन सकती है विलेन

मैनचेस्टर : बारिश के कारण इस विश्व कप में चार मैच बिना फैसले के खत्म हुए। इसमें से भारत और पाकिस्तान के साथ एक-एक बार ऐसा हुआ है। आइसीसी के साथ दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसक दुआ मना रहे हैं कि रविवार को बारिश नहीं हो। हालांकि, यहां के मौसम विभाग की भविष्यवाणी डरा रही। उसके मुताबिक शनिवार और रविवार दोनों दिन बारिश की संभावना है।

टिकटों के लिए मारामारी

मैनचेस्टर : इस मैच की टिकट के दाम रीसेल में एक लाख रुपये तक पहुंच गए हैं। ब्रिटेन में लाखों की संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं। यही नहीं अमेरिका, सिंगापुर और भारत से भी हजारों लोग यह मैच देखने आ रहे हैं। 20 हजार क्षमता वाले ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में होने वाले इस मैच के टिकट विंडो खुलने के कुछ ही घंटों में बिक गए, लेकिन जिन लोगों ने उस समय टिकट खरीदा था, अब वे उन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही लोगों से टिकट लेकर उसे रीसेल करने वाली वेबसाइट वियागोगो के पास करीब 480 टिकट दोबारा बिक्री के लिए आए। ब्रांज से लेकर प्लेटिनम वर्ग के टिकट 17 से 60000 तक में बिके हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलेटी के टिकट एक लाख रुपये से ज्यादा में बिक रहे हैं। अभी तक के मैचों में इस मुकाबले की टिकट ही सबसे ज्यादा महंगी हैं। आइसीसी ने भी भारत-पाकिस्तान मैच की जो टिकट बैलेट के जरिये बेची थीं उनके दाम अन्य मुकाबलों से ज्यादा थे।

भारत की टीम

केएल राहुल – नंबर एक

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
16	380	100*	34.54	1	2

रोहित शर्मा – नंबर दो

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
208	8189	264	48.17	23	42

विराट कोहली – नंबर तीन

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
229	10943	183	59.47	41	50

दिनेश कार्तिक – नंबर चार

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
91	1738	79	31.04	0	9

महेंद्र सिंह धौनी – नंबर पांच

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
343	10561	183*	50.53	10	71

केदार जाधव – नंबर छह

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
61	1174	120	43.48	2	5

हार्दिक पांड्या – नंबर सात

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
47	794	83	30.53	0	4

भुवनेश्वर कुमार– नंबर आठ

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
107	123	5/42	34.98	1

कुलदीप यादव– नंबर नौ

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
46	88	6/25	22.64	1

युजवेंद्रा सिंह चहल – नंबर 10

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
43	78	6/42	24.16	2

जसप्रीत बुमराह – नंबर 11

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
51	90	5/27	21.98	1

मुहम्मद शमी – नंबर 12

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
63	113	4/35	26.11	0

शिखर धवन – नंबर 13

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
130	5480	143	44.91	17	27

रवींद्र जडेजा– नंबर 14

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
151	174	5/36	35.89	1

विजय शंकर – नंबर 15

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
9	165	46	33.00	0	0

पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद, • एएफपी

पाकिस्तान की टीम

इमाम उल हक – नंबर एक

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
31	1486	57.15	6	6	

फखर जमां – नंबर दो

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
39	1700	210*	48.57	4	10

बाबर आजम – तीन नंबर

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
67	2854	125*	50.96	9	13

मुहम्मद हफीज – चार नंबर

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
213	6507	140*	33.19	11	38

सरफराज अहमद – पांच नंबर

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
109	2231	105	34.85	2	11

आसिफ अली – छह नंबर

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
18	361	52	27.76	0	3

शोएब मलिक – नंबर सात

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
286	7534	143	34.71	9	44

वहाब रियाज – नंबर आठ

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
82	106	5/46	34.61	1

हसन अली – नंबर नौ

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
52	81	5/34	28.35	3

शादाब खान– नंबर 10

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
36	49	4/28	27.89	0

मुहम्मद आमिर – नंबर 11

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
54	70	5/30	29.91	1

शाहीन अफरीदी – नंबर 12

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
15	26	4/38	26.26	0

मुहम्मद हसनैन – नंबर 13

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
5	5	2/52	60.60	0

इमाद वसीम – नंबर 14

मैच	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत	5 विकेट
35	39	5/14	19.53	5

हैरिस सोहेल – नंबर 15

मैच	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत	100	50
35	1328	130	45.79	2	10

विवाद भी हुए

जब बीच से हट गई भारतीय टीम

तीन मैचों की सीरीज खेलने 1978 में पाकिस्तान गई थी भारतीय टीम। सभी मैच 40 ओवर के थे। पहला मैच भारत ने चार रन से जीता, दूसरा मैच भारत आठ विकेट से हारा। तीसरा मैच विवादित रहा। साहिवाल में हुए मैच में पाकिस्तान ने सात विकेट पर 205 रन बनाए। भारत 37.4 ओवर में दो विकेट पर 183 रन बना चुका था, लेकिन बिशन सिंह बेदी ने पाकिस्तानी टीम पर अंपायरिंग में बेईमानी का आरोप लगाते हुए अपने बल्लेबाजों को बुला लिया था। तब मैच रेफरी ने पाकिस्तान को जीता हुआ घोषित किया और भारत वह सीरीज 1-2 से हार गया था।

युद्ध बना क्रिकेट का दुश्मन

भारत और पाकिस्तान के बीच खेल संबंध नहीं होने की सबसे बड़ी वजह युद्ध और पाकिस्तान की तरफ से भारत पर कराए जाने वाले आतंकी हमले हैं। पिछली शताब्दी के सातवें दशक में भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना था, लेकिन 1965 और 1961 के युद्ध की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पाया था। 1975 में दोनों मुल्कों ने इस ओर सोचना शुरू हुआ। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और उधर जुल्फीकार भुट्टो की मृत्यु हुई। 1978 में भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया।

भारत ने विश्व कप में हमेशा पाक को हराया

विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत छह बार हुई, जिसमें हर बार हमने पाकिस्तान को पराजित किया। भारत ने अब तक दो बार (1983 और 2011) विश्व कप जीता है, जबकि पाकिस्तान ने 1992 में इमरान खान के नेतृत्व में पहली बार यह खिताब जीता था।

हाथ तक मिलाने से कर दिया था इन्कार

दक्षिण अफ्रीका में हुए 2003 विश्व कप में सेंचुरियन में दोनों टीमों की भिड़ंत हुई। इस दौरान तल्खी इतनी ज्यादा थी कि भारतीय टीम के खिलाड़ी पाकिस्तानियों से हाथ तक नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन कुछ अधिकारियों के बीच में पड़ने के कारण दोनों टीमों को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बेइमानी से बचने के लिए बुलाए इंग्लिश अंपायर

1980 में जब भारत ने फिर पाकिस्तान का दौरा किया, तो पाक के कप्तान इमरान खान ने बेइमानी के आरोपों से बचने के लिए इंग्लैंड से अंपायर बुलवाने की प्रार्थना की, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मान लिया।

> रोहित और विराट टीम के दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान इन दोनों को जल्द आउट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा होगा। आमिर और वहाब रियाज शुरुआत में विकेट लेना चाहेंगे, लेकिन रोहित और विराट को लंबी पारी खेलने पर ध्यान देना चाहिए।
>
> **-सचिन तेंदुलकर**, पूर्व भारतीय बल्लेबाज

> 2003 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ लंच के समय मैं एक टेबल पर और यूसुफ व शोएब अख्तर एक टेबल पर बैठे थे। हम पंजाबी में बात कर रहे थे। यूसुफ ने व्यक्तिगत कमेंट किया और बाद में मेरे धर्म पर बोला। मैंने उसे जवाब दिया। इससे पहले की कोई समझ पाता, हम दोनों के हाथों में कांटे थे और हम एक-दूसरे पर हमला करने को तैयार थे। तब राहुल भाई और जवागल भाई ने मुझे रोका।
>
> **-हरभजन सिंह**, भारतीय ऑफ स्पिनर

> अगर इमरान किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो वह उसे पाने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी के तौर पर रह सकते हैं। वह शांति के लिए पूरे प्रयास करेंगे, सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर ही नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर भी।
>
> **-आसिफ इकबाल**, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान

चोटिल होने से अच्छा मैच नहीं खेलें : कोहली

विशेष संवाददाता, मैनचेस्टर

भारतीय क्रिकेट टीम को रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतिक्षित मैच खेलना है। मैच से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ लंबी बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि अगर मैच बारिश के कारण नहीं होता है और अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ा तो आप क्या करेंगे। कोहली ने कहा कि यह बहुत दुखद होगा कि अगर मैच नहीं हो पाया, लेकिन खिलाड़ियों की सोच से और जहां दोनों टीम खड़ी हैं उस लिहाज से खेलने के लिए बुरी परिस्थितियों में मैच खेलना अच्छा नहीं होगा। यह टूर्नामेंट की शुरुआत है और हम कोई चोट नहीं चाहते हैं। आप मौसम को काबू में नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक अंक मिलना बुरा नहीं है।

इस मैच को लेकर तैयारियां बाधित होने पर कोहली ने कहा कि हमने अच्छा क्रिकेट खेला है। ऐसे में हम चिंतामुक्त हैं। दो जीत से हमे अधिक आत्मविश्वास मिला है। अभ्यास सत्र हमें मानसिक रूप से मजबूत करते हैं। हम मैच के लिए तैयार हैं। बस हम मैदान पर जाना चाहते हैं। उम्मीद है मैच हो पाएगा। भारत-पाकिस्तान के मैच के मायने पर कोहली ने कहा कि जब हम मैदान में घुसते हैं तो शांत माहौल रहता है। उनके लिए यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है जो पहली बार इतना बड़ा मुकाबला खेल रहे होते हैं। हालांकि आप जब भी मैदान में घुसते हो आपको पेशेवर होना पड़ता है। इस मैच के बारे में कोहली ने कहा कि लोगों के पास मैच को रोमांचित बनाने का मौका है, क्योंकि लोग इस मैच को प्यार करते हैं। इतने बड़े मैच का हिस्सा होना सुखद है। शिखर धवन की चोट पर कोहली ने कहा कि उन्होंने प्लास्टर पहना हुआ है और हम देखेंगे कि वह कितना जल्दी ठीक होते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चोट जल्दी ठीक हो और वह जल्द खेलने के लिए उपलब्ध हों। खासकर सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला। वह आत्मविश्वास से भरे हैं और खेलना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि उनका मानसिक तौर पर मजबूत होना उन्हें जल्दी ठीक करने में मदद करेगा।

बल्लेबाजों का इंतजार कर रही पाटा पिच

अभिषेक त्रिपाठी • मैनचेस्टर

ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम की बीच वाली पिच में घास का एक भी तिनका नजर नहीं आ रहा है। इसी में भारत और पाकिस्तान की टीम रविवार को आमने-सामने होंगी। इस विश्व कप में यह इस स्टेडियम का पहला मुकाबला होगा। यह पिच बिलकुल नई और ठोस है। हालांकि बारिश के कारण कवर से ढकी होने की वजह से इसमें थोड़ी नमी होगी, जिस कारण तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। आसमान में छाए बादलों का साथ भी तेज गेंदबाजों को मिलेगा, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज टिक गया तो फिर उसे रन बनाने में मुश्किल नहीं होगी।

ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में अब तक विश्व कप के 11 मैच खेले गए हैं। इस बार इस मैदान पर विश्व कप के छह मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला सेमीफाइनल भी शामिल है। भारत को यहां दो मैच खेलने हैं। रविवार को पाकिस्तान से भिड़ने के बाद टीम इंडिया 27 जून को यहां वेस्टइंडीज का सामना करेगी। इसी मैदान पर 16 जून 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का कम स्कोर वाला मैच खेला गया था, जिसे भारत ने जीता था।

भारतीय खिलाड़ियों को हो रही दिक्कत: आइसीसी ने भारतीय खिलाड़ियों को प्राइवेट जिम में वर्कआउट करने को कहा है क्योंकि वे जिन होटलों में रह रहे हैं, उनमें वर्कआउट करने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। खिलाड़ियों के लिए बुक किए गए होटलों के जिम में उनकी जरूरतों के लिहाज से पर्याप्त मशीनें नहीं हैं और इसीलिए भारतीय खिलाड़ियों को प्राइवेट जिम में वर्कआउट करने के लिए अलग से पास मुहैया कराया गया है। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा कि ब्रिटेन के होटलों में जिम और स्वीमिंग पूल पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। इंग्लैंड को इस मामले में सुधार की जरूरत है। भारतीय टीम के प्रशंसकों और सुरक्षा को देखते हुए भी यह एक अहम मुद्दा है। भारतीय टीम के लिए कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं और इससे टीम प्रबंधन को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके अलावा भारतीय क्रिकेटरों के लिए यात्रा भी एक सिरदर्द रहा है। खिलाड़ियों से बसों में यात्रा करने को कहा जा रहा है, जबकि रेलगाड़ी से यात्रा करने से काफी समय बचता है। इंटरसिटी यात्रा अभी भी बसों में हो रही है, जबकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुटबॉल खिलाड़ी अब समय बचाने के लिए रेलगाड़ी में इंटरसिटी यात्रा करते हैं।

विश्व कप डायरी

धवन ने किया अभ्यास

मैनचेस्टर : भारतीय ओपनर शिखर धवन अंगूठे की चोट के कारण अंतिम एकादश से बाहर चल रहे हैं। हालांकि वह यहां टीम इंडिया के साथ ही हैं और उन्होंने शुक्रवार को अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह पैरों से एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि धवन के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में चोटिल हो गए थे। धवन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आप इन परिस्थितियों को एक बुरा सपना बना सकते हैं या फिर वापसी करने के लिए एक मौका। आप सभी का शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। धवन के अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। बीसीसीआइ और टीम प्रबंधन ने फैसला लिया है कि अगले एक सप्ताह तक धवन टीम के साथ डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, थोड़े समय में उनकी चोट ठीक हो सकती है। हालांकि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते वह अगले कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे।

2010 के बाद से जिन चार क्रिकेट मैचों को सबसे ज्यादा दर्शक मिले, उसमें तीन भारत बनाम पाकिस्तान के थे

2011 विश्व कप फाइनल भारत-श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसे 55.8 करोड़ लोगों ने देखा

2011 विश्व कप का भारत व पाकिस्तान के बीच खेला गया सेमीफाइनल 49.5 करोड़ दर्शकों ने देखा

2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान भिड़े, जिसे 32.4 करोड़ दर्शकों ने देखा

2015 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान भिड़ंत को 31.3 करोड़ दर्शकों ने देखा

131 वनडे भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए। पाकिस्तान ने 73 तो भारत ने 54 मैच जीते। चार मुकाबले परिणाम रहित रहे

05-05 मैच एशिया कप में दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा

पाकिस्तान के कोच और समर्थकों को भी नहीं पता टीम की क्षमता : सुनील गावस्कर

अब पूरे क्रिकेट जगत की नजरें रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले विश्व कप मुकाबले पर लगी हैं। यह मुकाबला कोई भी जीते, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को मजा आने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम काफी मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान ने इस विश्व कप में ही दुनिया की नंबर एक इंग्लैंड टीम को पराजित किया है। दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का भी मानना है कि पाकिस्तान ऐसी टीम है जिसको खुद नहीं पता होता है कि वह मैच के दिन कैसा प्रदर्शन करेगी। विश्व कप और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर हाल ही में **अभिषेक त्रिपाठी** ने **सुनील गावस्कर** से विशेष बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश-

- **यह तो सिर्फ कहने के लिए होता है कि ये भी आम मैचों की तरह है, लेकिन कुछ ऐसे मैच होते हैं जिन्हें आप सिर्फ एक आम मैच नहीं कह सकते हैं।**
- **आज भी उस पल को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि हम विश्व कप जीतेंगे**

साक्षात्कार

- **भारत और पाकिस्तान जब भी क्रिकेट के मैदान में एक-साथ उतरते हैं तो वह खास होता है। 2017 में इंग्लैंड में ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब भारत को शिकस्त मिली तो मैदान का माहौल काफी गर्म था। क्या आपको लगता है कि भारत-पाक मैचों को सिर्फ आम मैचों की तरह लिया जा सकता है?**

-आखिरकार यह भी एक मैच ही होता है, लेकिन मैदान पर जो तनाव होता है, जो दबाव बनता है उसे आप नकार नहीं सकते। इन दोनों देशों के बीच मुकाबले से पहले आप तनाव या दबाव दूर करने के लिए चाहे हेडफोन पर कितने भी अच्छे गाने क्यों ना सुन लीजिए, लेकिन वह दबाव आपके ऊपर रहता ही है। अगर यह फाइनल मुकाबला हो तो फिर और दवाब बढ़ना स्वभाविक है। यह तो सिर्फ कहने के लिए होता है कि यह भी आम मैचों की तरह है, लेकिन कुछ ऐसे मैच होते हैं जिन्हें आप सिर्फ एक आम मैच नहीं कह सकते हैं। भारत-पाकिस्तान मुकाबला उनमें से ही एक है। यही नहीं, अगर टीम विश्व कप का फाइनल खेल रही है, तो ऐसे में उसके सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या वेस्टइंडीज, वह एक आम मैच नहीं होगा। ऐसा ही पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर है, इसीलिए लोग कहते हैं कि हमने अगर पाकिस्तान को हरा लिया और अगर चैंपियनशिप नहीं भी जीती, तब भी कोई परेशानी नहीं है।

- **पाकिस्तान की मौजूदा टीम को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार वह विश्व कप में भारत को हराने की अपनी कसर पूरी कर पाएगा?**

-देखिए, पाकिस्तान की जो क्षमता है, वह खुद उसे नहीं जानता। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के कोच और उसके समर्थकों को भी नहीं पता चलता है कि उन्हें अपनी टीम की ओर से एक चैंपियन टीम वाला प्रदर्शन देखने को मिलेगा या फिर एक क्लब स्तर की टीम वाला प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में कोई टीम है कि जिसके आज और कल के प्रदर्शन में जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिल सकता है, तो वह पाकिस्तान की है। जब पाकिस्तान का प्रदर्शन आसमान वाली टीम का है तो वह किसी भी टीम को हरा सकरी है, लेकिन अगर जमीन वाली टीम जैसा प्रदर्शन है तो उसे कोई भी टीम हरा सकती है।

- **पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था जिसे इंग्लैंड में बसे पाकिस्तानी समर्थक एक बदलाव के तौर पर देख रहे थे। ऐसे में क्या उस जीत का मनोवैज्ञानिक लाभ पाकिस्तान को इस विश्व कप में मिलेगा?**

-पाकिस्तान के कोच, उसका सपोर्ट स्टाफ और कप्तान सभी ऐसा ही कहेंगे। ये सभी यही कहेंगे कि देखो हमने भारत को हराया था, लेकिन जो लोग क्रिकेट को नजदीक से देखते हैं उन्हें पता है कि उससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत, पाकिस्तान से हार चुका था, लेकिन हमारी टीम विश्व कप में आज तक नहीं हारी है। भारतीय टीम को यही याद रखना होगा। जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ वह ठीक है क्योंकि वह पहले भी हो चुका था, लेकिन विश्व कप में अब तक भारत नहीं हारा है।

- **आप कपिल देव की कप्तानी में चैंपियन बनी भारतीय टीम के गवाह रहे। आपने धौनी को मुंबई में विश्व कप की ट्रॉफी उठाते देखा और अब विराट कुछ वैसी ही सोच के साथ इंग्लैंड गए हैं। इन तीनों कप्तानों को आप कैसे आंकते हैं?**

-स्वभाव के हिसाब से आप कह सकते हैं कि कपिल देव और एमएस धौनी एक जैसे हैं। दोनों बेहद शांत और आगे बढ़कर टीम की अगुआई करने वाले। वैसे विराट भी आगे बढ़कर टीम को संभालते हैं, लेकिन वह कभी-कभी कुछ ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हालांकि उनके पास वह काबिलियत है कि अगर भारत के हाथों से मुकाबला निकल रहा हो तो वह अपनी बल्लेबाजी से उसे भारत की ओर मोड़ सकते हैं। यह विराट की सबसे खास काबिलियत है। जैसे कपिल देव को जिम्मी अमरनाथ और सैयद किरमानी जैसे खिलाड़ी खूब मदद करते थे, वैसे ही विराट के पास धौनी हैं। इससे टीम में बहुत फर्क पड़ता है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से कपिल ने लॉर्ड्स की बालकनी में विश्व कप ट्रॉफी उठाई थी, वैसे ही विराट भी उठाएंगे।

- **इंग्लैंड में विश्व कप जीतने का पल आज भी आपको कितना रोमांचित करता है?**

-आज भी उस पल को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि हम विश्व कप जीतेंगे, लेकिन हमारी टीम ने पहले मैच के बाद विश्व कप जीतने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। विश्व कप के शुरू होने से पहले हमें आशा थी कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन फाइनल तक पहुंचेंगे, इसका हमें विश्वास नहीं था। पहले मैच में जब हमने वेस्टइंडीज को अच्छे रनों के अंतर से हराया, तभी हमें लग गया कि हम कुछ खास कर सकते हैं और बिलकुल वैसा ही हुआ

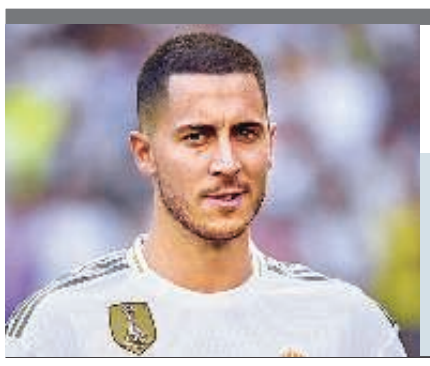

भारत में काम करने का मौका मिलना विशेष था। मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। सौरव गांगुली और मेरे लिए शुरुआत कठिन थी। वो नए कप्तान थे और मैं विदेशी कोच।
–जॉन राइट, भारत के पूर्व कोच

आधिकारिक रूप से रीयल से जुड़े हेजार्ड

मैड्रिड, आइएएनएस : बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर ईडन हेजार्ड आधिकारिक रूप से स्पेनिश क्लब रीयल मैड्रिड से जुड़ गए हैं। रीयल के घरेलू मैदान सेंटियागो बर्नब्यू में हजारों प्रशंसकों के बीच हेजार्ड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे पहले उन्होंने मेडिकल चेक-अप में हिस्सा लिया। हेजार्ड की उपस्थिति के अब एकबार फिर गैलेक्टिकोज टीम की उम्मीद की जा रही है।

मुकाबला ▸ इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को दी आठ विकेट से करारी शिकस्त, रूट का शतक, आर्चर व वुड ने झटके तीन-तीन विकेट

अंग्रेजों के आगे फीके पड़े कैरेबियाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर वेस्टइंडीज टीम गुरुवार को साउथैंप्टन में विश्व कप के अपने चौथे मैच में इंग्लैंड के सामने फीकी पड़ गई। द रोज बाउल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने विंडीज टीम को खेल के हर क्षेत्र में पछाड़ते हुए आठ विकेट से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर विंडीज को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और उसे 44.4 ओवरों में 212 रनों पर ही समेट दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 33.1 ओवर में दो विकेट पर 213 रन बनाकर आठ विकेट से जीत दर्ज की।

213 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। जॉनी बेयरस्टो (45) और जो रूट (नाबाद 100) ने पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी करके विंडीज गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद बेयरस्टो को शेनॉन गेब्रियल ने आउट कर दिया। बेयरस्टो के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए क्रिस वोक्स ने 40 रन बनाए और रूट के साथ दूसरे विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी करके टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। 199 के स्कोर पर वोक्स को गेब्रियल ने ही पवेलियन भेजा। इस बीच रूट ने इस विश्व कप में दूसरा शतक लगाकर अपनी टीम को आठ विकेट से जीत दिला दी। रूट ने 94 गेंद में 11 चौके लगाए। इससे पहले, विंडीज निकोलस पूरन के 63 रनों के बावजूद 44.4 ओवर में 212 रनों पर पवेलियन लौट गई। पूरन ने 78 गेंदों का सामना किया और तीन चौकों के अलावा एक छक्का लगाया। पारी की शुरुआत में क्रिस वोक्स ने इविन लुइस (02) को पैर नहीं जमाने दिए। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लुइस चार रन के टीम स्कोर पर पवेलियन लौट लिए। शाई होप (11) और क्रिस गेल (36) ने टीम को 50 के पार पहुंचा। टीम का स्कोर 54 था तभी लियाम प्लंकेट ने गेल को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच कराया। एक रन बाद होप, मार्क वुड की गेंद पर चलते बने।

विंडीज को संकट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी पूरन और शिमरोन हेटमायर (39) ने ली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी कर विंडीज को अच्छे स्कोर के रास्ते पर बनाए रखा। इसके बाद जो रूट ने शानदार गेंदबाजी की। हेटमायर, रूट को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे। रूट विंडीज के कप्तान जेसन होल्डर (09) का विकेट लेने में भी सफल रहे। इंग्लैंड के सामने अब आंद्रे रसेल की चुनौती थी जिसे वुड ने खत्म कर दिया। रसेल 16 गेंदों पर एक चौके और दो छक्के के साथ 21 रन बनाकर वुड की गेंद पर वोक्स को कैच देकर पवेलियन लौट लिए। इसके बाद विंडीज की टीम के निचले क्रम को जोफ्रा आर्चर ने धराशायी कर दिया।

शिमरोन हेटमायर का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते इंग्लैंड के जो रूट। एपी

स्कोर बोर्ड

टॉस : इंग्लैंड (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : जो रूट

वेस्टइंडीज — 212 (44.4 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
क्रिस गेल का. बेयरस्टो बो. प्लंकेट	36	41	05	01
इविन लुइस बो. वोक्स	02	08	00	00
शाई होप एलबीडब्ल्यू बो. वुड	11	30	01	00
निकोलस पूरन का. बटलर बो. आर्चर	63	78	03	01
शिमरोन हेटमायर का. एवं बो. रूट	39	48	04	00
जेसन होल्डर का. एवं बो. रूट	09	10	00	01
आंद्रे रसेल का. वोक्स बो. वुड	21	16	01	02
कार्लोस ब्रेथवेट का. बटलर बो. आर्चर	14	22	00	01
शेल्डन कॉटरेल एलबीडब्ल्यू बो. आर्चर	00	01	00	00
ओशाने थॉमस नाबाद	00	11	00	00
शेनॉन गेब्रियल बो. वुड	00	03	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-5, वा-12) 17
कुल : 44.4 ओवर में 212 रन पर ऑलआउट

विकेट पतन : 1-4 (लुइस, 2.6), 2-54 (गेल, 12.6), 3-55 (होप, 13.2), 4-144 (हेटमायर, 29.5), 5-156 (होल्डर, 31.6), 6-188 (रसेल, 36.2), 7-202 (पूरन, 39.4), 8-202 (कॉटरेल, 39.5), 9-211 (ब्रेथवेट, 43.4)

गेंदबाजी :
क्रिस वोक्स 5-2-16-1
जोफ्रा आर्चर 9-1-30-3
लियाम प्लंकेट 5-0-30-1
मार्क वुड 6.4-0-18-3
बेन स्टोक्स 4-0-25-0
आदिल राशिद 10-0-61-0
जो रूट 5-0-27-2

इंग्लैंड — 213/2 (33.1 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
जॉनी बेयरस्टो का. ब्रेथवेट बो. गेब्रियल	45	46	07	00
जो रूट नाबाद	100	94	11	00
वोक्स का. सब (एलेन) बो. गेब्रियल	40	54	04	00
बेन स्टोक्स नाबाद	10	06	02	00

अतिरिक्त : (लेबा-2, नोबा-1 वा-15) 18
कुल : 33.1 ओवर में दो विकेट पर 213 रन
विकेट पतन : 1-95 (बेयरस्टो, 14.4), 2-199 (वोक्स, 31.5)

गेंदबाजी :
शेल्डन कॉटरेल 3-0-17-0
ओशाने थॉमस 6-0-43-0
शेनॉन गेब्रियल 7-0-49-2
आंद्रे रसेल 2-0-14-0
जेसन होल्डर 5.1-0-31-0
कार्लोस ब्रेथवेट 5-0-35-0
क्रिस गेल 5-0-22-0

परिणाम : इंग्लैंड आठ विकेट से जीता

सचिन ने बल्ले बनाने वाली कंपनी स्पार्टन पर किया केस

मेलबर्न, प्रेट्र : दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बल्ले बनाने वाली कंपनी स्पार्टन पर 20 लाख डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) नहीं देने पर मामला दर्ज कराया है। सचिन ने ऑस्ट्रेलियाई अदालत में केस दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने सिडनी स्थित कंपनी पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने उन्हें वो रकम नहीं दी है। इस मामले की सुनवाई 26 जून को सिडनी की अदालत में होनी है।

सचिन, फाइल फोटो

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, तेंदुलकर के वकील ने एक अदालत में दस्तावेज दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पार्टन स्पोर्ट्स इंटरनेशनल ने तेंदुलकर को बकाया राशि नहीं दी है और सितंबर-2018 से 20 लाख डॉलर की राशि बकाया है। तेंदुलकर और कंपनी के बीच जुलाई 2016 में एक करार हुआ था जिसके तहत कंपनी हर साल सचिन को 10 लाख डॉलर (करीब सात करोड़ रुपये) देने वाली थी जिसके बदले में वह सचिन की फोटो अपनी उत्पाद बेचने के लिए उपयोग करना चाहती थी। सितंबर-2018 में सचिन ने कंपनी के साथ करार खत्म कर दिया और कंपनी से अपनी फोटो का उपयोग करने को मना कर दिया था। सचिन के वकील ने कहा है कि इसके बावजूद कंपनी ने उनकी फोटो का इस्तेमाल किया।

मेराडोना ने मैनेजर के पद से दिया इस्तीफा

मेक्सिको सिटी, एएफपी : महान फुटबॉलर डिएगो मेराडोना ने स्वास्थ कारणों से मेक्सिको के फुटबॉल क्लब डोराडोस के मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उनके वकील ने दी। मेराडोना का मेक्सिको के दोयम दर्ज के क्लब डोराडोस के साथ नौ महीने का कार्यकाल उतार-चढ़ाव भरा रहा।

उनके वकील ने ट्विटर पर लिखा कि 58 वर्षीय मेराडोना ने डोराडोस के मैनेजर के पद पर नहीं बने रहने का फैसला किया है। डॉक्टर के सुझाव के बाद वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और अपने कंधे और घुटने के दो ऑपरेशन कराएंगे। हम डोराडोस के पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं और भविष्य में हम एक साथ अपने सपने को पूरा करने की कोशिश जारी रखेंगे।

अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी मेराडोना पिछले साल सितंबर में डोराडोस से जुड़े थे। तब सवाल उठ रहे थे कि आखिर उन्होंने फुटबॉल से ज्यादा

फुटबॉल डायरी

- स्वास्थ्य कारणों से छोड़ा मेक्सिकन क्लब का साथ
- नौ महीने के कार्यकाल में नहीं जिता पाए कोई खिताब

ड्रग्स के लिए मशहूर जगह के क्लब को कोचिंग देने का फैसला क्यों किया। हालांकि उन्होंने अपने क्लब को लगातार दो टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचाकर सबका मुंह बंद कर दिया। हालांकि वह डोराडोस को खिताब नहीं दिला सके, जिससे उनका क्लब फर्स्ट डिविजन टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका। मेराडोना के क्लब छोड़ने के फैसले का स्वागत करते हुए डोराडोस ने भी उनको धन्यवाद किया। मेराडोना का क्लब के साथ सफर कुछ खास नहीं रह पाया था।

नेमार के बारे में होती है ज्यादा चर्चा : टिटे

लीड्स, एएनआइ : ब्राजील के कोच टिटे ने कहा कि नेमार के बारे में मीडिया में ज्यादा चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि टीम में जितनी बात उनके बारे में नहीं चलती उससे कहीं ज्यादा उनके बारे में मीडिया में चर्चा होती है। टीम में हमारा ध्यान सिर्फ तैयारियों पर केंद्रित होता है। मैं कभी नेमार जैसे खिलाड़ी के बगैर खेलने वाली स्थिति में नहीं रहना चाहूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कोपा अमेरिका कप में ब्राजील की टीम नेमार के बगैर अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जो चोट की वजह से वह टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। उधर, ब्राजील पुलिस ने गुरुवार को नेमार से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की।

पहली जीत चाहेंगे दक्षिण अफ्रीका व अफगानिस्तान

कार्डिफ, प्रेट्र : विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें शनिवार को कार्डिफ में एक-दूसरे से लोहा लेने उतरेंगी। अंक तालिका में आखिरी दो पायदान पर मौजूदा इन दोनों टीमों के लिए यह इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने का सबसे अच्छा मौका होगा।

संभवतः यह पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीकी टीम शुरुआत से ही विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदारों में शामिल नहीं है, लेकिन उसका चार मैचों में एक भी जीत नहीं दर्ज कर पाना किसी को पच नहीं रहा है। इंग्लैंड, बांग्लादेश और भारत के खिलाफ लगातार तीन मुकाबलों में हार के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ उसका मुकाबला बारिश की वजह से रद हुआ था। अफगानिस्तान का भी कमो-बेस यही हाल है जिसे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले अपने तीनों मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी है। अनुभवहीन बल्लेबाजी लाइन-अप वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपने कई खिलाड़ियों के चोटिल होने की समस्या से भी दो-चार होना पड़ा है। उसके बल्लेबाज पूरी तरह से संघर्ष करते नजर आए हैं और यहां तक कि वेस्टइंडीज के खिलाफ बारिश से रद हुए मुकाबले में भी उसके दो विकेट 29 रनों पर गिर गए थे। हाशिम अमला अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान फाफ डुप्लेसिस और क्विंटन डिकॉक जैसे बल्लेबाजों के कंधों पर बल्लेबाजी का दारोमदार होगा। वहीं अफगानिस्तान के लिए भी बल्लेबाजी प्रमुख समस्या है।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस। एपी

श्रीलंका का सामना आज ऑस्ट्रेलिया से

लंदन, प्रेट्र : बारिश की वजह से दो मैच धुलने के बाद श्रीलंका की टीम जब शनिवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी तो वह इस मैच में अपना सब कुछ झोक देना चाहेगी। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया की गहराई को भेद पाना उसके लिए काफी मुश्किल चुनौती होगी। श्रीलंका ने चार जून के बाद से विश्व कप का कोई भी मैच नहीं खेला है। उसे बारिश की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दो मुकाबलों में अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ा। 1996 में खिताब जीतने वाली उपमहाद्वीप की यह टीम चार मैचों में एक जीत के साथ तालिका में पांचवें स्थान पर है। उसे एकमात्र जीत बारिश से प्रभावित अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में मिली। दूसरी ओर, गत विजेता ऑस्ट्रेलिया को रोक पाना दूसरी टीमों के लिए अब तक मुश्किल साबित हुआ है। उसे अब तक खेले चार मैचों में से इकलौती हार भारत के खिलाफ मिली है। अब तक एक शतक और दो अर्धशतक लगाने वाले डेविड वार्नर बेहतरीन फॉर्म में हैं। बेशक वार्नर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं लेकिन पाक के खिलाफ उन्होंने 111 गेंदों पर 107 रन बनाए थे।

विविध

ई-कचरे के निस्तारण की कारगर युक्ति पर जोर

केंद्र सरकार की पहल पर एनएमएल, जमशेदपुर ने विकसित की पर्यावरण हितैषी तकनीक

विकास श्रीवास्तव, जमशेदपुर

केंद्र सरकार की पहल पर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर (झारखंड) ने ई-कचरा निस्तारण की पर्यावरण हितैषी तकनीक विकसित की है, जिसे हाथोंहाथ लिया जा रहा है। अनेक उद्यमियों ने इसमें रुचि दिखाई है। दरअसल, इस तरह की कारगर व्यवस्था के अभाव में पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। ई-कचरे को जलाकर इसमें से बहुमूल्य धातु निकालने की लालच भी बड़ी वजह है, जिस पर रोक लगना आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण

इस दिशा में एनएमएल के वैज्ञानिकों की यह कोशिश सार्थक साबित हो सकती है। पुराने कंप्यूटर, टीवी सेट, मोबाइल फोन, की-बोर्ड, माउस, टेलीफोन सेट, माइक्रोचिप, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कबाड़ चुनौती बन रहा है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने इसके निस्तारण का जो तरीका खोजा है, वह पर्यावरण हितैषी तो है ही, उद्यमियों के लिए किफायती भी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोना, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, नियोडाइमियम, लेंथेहम, टेरबियम, यीट्रियम, इंडियम, लीथियम, निकेल जैसी महंगी धातुओं लगी होती हैं, जिन्हें निस्तारण के बाद सहेजा जा सकता है। आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले इस प्रोजेक्ट की सफलता के चर्चे फैले तो उद्योगपतियों और कारोबारियों का ध्यान भी इस ओर गया। अब यहां कई कारोबारियों ने इस तकनीक के आधार पर ई-कचरा निष्पादन उद्योग लगाने में रुचि दिखाई है। एनएमएल परिसर में बने अर्बन ओर रीसाइकिलिंग सेंटर में इसके बारे में सभी आवश्यक व प्रायोगिक जानकारी दी जा रही है। मकसद है कि लोग छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयां लगाकर न केवल धनोपार्जन करें, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान भी करें। ई-कचरा निष्पादन पर काम करने वाले एनएमएल के वैज्ञानिक मनीष कुमार झा के अनुसार एनएमएल का अर्बन ओर रीसाइकिलिंग सेंटर पूर्वी भारत में इस तरह का पहला प्रयास है। इससे पहले दक्षिण भारत में ई-कचरे के निस्तारण की पहल की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि ई-कबाड़ को सबसे पहले निम्न तापमान पर जलाया जाता है, लेकिन इस युक्ति में सभी कार्बनिक सामग्री गैस में परिवर्तित हो जाती है और बाहर निकलने की जगह अंदर ही एक पाइपनुमा उपकरण में जमा हो जाती है। इससे प्रदूषण नहीं होता, बल्कि इसे ठंडा कर फ्यूल ऑयल (ईंधन तेल) बनाया जाता है। बची हुई धातु को प्रसंस्करण की विविध तकनीकों की सहायता से अलग किया जाता है।

1000 किलो मोबाइल सेट से निकलता है 350 ग्राम सोना : एनएमएल के प्रिंसिपल साइंटिस्ट मनीष कुमार झा के अनुसार इन उपकरणों में सोना अलग-अलग धातुओं जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम के ऊपर लेपित रहता है, जिसे खास प्रक्रिया से अलग कर निकाल लिया जाता है। 1000 किलोग्राम वजन के मोबाइल फोन के कबाड़ से लगभग 350 ग्राम सोना का उत्पादन संभव है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला द्वारा विकसित तकनीक से शुद्ध सोना प्राप्त होता है। इसी तरह, मोबाइल फोन की बैटरी से कोबाल्ट कोबाल्ट, लीथियम, निकेल जैसी धातुओं का पर्यावरण हितैषी निष्कर्षण संभव हो सका है।

एनएमएल जमशेदपुर के अर्बन और रीसाइकिलिंग सेंटर में निस्तारण के लिए जमा ई-कचरा। जागरण

बड़ी मुसीबत बन चुका है ई-कचरा

भारत में 120 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से ई-कचरे का ढेर लग रहा है। यह कचरा घर-घर और गली-गली में फैला है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके खतरों से अनजान हैं। जलाने से यह ई कचरा 38 प्रकार की खतरनाक रासायनिक गैस उत्सर्जित करता है और कई बार बड़ी मुसीबत की भी वजह बनता है। देश में कैंसर सहित कई अज्ञात बीमारियों की यह एक वजह ई-कचरा भी है। जागरूकता की कमी से लोग ई-कचरा कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। ऐसा करना भी पर्यावरण के लिए खतरनाक है। नई तकनीक इन सबका समाधान लेकर आई है।

पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से एनएमएल जमशेदपुर को पांच करोड़ रुपये दिए गए थे। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अब सरकार इसके विस्तार के लिए एनएमएल को 15 करोड़ रुपये और देने जा रही है।
– मनीष कुमार झा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, एनएमएल, जमशेदपुर

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

12 साल के बेटे को चौकी में बैठाया...

यशपाल वर्मा, करनाल

- आपातकाल के दौरान किए गए संघर्ष और झेली गई यातनाओं की बात कर भावुक हो जाते हैं लोग
- करनाल के आत्मप्रकाश और पानीपत के गर्ग परिवार ने सुनाई आपबीती, रो पड़े आत्मप्रकाश

ईश्वर सबका भला करे, कहकर आत्मप्रकाश की आंखें नम हो उठीं। वे उस दौर की कड़वी यादों में खो गए, जब देश में आपातकाल लगा था। उन्होंने और उनके परिवार ने जो यातनाएं झेलीं, वे यादें आज भी उन्हें विचलित कर देती हैं। करनाल, हरियाणा निवासी आत्मप्रकाश से जब हमने तकलीफों के बारे में पूछा, तो आंखों से बहने वाले आंसू पूरी कहानी कह गए। बोले, तकलीफों के मंजर को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। किसी पर आरोप भी लगाना गलत है।

आत्मप्रकाश ने बताया, मैं किसी जरूरी काम से चंडीगढ़ गया था। मुझे नहीं पता था कि पुलिस मुझे तलाश कर रही थी। पुलिस वाले मेरे घर पहुंचे। घर में जब मैं नहीं मिला, तो सदर पुलिस कर्मचारी मेरे 12 वर्षीय बेटे गुलशन को उठाकर ले गए। पुलिस कर्मचारियों ने परिवार को चेताया कि जब आत्मप्रकाश आ जाएंगे तो बेटे को छोड़ देंगे। पुलिस ने बच्चे को पूरे दिन चौकी में बैठाए रखा...। उस दौर की याद करते हुए आत्मप्रकाश बताते हैं कि वह तब अखबार बांटने का काम करते थे। साथ ही संघ की विचारधारा को अपनाए हुए थे। आपातकाल के मंजर को याद करते-करते आत्मप्रकाश भावुक हो गए और चुप्पी साध ली। फिर पूछने पर बोले, ईश्वर सब का भला करे...। ऐसे दिन किसी भी देश में न आएं, जिसमें लोगों को जबरन उठाकर जेलों में ठूंस दिया गया...।

आत्मप्रकाश। जागरण

किरण गर्ग।

इंद्रसेन गर्ग। (फाइल)

पहले नहाऊंगा, हनुमान पाठ करूंगा, तब करना मुझे गिरफ्तार...

राज सिंह, पानीपत : पानीपत, हरियाणा निवासी गर्ग परिवार ने भी आपातकाल का कहर झेला। परिवार के मुखिया इंद्रसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। तब परिवार ने जो सहा, उसे बयां करते हुए स्वर्गीय इंद्रसेन की पत्नी किरण और पुत्र अजय ने बताया कि उन्हें उस संघर्ष का एक-एक पल किसी चलचित्र की तरह अब भी याद है। 72 साल की किरण ने कहा, इंद्रसेन की मेन बाजार में क्रॉकरी शॉप थी। आरएसएस में नगर कार्यवाहक थे। आपातकाल घोषित होने पर किला थाना पुलिस ने तमाम विपक्षी संगठनों, पत्रकारों, साहित्यकारों की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। इंद्रसेन भूमिगत होकर दिल्ली में जा छिपे। पुलिस घर आई और इंद्रसेन के बड़े भाई वजीर चंद को गिरफ्तार कर ले गई। तब दो जुलाई 1975 को इंद्रसेन को लौटना पड़ा। किला थाना पुलिस घर आ धमकी। इंद्रसेन ने कहा कि पहले नहाऊंगा, हनुमान पाठ करूंगा, फिर नाश्ता करने के बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी बात नहीं मानोगे तो दीवार कूदकर भाग जाऊंगा। किरण के मुताबिक कृष्ण स्वरूप नाम का पुलिसकर्मी उनकी बात को मान गया। इंद्रसेन को करनाल जेल भेजा गया, जहां वह एक साल कैद रहे। अजय गर्ग ने बताया कि परिवार में दो भाई-तीन बहनें हैं। आपातकाल के दौरान उनकी आयु करीब 11 वर्ष थी। पिता की छोटी सी दुकान थी। पिता और ताऊ जेल गए तो भूखे मरने की नौबत आ गई। दुकान का सामान औने-पौने दाम में बेचना पड़ा था। हालात ऐसे थे कि कोई सामान नहीं खरीदना चाहता था, बात करने से भी मुहल्ले के लोग डरते थे। मां ने उस दौरान कैसे घर संभाला, याद करते हैं तो रोना आ जाता है। दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे।

बाल-युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 23 भाषाओं की कृतियों को युवा और 22 लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार

साहित्य अकादमी ने बाल व युवा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। हिंदी भाषा में कविता संग्रह 'बाघ और सुगना मुंडा की बेटी' के लिए अनुज लगून को युवा साहित्य पुरस्कार और कहानी 'काचू की टोपी' के लिए गोविंद शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा।

चयन समिति द्वारा अनुशंसित पुरस्कारों के लिए शुक्रवार को अगरतला में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल ने स्वीकृति दी। युवा पुरस्कार के तहत 23 भारतीय भाषाओं में 11 कविता संग्रह, छह कहानी संग्रह, पांच उपन्यास और साहित्यिक आलोचना की कृति को पुरस्कार दिए जाएंगे। 22 लेखकों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया गया। बाल साहित्य पुरस्कार उन्हीं पुस्तकों से संबंधित है, जो एक जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2017 के मध्य पहली बार प्रकाशित हुईं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी में पुस्तक 'इंडिया थ्रू आर्केलॉजी : एक्सवेटिंग हिस्ट्री (इतिहास) के लिए देविका कारिअप्पा, पंजाबी में उपन्यास 'एलियंस दी धरती ते' के लिए पवन हरचांदपुरी व उर्दू में कहानी 'साइंस के दिलचस्प मजामीन' के लिए मोहम्मद खलील समेत अन्य लेखकों को ताम्रफलक और 50,000 रुपये का चेक 14 नवंबर 2019 को विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

युवा साहित्य पुरस्कार उन लेखकों को दिया गया, जिनकी उम्र एक जनवरी 2019 को 35 वर्ष या उससे कम है। इस श्रेणी में पंजाबी उपन्यास 'वक्त बितेया नहीं' के लिए यदविंदर सिंह संधू, संस्कृत में कविता संग्रह 'वाग्विलासिनी' के लिए युवराज भट्टाराई व उर्दू उपन्यास 'लफ्जों के लहू' के लिए सलाम अब्दुस समद समेत अन्य भाषाओं के पुरस्कृत युवा साहित्यकारों को ताम्रफलक और 50 हजार रुपये की राशि समारोह में दी जाएगी।

तनुश्री दत्ता ने रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का नहीं किया जिक्र : मुंबई पुलिस

मुंबई, एएनआइ : मुंबई पुलिस ने कहा है कि अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने वर्ष 2008 में अभिनेता नाना पाटेकर के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं किया था।

पुलिस के बयान के अनुसार, 'दत्ता ने शिकायत में कहा है कि उन्हें डांस के क्रम में बदलाव की जानकारी नहीं थी। न ही बताया गया था कि डांस में पाटेकर भी होंगे। हालांकि, गवाहों का कहना है कि यह सही नहीं है। वह बदलाव से वाकिफ थीं।' पुलिस ने लिखा, 'गोरेगांव थाने में वर्ष 2008 में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं है। सिंटा व टीवी निर्माता संघ के साथ दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भी यौन दुराचार का उल्लेख नहीं है।'

दरअसल, गुरुवार को मुंबई पुलिस ने एक स्थानीय अदालत में बी समरी रिपोर्ट दाखिल कर पाटेकर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य न मिलने की बात कही थी। इसके बाद दत्ता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उल्लेखनीय है कि दत्ता ने वर्ष 2008 में 'हॉर्न ओके प्लीज' फिल्म की शूटिंग के दौरान पाटेकर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए गत वर्ष अक्टूबर में एक मुकदमा दर्ज कराया था।

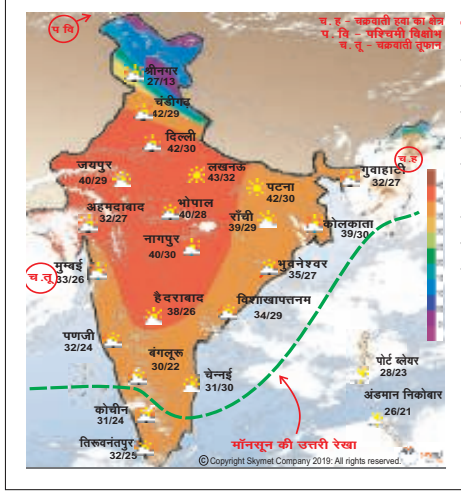

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में तथा उत्तरी हिमाचल के एक-दो स्थानों पर गरज के साथ वर्षा संभव है। पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में धूलभरी आंधी के साथ मेघगर्जना या छिटपुट वर्षा संभव है। राजस्थान के पूर्वी भागों में एक-दो स्थानों पर मध्यम वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/26/व	अहमदाबाद	41/29/व
कोलकाता	40/31/व	बड़ौदा	39/28/व
चेन्नई	40/29/आंबा	नागपुर	42/28/व
हैदराबाद	37/26/आंबा	इन्दौर	39/26/आंबा
बंगलूरू	30/22/व	रांची	37/29/व
त्रिवेन्द्रम	33/26/व	पटना	40/30/आंबा
गुवाहाटी	31/27/आंबा	जमशेदपुर	40/29/आंबा
गंगटोक	21/10/आंबा	पुणे	25/23/व

चार्ल्स गुडइयर को वल्कनाइज्ड रबर का पेटेंट मिला

1844 में आज ही अमेरिकी केमिस्ट चार्ल्स गुडइयर को वल्कनाइज्ड रबर का पेटेंट मिला था। वल्कनाइजेशन एक खास रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके जरिये प्राकृतिक रबर को सल्फर की मदद से वल्कनाइज्ड रबर में तब्दील किया जाता है। यह रबर बेहद मजबूत और टिकाऊ होता है।

भारत के बंटवारे की योजना को स्वीकार किया गया

1947 में आज ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के बंटवारे की योजना स्वीकार कर ली थी। पश्चिमी पंजाब का मुस्लिम बहुल इलाका और पूर्वी बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान के हिस्से चला गया। पूर्वी बंगाल का इलाका बाद में जाकर बांग्लादेश बना।

बेहतरीन अदाकारा और गायिका थीं सुरैया

सशक्त अभिनय और जादुई गायन से सिनेमा प्रेमियों को अपना दीवाना बनाने वाली सुरैया का जन्म 1929 में आज ही पंजाब में हुआ था। तीस साल के करियर में उन्होंने 67 फिल्मों में अभिनय किया और 338 गाने गाए। बतौर अभिनेत्री 1941 में आई ताजमहल उनकी पहली फिल्म रही। पहली बार फिल्म शारदा में गाने का मौका मिला। फिल्मों में उनकी जोड़ी अभिनेता देवानंद के साथ खूब जमी। दो बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 31 जनवरी, 2004 को दुनिया को अलविदा कह गईं।

इधर-उधर की

26 साल बाद लौटाया चोरी किया बच्चा

बीजिंग, एजेंसी : चीन में एक महिला द्वारा मालिक के यहां से चोरी किए गए बच्चे को 26 साल बाद लौटाने का मामला सामने आया है। 1992 में शियांग पिंग नामक एक महिला के दो बच्चे हुए, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई। उसे एक ओझा ने बताया यदि वह किसी के बच्चे को चोरी कर ले तो उसकी बिगड़ी किस्मत सही हो जाएगी और वह एक और बच्चे को जन्म दे सकेगी। इसके बाद शियांग पिंग एक घर में आया का काम करने लगी और कुछ दिन बाद मालिक के 15 माह के बच्चे को चुराकर भाग गई। 1995 में वह एक बच्ची को जन्म देती है। इसके बाद उसका ओझा की बात पर विश्वास बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी बिगड़ी किस्मत सही हो गई है। लिहाजा, 26 साल बीत जाने के बाद वह बच्चे को असली मां-बाप को लौटाने का फैसला करती है। वह अपने मालिक के घर जाती है और बच्चा चुराने की कहानी बताती है। वहां उसे बताया जाता है कि उनका खोया बच्चा तो तीन साल बाद ही मिल गया था। यह बात सुनकर वह आवाक रह गई। बाद में वह कोर्ट पहुंची है। कोर्ट डीएनए टेस्ट का आदेश देता और शियांग पिंग की जीत होती है।

हैरी पॉटर की दुनिया की तरह चलती-फिरती दिखेंगी तस्वीरें

तकनीक ▸ वैज्ञानिकों ने बनाया नया टूल, देख सकेंगे एनीमेटेड 3डी फोटो

अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को मिली सफलता

वाशिंगटन, प्रेट्र : हैरी पॉटर की दुनिया की तरह जल्द ही हमारे फोटोग्राफ भी चलते-फिरते दिखाई दे सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टूल तैयार किया है, जिसमें किसी व्यक्ति की 2डी इमेज चलती-फिरती दिखाई देगी। वैज्ञानिकों ने इस टूल में एक एल्गोरिद्म का इस्तेमाल किया है। जिसे फोटो वेक-अप नाम दिया गया है। इसमें उपयोगकर्ताओं को एनीमेटेड 3डी फोटो देखने की सुविधा मिलती है।

अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर इरा केमेलमाकर-श्लीजरमैन ने कहा इसे तैयार करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने बताया कि इसकी सबसे मुश्किल बाधा यह थी कि इसमें इनपुट के तौर पर केवल कैमरा का सिंगल शॉट ही उपलब्ध था। उन्होंने कहा कि हमारा काम कलात्मक और रचनात्मक दृश्यों को तकनीक से जोड़ना है और अपने प्रयास में हमने सफलता पाई है। इससे पहले, शोधकर्ता मानते थे कि किसी व्यक्ति की सिंगल शॉट की फोटो में एनीमेशन करना असंभव है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन कर्टलेस ने कहा कि पहले एक ऑब्जेट की कई ओर से तस्वीर लेने के बाद उसे 3डी बनाने पर काम होते रहे हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि हम सिर्फ एक ही तस्वीर का उपयोग करके उसे एनीमेटेड बना सकते हैं।

कुछ इस तरह से चित्र फोटो से बाहर आते दिखाई देंगे। प्रतीकात्मक

इस तरह से करता है काम : हैरी पॉटर की फिल्मों के जादू को वास्तविक बनाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए फोटो वेक-अप टूल में किसी भी फोटो के प्रत्येक पिक्सल की 3डी इंफार्मेशन सेव की गई है, जिससे की यह किसी भी 2डी फोटो से मिली जानकारी को 3डी में समझ सकता है। जब इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है तो यह फोटो में व्यक्ति की पहचान करके उसको आउट लाइन करता है फिर उसका एक 3डी टेम्प्लेट तैयार करता है। मुख्य काम इसके बाद होता है और एल्गोरिद्म आश्चर्यजनक रूप से काम करती है और 3डी में तैयार किए गए टेम्प्लेट को वापस 2डी में बदल देती है। इसके बाद फोटो में आपको वह व्यक्ति चलता-फिरता दिखाई देता है।

गेम की दुनिया में आएगा बदलाव: शोधकर्ताओं का मानना है कि एप्लीकेशन के माध्यम से गेम की दुनिया में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इसमें यूजर गेम के अंदर एक नया अवतार ले सकते हैं जो वास्तव में उनकी ही तरह दिखेगा।

एवरेस्ट पर स्थापित किए गए दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र

काठमांडू, आइएएनएस : माउंट एवरेस्ट पर दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेपाल समेत आठ देशों के वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों की टीम ने गत अप्रैल से जून के बीच पांच मौसम केंद्र स्थापित करने में सफलता हासिल की। इसके लिए द नेशनल जियोग्राफिक सोसायटी व नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में अभियान चला था।

नैटजियो सोसायटी के मार्केटिंग व कम्युनिकेशन निदेशक फेइ जेंक्स ने गुरुवार को बताया कि एक केंद्र एवरेस्ट के बालकोनी क्षेत्र में 8,430 मीटर की ऊंचाई और दूसरा साउथ कोल में 7,945 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। ये दोनों ही स्वचालित मौसम केंद्र हैं। इनके अलावा 8848 मीटर ऊंचे एवरेस्ट के बेस कैंप (5,315 मीटर), कैंप-2 (6,464 मीटर) और फोर्टसे (3,810 मीटर) पर तीन अलग-अलग मौसम केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी केंद्र तापमान, आर्द्रता, दबाव, हवा की गति और दिशा के बारे में जानकारियां इकट्ठा करेंगे। इनके द्वारा जुटाए गए डाटा से पर्वतीय क्षेत्र में मौसम संबंधी खतरों का सही समय पर पूर्वानुमान लग सकेगा। एवरेस्ट के बालकोनी क्षेत्र के मौसम केंद्र से हमारे वायुमंडल की दूसरी सतह यानी स्ट्रेटोस्फेयर में होने वाले बदलाव की भी निगरानी की जा सकेगी।

फिल्म रिव्यू

जोरदार एक्शन, लचर इमोशन

★★★

मेन इन ब्लैक : इंटरनेशनल

निर्देशन : एफ गैरी ग्रे
प्रमुख कलाकार : क्रिस हेम्सवर्थ, टेसा थॉम्पसन, रेबेका फर्ग्युसन, लेस ट्विंस, कुमैल ननजियानी
अवधि : 1 घंटा 55 मिनट

मेन इन ब्लैक (एमआइबी) की फंतासी करीब 22 साल पहले इंसान और एलियन के साथ दुनिया को बचाने की कहानी के साथ रची गई थी। पहली फिल्म 'मेन इन ब्लैक' वर्ष 1997 में रिलीज हुई थी। वर्ष 2002 में दूसरी किस्त और 2012 में तीसरी किस्त आई थी। करीब सात साल बाद इस सीरीज की यह चौथी फिल्म आई है। पिछली तीनों फिल्मों में टॉमी ली जोंस (एजेंट के) और विल स्मिथ (एजेंट जे) की जोड़ी खूब पसंद की गई थी। चौथी सीरीज में पूर्ववर्ती एजेंट जे और एजेंट के ने अपने काले कोट और काले चश्मे इस बार क्रिस हेम्सवर्थ और टेरा थॉम्पसन को सौंप दिए हैं।

कहानी वर्ष 2016 में पेरिस से शुरू होती है और जल्द ही बीस साल पीछे चली जाती है। बचपन में मौली अपनी खिड़की से देखती है कि एक एलियन के उनके घर में घुसने पर एमआइबी एजेंट उनके पैरेंट्स की याददाश्त मिटा देते हैं। मौली एमआइबी एजेंट बनने का सपना देखती है। कुछ वर्ष बाद मौली (टेसा थॉम्पसन) एमआइबी के लंदन कार्यालय में एजेंट एम के तौर पर एजेंट एच (क्रिस हेम्सवर्थ) की असिस्टेंट बन जाती है।

जल्द ही उनके हाथ में एलियन का हथियार आ जाता है, जिस पर दो दुष्ट जुड़वां लोगों की नजर है। एजेंट एम और एच दुनिया का विनाश करने वाले इस हथियार को दुष्ट लोगों से बचाना चाहते हैं। जुड़वां दुष्ट लोगों की भूमिका को फ्रेंच ब्रेक डांसर लॉरेंट और लैरी निकोलस ने जीवंत किया है। एक दृश्य में उनका डांस भी है।

इस बार भी एलियंस की विचित्र दुनिया दिखाई गई है। मोटरसाइकिल के आसमान में उड़ने और पानी में चलने के दृश्य भी रोमांचक हैं। न्यूयॉर्क सबवे में मेट्रो ट्रेन का हाई स्पीड ट्रेन में तब्दील होना अचंभित करता है। हालांकि फिल्म में एक बड़ा मोड़ है, जिसकी गहराई में लेखक नहीं जाते। वे अंत में उसे पेश कर आशा करते हैं कि सब उसे समझ लेंगे। फिल्म के डायलॉग भी खास प्रभावित नहीं करते। टेसा थॉम्पसन और क्रिस हेम्सवर्थ की केमिस्ट्री खास नहीं जमी। फिल्म का सबसे रोचक हिस्सा पाउनी के तौर पर कुमैल नैनजियानी द्वारा दी गई आवाज रही। पाउनी द्वारा की गई कॉमेडी दिलचस्प है।

-स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

नासा ने महिला गणितज्ञों के सम्मान में बदला सड़क का नाम

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी तीन अश्वेत महिला गणितज्ञों के सम्मान में वाशिंगटन स्थित मुख्यालय के सामने की सड़क का नाम बदलकर 'हिडन फिगर्स' कर दिया है। इन गणितज्ञों का नासा के शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रमों में बहुत योगदान रहा है। इनपर एक फिल्म 'हिडन फिगर्स' भी बन चुकी है।

कैथरीन जॉनसन, डॉर्थी वॉन और मैरी जैक्सन ने 1940 से 1960 के बीच नासा के अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान में विशेष योगदान दिया था। इसी दौरान अमेरिका ने पहले पुरुषों को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा और फिर चंद्रमा में। इतनी उपलब्धियों के बावजूद इन तीनों अश्वेत महिला गणितज्ञों को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। नासा ने बताया कि इन तीनों अश्वेत महिला गणितज्ञों का काम भुला दिया गया था, लेकिन सालों बाद मार्गोट ली शेटरली ने इन गणितज्ञों के ऊपर अपनी किताब 'हिडन फिगर्स' लिखी। इसके बाद 2016 में इसी नाम से इन पर एक फिल्म बनाई गई जो ब्लॉकबस्टर रही थी।

क्रेटरों में जमा धातुओं की वजह से बदल जाता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के सबसे बड़े क्रेटर (एस्टेरॉयड गिरने से बना गड्ढा) में एक ऐसी सामग्री की खोज की है, जिसकी वजह से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बदलाव आता है। अमेरिका की बायलर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह सामग्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 'एटकेन बेसिन' में पाई गई है और इसमें एस्टेरॉयड की धातु का मिश्रण है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड के टकराने से ही चंद्रमा पर क्रेटरों का निर्माण हुआ है। बायलर यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर पीटर बी जेम्स ने कहा कि इन क्रेटरों में पाई जाने वाली धातु का आकार अमेरिका के हवाई द्वीप से पांच गुना बड़ा है। कई क्रेटर अंडाकार भी हैं जो 2,000 किलोमीटर तक चौड़े और कई मील गहरे हैं। इतने बड़े आकार के बावजूद इन्हें पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये चंद्रमा के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में हो रहे परिवर्तनों को मापने के लिए शोधकर्ताओं ने नासा की ग्रेविटी रिकवरी और इंटीरियर लेबोरेटरी (जीआरएआइएल) मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के डाटा का विश्लेषण किया।

- एस्टेरॉयड गिरने से बने गड्ढों में वैज्ञानिकों ने खोजी रहस्यमयी सामग्री
- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 'एटकेन बेसिन' में पाई गई है सामग्री, इसमें एस्टेरॉयड की धातु का मिश्रण भी है

2000 किलोमीटर लंबे और कई मील गहरे हैं ये क्रेटर। प्रतीकात्मक

जेम्स ने कहा कि जब हमने लूनार रीकॉसेंस ऑर्बिटर से चंद्रमा की स्थलाकृति के डाटा का अध्ययन किया तो पाया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन के सैकड़ों मील नीचे बड़ी मात्रा में रहस्यमयी धातु मौजूद है। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि चंद्रमा पर क्रेटरों के जिम्मेदार यह एस्टेरॉयड ही हैं और इनकी धातु चंद्रमा की निचली सतह में मौजूद है।

जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित शोध के अनुसार एस्टेरॉयड के प्रभावों का कम्प्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इनकी ऊपरी परत चंद्रमा से टक्कर के दौरान निकल गई और बने क्रेटरों में जमा हो गई।

दुनियाभर में बाधित रही इंस्टाग्राम की सेवा

नई दिल्ली, एएनआइ/आइएएनएस : फेसबुक की सहयोगी कंपनी इंस्टाग्राम की सेवा शुक्रवार सुबह दुनिया भर में करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक बाधित रही। इसकी वेबसाइट व एप के इस्तेमाल में यूजर को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर तो इस समस्या को ट्विटर पर ले आए और हैशटैग इंस्टाग्राम डाउन के साथ ट्रोल करना शुरू कर दिया। दस दिनों पहले भी इंस्टाग्राम को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा था।

इंस्टाग्राम ने यूजर को आने वाली परेशानियों को स्वीकार करते हुए ट्वीट किया, 'हमें जानकारी है कि लोगों को इंस्टाग्राम अकाउंट के इस्तेमाल में परेशानी आ रही है। हम इसे दूर करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।'

फोटो साझा करने वाले इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में यूजर ने इस्तेमाल व सर्च से लेकर कई तरह की शिकायतें कीं। सोशल मीडिया साइट की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर डॉट कॉम के अनुसार, यूजर ने पहली बार देर रात ढाई बजे इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में परेशानी आने की शिकायत की। शुक्रवार को कुछ ही देर में करीब 50 हजार लोगों ने परेशानी की शिकायत की।

शोध अनुसंधान

आनुवांशिक बहरेपन को रोक सकती है मलेरिया रोधी दवा

शोधकर्ताओं को आनुवांशिक विकारों के चलते होने वाली बहरेपन की समस्या को दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने पाया कि मलेरिया रोधी एक दवा से इस समस्या की रोकथाम करने में मदद मिल सकती है। अमेरिका की केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जेब्राफिश पर आर्टीमिसिनिन दवा को लेकर अध्ययन किया। इस मलेरिया रोधी दवा को लेकर किए गए अध्ययन में पाया गया कि कान के अंदर की संवेदी कोशिकाओं को एक खास झिल्ली तक जरूरी प्रोटीन पहुंचाने में आर्टीमिसिनिन दवा मदद कर सकती है। इससे सुनने की क्षमता को बहाल करने में मदद मिल सकती है। -प्रेट्र

सुबह-शाम की एक्सरसाइज का पड़ सकता अलग प्रभाव

स्वस्थ तन और मन में एक्सरसाइज की अहम भूमिका होती है। लेकिन एक नए अध्ययन में पाया गया है कि इससे होने वाला फायदा इस पर भी निर्भर करता है कि व्यायाम किस समय किया जाता है। सुबह और शाम के वक्त की गई एक्सरसाइज का अलग-अलग असर पड़ सकता है। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, यह निष्कर्ष चूहों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि सुबह और शाम के समय की गई एक्सरसाइज के प्रभाव में भिन्नता देखने को मिली। सुबह की गई एक्सरसाइज से मांसपेशियों की कोशिकाओं में जीन प्रोग्राम शुरू होता है। इससे कोशिकाओं के शुगर और फैट की मेटाबोलिज्म क्षमता बढ़ जाती है। जबकि शाम के वक्त की एक्सरसाइज से शरीर में ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। -एएनआइ

दुनिया का पहला जेट सूट

लंदन की प्रमुख ग्रेविटी इंडस्ट्री ने दुनिया का पहला ऐसा जेट सूट तैयार किया है, जिसे पहनकर उड़ा जा सकता है। इंडस्ट्री के संस्थापक एवं चीफ टेस्ट पायलट रिचर्ड ब्राउनिंग और उनके सहयोगी पायलट ने रॉयल विक्टोरिया स्थित जलमार्ग में इस सूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ग्रेविटी इंड्रस्ट्री की योजना 2020 में इंटरनेशनल जेट सूट की सुपरसीरीज कराने की है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एपी

लग्जरी कार को बना दिया टैंक

रूस के उत्साही इंजीनियर ने महंगी लक्जरी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी सेडान कार को एक टैंक में बदल दिया। सेंट पीट्र्सबर्ग में इस कार का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक युवती ने टैंक-कार के नीचे से निकलकर भी देखा। इस कार को इंजीनियर कॉन्स्टेंटिन जारुट्स्की ने डिजाइन और अपग्रेड किया है। रायटर

स्क्रीन शॉट

जो मन होता है, वही पहनती हैं कट्रीना कैफ

फिल्मों के प्रमोशन के दौरान अक्सर सितारे अपने किरदार के रंग में ही रंगे नजर आते हैं। पिछले दिनों कट्रीना कैफ फिल्म 'भारत' के प्रमोशनों में भारतीय रंग में रंगी नजर आई थीं। पूरे प्रमोशन के दौरान वह ज्यादातर साड़ी में दिखीं। यहां तक कि इंस्टाग्राम पर शेयरकी गईं उनकी पोस्ट भी हिंदी में लिखी गई थीं। इस बदलाव के बारे में जब कट्रीना से पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'मैं देवनागरी लिपि में काफी लिखती-पढ़ती हूं। मुझे जब कोई मैसेज अच्छा लगता है, तो उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हूं। जहां तक साड़ी पहनने की बात है, तो मेरे जो मन में आता है, वही पहनती हूं। कई बार मैं लगातार महीनों तक सूट ही पहनती रहती हूं। जब मन होता है, तब कई महीनों लगातार साड़ियां पहनती हूं। मैं बस एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती हूं।' ईद पर रिलीज हुई सलमान खान और कट्रीना कैफ अभिनीत फिल्म 'भारत' लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। इस फिल्म के बाद कट्रीना कैफ रोहित शेट्टी की फिल्म 'सूर्यवंशी' में व्यस्त हो गई हैं।

दर्शक ट्रोलर्स नहीं हैं : अर्जुन कपूर

अर्जुन कपूर सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोल होते रहते हैं और कुछ लोगों का बेबाकी से जवाब देते हैं। अर्जुन के मुताबिक, वह जवाब तभी देते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। अगर कोई उनकी बहन अंशुला, जाह्नवी या खुशी के बारे में कोई गलत बोलता है तो उनका फर्ज बनता है कि पलटकर जवाब दें। बकौल अर्जुन, 'मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता। मुझे शुरू से ट्रोल किया जा रहा है। आप जितना सफल होंगे, उतना लोग आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे ट्रोल नहीं करते तो मुझे लगता कि लोग मुझे ट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप प्रासंगिक बने हुए हैं। लोगों की निगाहें आप पर हैं। कहीं न कहीं वे आपको नीचे खींचना चाहते हैं, लेकिन दर्शक ट्रोलर्स नहीं हैं। जो ट्रोलर्स होते हैं, वे बिना नाम और चेहरे के होते हैं। बड़े-छोटे हर स्टार्स ट्रोल होते हैं। घर पर बैठकर टाइप करना आसान होता है, बाहर जाकर जिंदगी जीना बहुत अलग बात है।'

तय समय से पहले पूरी हुई फिल्म 'चेहरे' की शूटिंग

आनंद पंडित की अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'चेहरे' की शूटिंग अपने तय समय से चार दिन पहले ही पूरी हो गई है। आनंद समय से पहले फिल्म की शूटिंग खत्म होने की वजह सही प्लानिंग और रणनीति को मानते हैं। फिल्म का निर्देशन रूमी जाफरी ने किया है। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को फिल्म में अलग लुक में दिखने के बाद से ही लोगों में बड़ी उत्सुकता है। प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने बताया, 'हमने फिल्म की शूटिंग खत्म करने की जो तारीख तय की थी, उससे चार दिन पहले ही शूटिंग खत्म हो गई है। फिल्म की शूटिंग का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और मैं पूरी टीम को इस शूटिंग को सफलतापूर्वक समाप्त करवाने के लिए धन्यवाद देता हूं। अब फिल्म की रिलीज का इंतजार है।' 'चेहरे' से पहले आनंद पंडित की मोशन पिक्चर्स कंपनी 'प्यार का पंचनामा 2', 'सरकार 3', 'सत्यमेव जयते', 'बाजार' और हाल ही में आई 'टोटल धमाल' जैसी हिट फिल्में बना चुकी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के अलावा कीर्ति खरबंदा, रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ कपूर, द्रुतमान चक्रवर्ती, रघुवीर यादव और अन्नू कपूर भी हैं। फिल्म अगले साल 21 फरवरी को रिलीज होगी।

वरुण और अनुष्का की 'सुई धागा' पहुंची शंघाई

पिछले साल रिलीज हुई वरुण धवन और अनुष्का शर्मा अभिनीत फिल्म 'सुई धागा : मेड इन इंडिया' को शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द बेल्ट ऐंड रोड फिल्म वीक के प्रतिस्पर्धा श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इस श्रेणी की प्रतियोगिता में चुनी जाने वाली यह एकमात्र भारतीय फिल्म है। इस फेस्टिवल का आगाज आज (15 जून) से होगा। उसमें दुनिया भर से आई सराहनीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 'सुई धागा' कामकाजी दंपती की कहानी है, जो आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। वरुण और अनुष्का को उम्मीद है कि फिल्म इस फेस्टिवल में भी दर्शकों का दिल जीत लेंगी।

चिंताजनक

अमेरिका के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में सामने आई बात, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि और पशुधन को पहुंचेगा नुकसान, बढ़ेगी असमानता

जलवायु परिवर्तन से भविष्य में बढ़ेंगे खूनी संघर्ष

बोस्टन, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है और आगे आने वाले समय में यह और कितना प्रभावित करेगा वैज्ञानिक लगातार इस पर अध्ययन कर रहे हैं। अब एक नए अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दावा किया गया है कि बहुत तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन भविष्य में कई देशों में सशस्त्र संघर्ष का खतरा बढ़ा रहा है। इसके कारण भविष्य में हिंसा बढ़ेगी।

नेचर जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन ने पिछली सदी से लेकर अब तक संघर्ष के जोखिम को तीन से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया है और यह जोखिम आगे आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। अध्ययन में बताया गया कि अगर तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो लोगों के बीच होने वाले संघर्ष पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पांच गुना ज्यादा पड़ेगा और संघर्षों के जोखिम में 26 फीसद तक की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं, अगर तापमान में केवल दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है जो कि पेरिस जलवायु समझौते के तय मानक के अनुरूप है, फिर भी होने वाले संघर्षों में जलवायु का प्रभाव दोगुने से अधिक होगा और संघर्षों के जोखिम में 13 फीसद तक की वृद्धि होगी।

- जलवायु परिवर्तन से देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पहुंचेगा नुकसान
- सामाजिक समूहों के बीच असमानता बढ़ने से लोगों में बढ़ेगा संघर्ष

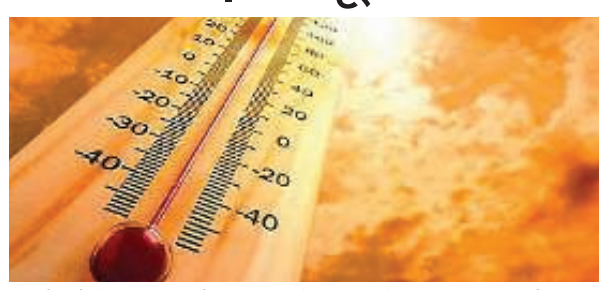

पिछली सदी से अब तक 20 फीसद तक बढ़ा है संघर्ष का जोखिम। प्रतीकात्मक

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कथरीन मच ने बताया कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हमे लगातार हो रहे उत्सर्जनों को कम करने की जरूरत है, यह तभी होगा जब हमे अपनी जिम्मेदारी का अहसास हो और एक दूसरे के सहयोग से काम करने की भावना हो। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है पर लोग अभी जागरूक नहीं हो रहे हैं।

इस तरह बढ़ेगा संघर्ष का खतरा: जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में होने वाला चरम बदलाव और उससे उत्पन्न हुई आपदाएं भविष्य में अर्थव्यवस्थाओं, खेती, पशुधन को नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे की सामाजिक समूहों के बीच असमानता बढ़ेगी। यह कारक जब संघर्ष के अन्य कारकों से मिलेंगे तो हिंसा का रूप ले लेते हैं।

गृहयुद्ध जैसा खतरा नहीं : स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर मार्शल बर्क ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से संघर्ष तो बढ़ेंगे, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह गृहयुद्ध का रूप ले लेगें।

यह बात सही है कि इस सदी में जलवायु परिवर्तन का अभूतपूर्व असर पड़ने वाला है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन से अभी तक जितने भी प्रभाव सामने आए हैं भविष्य में होने वाले प्रभाव उनसे अलग होंगे।